www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार, 03 जून, 2026

दैनिक जागरण

शिक्षा आदर्श व्यक्तित्व निर्माण का आधार है

शहरों की बिगड़ती सूरत

देश की राजधानी में एक पांच मंजिला भवन गिरने से छह लोगों की मौत और कई के घायल होने के बाद भवन स्वामी की गिरफ्तारी करने के साथ ही नगर निगम के दो इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दे गिए। इस घटना के बाद नगर निगम यह जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर शिकायतों के बाद भी उक्त इमारत में अतिरिक्त मंजिल का अवैध निर्माण कैसे हो रहा था? वह अन्य ऐसी ही इमारतों की छानबीन में भी जुट गया है, लेकिन इसके आसार कम ही हैं कि आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी और अवैध निर्माण का सिलसिला बंद होगा, क्योंकि यदि ऐसा होना होता तो बहुत पहले हो गया होता। आखिर दिल्ली में ऐसी कोई इमारत पहली बार नहीं गिरी, जो अवैध रूप से बनी थी या निर्मित की जा रही थी। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हो चुकी हैं और फिर भी नतीजा ढाक के तीन पात वाला है। ऐसा इसीलिए है, क्योंकि नगर निकाय के अधिकारी-कर्मचारी कुछ ले-देकर अवैध निर्माण होने देते हैं। वे पैसों के लालच में भवन निर्माण संबंधी नियम-कानूनों की अनदेखी करते हैं। इस मामले में जो स्थिति दिल्ली की है, वही शेष देश की भी है।

हमारे हर छोटे-बड़े शहर में अवैध एवं बेतरतीब निर्माण हो रहा है। यह स्थानीय निकायों के संरक्षण और उनकी जानकारी में होता है। इसी कारण शहरों में अवैध तरीके से रिहायशी और व्यावसायिक इमारतों का निर्माण होता रहता है। स्थिति यह है कि जो पुराने भवन दो-तीन मंजिल के होते हैं, वे जर्जर होने के बाद भी अवैध निर्माण के सहारे चार-पांच मंजिलों में तब्दील कर लिए जाते हैं। इससे क्षेत्र विशेष में आबादी का दबाव बढ़ने के साथ नागरिक सुविधाओं का अभाव भी बढ़ता है। अपने देश में ऐसा कोई नियम ही नहीं कि किसी इलाके में कितनी आबादी रहनी चाहिए। इससे भी बड़ी त्रासदी यह है कि हर कहीं रिहायशी इलाके व्यावसायिक इलाकों में तब्दील हो रहे हैं। देश भर में घरों में दुकानें बनाने की होड़ सी कायम है। ऐसा पुराने मोहल्लों के साथ नए मोहल्लों में भी हो रहा है। इसी कारण हमारे शहर बेतरतीब विकास का पर्याय बन गए हैं और वे नागरिक सुविधाओं के अभाव के साथ प्रदूषण एवं गंदगी से घिरते जा रहे हैं। अनियोजित शहर नगरीय जीवन को केवल कष्टकारी ही नहीं बनाते, बल्कि वे विकास में बाधक भी बनते हैं। आज के युग में शहर आर्थिक विकास के इंजन हैं, लेकिन तभी, जब उनका नियोजित ढंग से विकास हो। विडंबना यह है कि जिन नगर निकायों की पहली जिम्मेदारी शहरों के नियोजित विकास को सुनिश्चित करना है, वे उसका ही निर्वाह करने में बुरी तरह नाकाम हैं। यदि शहरों की सूरत संवारनी है और उन्हें विकास का वाहक बनाना है तो स्थानीय निकायों के कामकाज के तौर-तरीकों को पूरी तरह बदलना होगा।

निगरानी जरूरी

झारखंड में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग समुदायों के सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए संचालित योजनाएं राज्य की समावेशी विकास नीति का महत्वपूर्ण आधार हैं। मुख्यमंत्री स्तर पर छात्रवृत्ति, छात्रावास, स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति की समीक्षा तथा लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश स्वागतयोग्य हैं। विशेष रूप से ओबीसी छात्रवृत्ति का मुद्दा महत्वपूर्ण है। यदि केंद्र से अपेक्षित राशि नहीं मिल रही है, तब भी राज्य सरकार द्वारा 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर यह संदेश देना सकारात्मक है कि आर्थिक संसाधनों की कमी विद्यार्थियों की शिक्षा में बाधा नहीं बनने दी जाएगी। छात्रवृत्ति समय पर मिलना हजारों छात्रों के लिए उच्च शिक्षा जारी रखने का आधार है। छात्रवृत्ति समय पर मिले, यह हजारों विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए जरूरी। हालांकि केवल बजट आवंटन पर्याप्त नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि प्रशासनिक विलंब, निगरानी की कमी और समन्वय के अभाव में अच्छी योजनाओं का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाता। ऐसे में हर छह महीने में समीक्षा बैठक करने का सुझाव व्यावहारिक है। नियमित समीक्षा से कमियों की पहचान समय रहते हो सकेगी और अधिकारियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। कल्याणकारी योजनाओं की सफलता का वास्तविक पैमाना यही है कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर और पारदर्शी ढंग से पहुंचे।

> कल्याणकारी योजनाओं की सफलता का वास्तविक पैमाना यही है कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर और पारदर्शी ढंग से पहुंचे

गति पकड़ता सेमीकंडक्टर अभियान

हर्ष वी. पंत

भारत अब वैश्विक इलेक्ट्रानिक्स इकोसिस्टम में महज एक उपभोक्ता या असेंबलिंग तक ही सीमित न रहकर स्वयं को एक उत्पादक के रूप में भी स्थापित कर रहा है

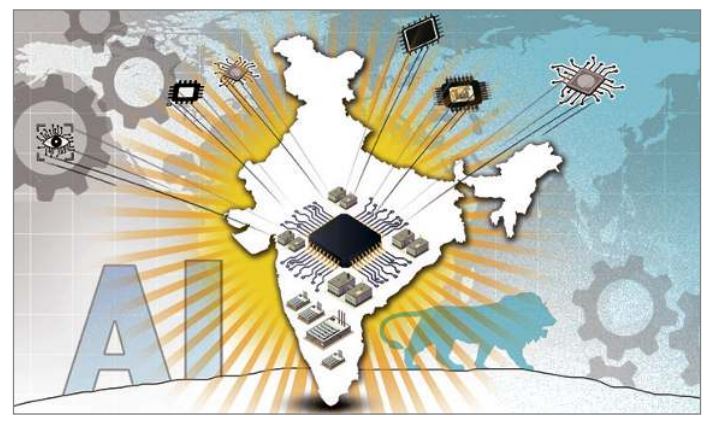

अवधेश राजपूत

वर्तमान दौर में सेमीकंडक्टर की अहमियत किसी से छिपी नहीं रही है। इस संदर्भ में अच्छी बात यह है कि भारत ने भी इसके निर्माण में तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हालिया नीदरलैंड दौरे पर वहां की दिग्गज कंपनी एएसएमएल और टाटा इलेक्ट्रानिक्स के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए है। एएसएमएल को आधुनिक सेमीकंडक्टर निर्माण की रीढ़ मानी जाने वाली उन्नत लिथोग्राफी प्रणालियों के मामले में विश्व के प्रमुख आपूर्तिकर्ता में से एक माना जाता है। यह अनुबंध इसका प्रतीक है कि भारत अब वैश्विक इलेक्ट्रानिक्स इकोसिस्टम में महज एक उपभोक्ता या असेंबलिंग तक ही सीमित न रहकर समूची मूल्य श्रृंखला में स्वयं को स्थापित करने पर ध्यान दे रहा है। यह करार गुजरात के धोलेरा में 11 अरब डालर के निवेश वाले टाटा के प्रस्तावित चिप निर्माण संयंत्र के लिए बेहद अहम है। धोलेरा को भारत के सेमीकंडक्टर हब के रूप में भी देखा जा रहा है।

सेमीकंडक्टर को लेकर भारत का दृष्टिकोण आर्थिक, रणनीतिक और भू-राजनीतिक निहितार्थों से प्रेरित है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इलेक्ट्रानिक्स की खपत में तेजी के चलते देश सेमीकंडक्टर के आयात पर बड़ी हद तक निर्भर है। आज के इस दौर में जहां चिप्स आटोमोबाइल एवं दूरसंचार से लेकर रक्षा प्रणालियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआइ और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे उदीयमान क्षेत्रों की रीढ़ बन चुके हैं, वहां उसकी आधारभूत सामग्री पर बाहरी निर्भरता को घटाना आत्मनिर्भरता के साथ ही आर्थिक सुरक्षा का भी एक अहम अवयव बन गया है। इसका भू-राजनीतिक संदर्भ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वैश्विक सेमीकंडक्टर उत्पादन मुख्य रूप से ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन और अमेरिका में केंद्रित है। कोविड-19 महामारी से लेकर अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी मोर्चे पर तनातनी जैसे पहलुओं ने इस आपूर्ति में गतिरोध पैदा करने का काम किया है। इसने दर्शाया है कि आपूर्ति श्रृंखलाओं का संकेंद्रण कितना भारी पड़ सकता है। इसका ही परिणाम रहा कि प्रमुख वैश्विक विनिर्माताओं और सरकारों ने उत्पादन में विविधता को प्रोत्साहन देने के लिए चीन से इतर उत्पादन की 'चीन प्लस वन' वाली नीति को अपनाया। इस क्रम में अपने बड़े बाजार, जनसांख्यिकीय गहराई और बढ़ते भूराजनीतिक महत्व के चलते भारत स्वयं को एक आकर्षक वैकल्पिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत कर रहा है।

रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो सेमीकंडक्टर निर्माण के निहितार्थ केवल वाणिज्यिक हितों तक सीमित नहीं हैं। सुरक्षित और विश्वसनीय चिप आपूर्ति श्रृंखलाओं पर नियंत्रण का पहलू अब राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी गहराई से जुड़ा है। विशेष रूप से रक्षा इलेक्ट्रानिक्स, साइबर बुनियादी ढांचे, दूरसंचार और एआइ संचालित तकनीकों जैसे क्षेत्रों में। इसी कारण सेमीकंडक्टर परिदृश्य महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के एक नए मोर्चे के रूप में उभरा है और इस क्षेत्र में भारत का प्रवेश बदलती वैश्विक वास्तविकताओं को स्वीकारने के उसके रवैये को ही रेखांकित करता है। नई दिल्ली ने इसी को ध्यान में रखकर अपना नीतिगत ढांचा भी तैयार किया है। इसके अंतर्गत 76,000 करोड़ रुपये के आवंटन वाले इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी आइएसएम, स्वीकृत चिप निर्माण परियोजनाओं के लिए 50 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता जैसी पहल की गई हैं। शायद ही विश्व में कहीं और ऐसे प्रोत्साहन दिए गए हैं। केंद्रीय बजट में भी आइएसएम 2.0 के दायरे का विस्तार करते हुए सेमीकंडक्टर उपकरण, सामग्री, बौद्धिक संपदा विकास, आपूर्ति श्रृंखला में लचीलेपन और शोध एवं विकास यानी आरएंडडी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

सेमीकंडक्टर अभियान से जुड़ी कई परियोजनाएं अब धरातल पर साकार होने लगी हैं। गुजरात इन गतिविधियों का गढ़ बना हुआ है। धोलेरा में टाटा-पावरचिप फैब्रिकेशन परियोजना तो साणंद में माइक्रोन की एटीएमपी इकाई स्थापित हो रही हैं। असम को टाटा की ओसैट परियोजना हासिल करने में सफलता मिली है, जबकि उत्तर प्रदेश नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एचसीएल-फाक्सकान संयुक्त उपक्रम के माध्यम से स्वयं को इस परिदृश्य पर मजबूती से उभारने में लगा है। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 तो बाकायदा दर्शाती है कि राज्य सरकारें किस प्रकार अतिरिक्त पूंजीगत सब्सिडी, कर छूट, भूमि दरों में रियायत, बिजली रियायत और कौशल विकास पहलों के माध्यम से केंद्रीय प्रोत्साहनों की पूरक बनकर इस प्रक्रिया को रफ्तार दे रही हैं। केंद्रीय रणनीतिक दूरदर्शिता और राज्यस्तरीय प्रतिस्पर्धा के बीच का यह तालमेल धीरे-धीरे भौगोलिक रूप से एक व्यापक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को तैयार कर रहा है।

कई स्तरों पर प्रगति के बावजूद इस राह में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। चिप निर्माण उन उद्योगों में से एक है, जिनके लिए व्यापक स्तर पर पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। पानी की भरोसेमंद एवं सतत आपूर्ति, बिजली की निरंतर उपलब्धता, कुशल कामकाजी आबादी एवं सक्षम आपूर्ति तंत्र का सुनिश्चित होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान विश्व में निर्यातों को लेकर जिस तरह के नियंत्रण एवं भू-राजनीतिक तनाव, खेमेबंदी और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, उसके प्रभाव से यह क्षेत्र भी अछूता नहीं। इन पहलुओं के सम्मिलित प्रभाव भी इस क्षेत्र के भविष्य की दशा-दिशा को प्रभावित करेंगे। देखा जाए तो टाटा-एसएमएल अनुबंध, माइक्रोन संयंत्र के संचालन और आइएसएम 2.0 के साथ स्पष्ट है कि भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति संकल्पना के स्तर से वास्तविकता का आकार ग्रहण करने लगी है। इससे एक दीर्घकालिक औद्योगिक क्रांति की बुनियाद रखी जा रही है। वैश्विक सेमीकंडक्टर परिदृश्य में स्वयं को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत कर रहे भारत को इससे केवल आर्थिक लाभ ही नहीं मिलेंगे, बल्कि वह रणनीतिक स्वायत्तता भी प्राप्त होगी, जहां तकनीकी क्षमताएं शक्ति संतुलन में अहम भूमिकाएं निभाने लगी हैं।

(लेखक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं)
response@jagran.com

12 बरस की सफलताएं और विफलताएं

राजीव सचान

मोदी सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाते समय इस पर भी ध्यान दे कि उसके हिस्से में कुछ नाकामियां भी हैं

विफलताओं पर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी। फाइल

मोदी सरकार अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे करने जा रही है। यह तय है कि इस अवसर पर उसकी ओर से अपनी उपलब्धियों का बखान किया जाएगा। इसके लिए भाजपा की ओर से एक अभियान चलाया जाने वाला है, जिसमें लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। निःसंदेह मोदी सरकार के पास अपनी उपलब्धियों के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है और यह हर सरकार का अधिकार है कि वह उनके बारे में जनता को अवगत कराए। यदि मोदी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करें तो उनकी एक लंबी सूची है। इन उपलब्धियों में कई ऐसे फैसले हैं, जिनमें से कुछ के बारे में यह कल्पना करना कठिन था कि कोई सरकार ऐसे फैसले ले पाएगी, जैसे जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना, पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक करना और फिर आपरेशन सिंदूर। ये दोनों सैन्य अभियान इस मायने में विशेष रहे कि विश्व में पहली बार किसी परमाणु हथियार संपन्न देश ने दूसरे ऐसे ही देश पर हवाई हमले किए। हालांकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया, लेकिन यदि मोदी सरकार नहीं होती तो शायद यह रास्ता बाधित ही रहता और राम मंदिर का निर्माण आनन-फानन नहीं होता। मोदी सरकार अपने तीसरे कोर एजेंडे समान नागरिक संहिता की दिशा में भी आगे बढ़ रही है।

जीएसटी लागू होना भी इस सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। वैसे तो नोटबंदी भी एक साहसिक फैसला था, लेकिन इसके वैसे सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुए, जैसे अपेक्षित थे। माओवाद का खात्मा भी मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ वर्षों पहले तक माओवाद का खात्मा असंभव सा दिखता था, पर मोदी सरकार और विशेष रूप से गृह मंत्री अमित शाह ने इसे संभव कर दिखाया और वह भी तय समय में। पिछले 12 वर्षों में आधारभूत ढांचे के निर्माण में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई है। देश भर में सड़कों का तेजी से निर्माण हुआ है। इसी तरह पुल, बिजलीघर, हवाई अड्डे निर्मित हुए हैं और रेल सुविधाओं का विकास हुआ है। ग्रामीण विकास की योजनाओं ने भी रफ्तार पकड़ी है। देश में डिजिटलीकरण भी द्रुत गति से हुआ है। इसके चलते भारत डिजिटल लेनदेन के मामले में विश्व में अग्रणी है। विकास के साथ ही प्रभावशाली जनकल्याणकारी योजनाओं की भी एक लंबी सूची है। इन योजनाओं ने आम आदमी का जीवन बदला है। शौचालय निर्माण, उज्ज्वला, आवास, बिजली, आयुष्मान, किसान सम्मान निधि, मुफ्त राशन संबंधी जैसी योजनाओं ने सचमुच लोगों को लाभान्वित किया है। जनधन योजना निर्धन जनता के वित्तीय समावेशन की एक बड़ी मिसाल हैं। इन योजनाओं के चलते करोड़ों लोगों को गरीबी के दायरे से बाहर निकालने में मदद मिली है। मोदी सरकार ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि उसे जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करना आता है। इन 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी बहुत काम हुआ है।

यदि आज भाजपा के नेतृत्व वाली राजग की 22 राज्यों में सरकारें हैं तो इसका एक बड़ा कारण मोदी सरकार की रीति-नीति है। कोई भी सरकार हो, उसकी प्रत्येक योजना कसौटी पर खरी नहीं उतरती। ऐसा ही मोदी सरकार की कुछ योजनाओं के साथ हुआ है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकी हैं। किसानों की आय दोगुनी करने का भी लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। हर सरकार के समय महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे रहते हैं। मोदी सरकार के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं।

अब जब मोदी सरकार अपने 12 साल की उपलब्धियों का गुणगान करने में जुटने वाली है, तब किसी को उसका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहिए कि कुछ ऐसे मोर्चों पर उसे विफलता हाथ लगी है, जिनमें उसे सफलता अर्जित करनी चाहिए थी, जैसे शिक्षा और परीक्षाओं की सूरत बदलनी चाहिए थी, लेकिन नई शिक्षा नीति के बाद भी शिक्षा का हाल संतोषजनक नहीं और परीक्षाओं, विशेषरूप से प्रतियोगी परीक्षाओं का हाल तो बहुत ही बुरा है। इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारें एक ही नाव पर सवार हैं। रह-रहकर प्रश्नपत्र लीक होते रहते हैं। मोदी सरकार की एक बड़ी विफलता न्याय को सुलभ और सुगम न बना पाना है। लचर न्यायिक तंत्र देश के विकास में एक बड़ी बाधा है। इसी तरह की एक बड़ी बाधा सरकारी कामकाज में व्याप्त भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार लाइलाज हो गया दिखता है। जहां निर्माण वहां तो भ्रष्टाचार है ही, इसके अलावा जहां कहीं भी सरकारी अनुमति, अनुमोदन आदि की आवश्यकता होती है, वहां भी लेन-देन होता है। स्मार्ट सिटी योजना भी कुल मिलाकर नाकाम ही रही और हमारे शहर बेतरतीब विकास की कहानी कहने के साथ विकसित भारत के लक्ष्य का बड़ी बाधा बने हुए हैं। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि मोदी सरकार अपनी 12 बरस की उपलब्धियों को गिनाते समय इस पर गंभीरता से ध्यान दे कि उसे कुछ विफलताएं भी हाथ लगी हैं, जिनके कारण देश में बेचैनी बढ़ रही है।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

धर्म का मर्म

धर्म एक ऐसा विशाल छत्र है, जिसकी छाया में पूरा संसार क्रियाशील है। ये धर्म ही है, जो जगत को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए एक अदृश्य संविधान के रूप में संसार में व्याप्त है। यही अनंतकाल से भौतिक संसार को निर्बाध बांधे हुए है। धर्म की विकृत तथा संकुचित परिभाषा ने हमें यह विश्वास दिला दिया है कि धर्म का अभिप्राय मात्र मत या पंथ से है। वास्तविकता में तो धर्म वह अटल एवं शाश्वत सिद्धांत है, जिसके माध्यम से संसार की हर क्रिया संचालित होती है। ग्रहों का धर्म है एक निश्चित गति पर सूर्य की परिक्रमा करना, ऋतुओं का धर्म है अपने स्वभाव अनुसार फल देना, वृक्ष का धर्म है छाया तथा फल देना।

मानव के संबंध में धर्म का मर्म बहुत व्यापक है। मानव के अतिरिक्त संपूर्ण जगत का धर्म एक धुरी से बंधा हुआ है, किंतु मानव का धर्म और व्यवहार देश-काल एवं परिस्थिति के सापेक्ष भी है। उसे इस कसौटी पर खरा भी उतरना है, क्योंकि यदि व्यक्ति परिस्थिति के अनुरूप धर्मोचित व्यवहार न करे तो वह अधर्म है। इस कारण भी कि मानव के पास ही वह विवेक है जो तय करता है कि उसके लिए किस समय क्या धर्म है। यहां प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि धर्म का अनुपालन आवश्यक क्यों है? वस्तुतः, धर्म ही वह महीन रेखा है जो उचित तथा अनुचित को अलग करती है।

मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का समग्र जीवन एक आदर्श धर्मोचित जीवन का जीवंत उदाहरण है। तभी हम कहते हैं 'रामो विग्रहवान धर्मः' अर्थात राम ही धर्म का विग्रह स्वरूप हैं। अतः जीवन में धर्म का पालन कर्तव्य से मुक्ति के लिए आवश्यक है। महाभारत की शिक्षा है 'यतो धर्मस्ततो जयः' अर्थात जहां धर्म है, वहीं विजय है और विजयश्री का आलिंगन धर्म की परिधि में ही संभव है। धर्म ही उत्थान है और अधर्म ही पतन।

आदित्य नारायण अवस्थी

'साइकिल संस्कृति' को करें आत्मसात

सुधीर कुमार

एम्स्टर्डम की सड़कों और गलियों को साइकिल चालकों की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है

नीदरलैंड (हालैंड) की राजधानी एम्स्टर्डम अपनी अनूठी 'साइकिल संस्कृति' के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस शहर की तकरीबन 60 प्रतिशत से अधिक आबादी आवागमन के लिए प्रतिदिन साइकिल का इस्तेमाल करती है। हां के नागरिकों में साइकिल के प्रति गजब का जुनून है। यह उनकी जीवनशैली का हिस्सा होने के साथ-साथ 'स्टेटस सिंबल' तक बन चुका है।

एम्स्टर्डम एक ऐसा शहर है, जहां की सड़कों और गलियों को साइकिल चालकों की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जबकि आमतौर पर ऐसा करते समय साइकिल चालकों के बारे में गंभीरता से सोचा भी नहीं जाता है। हालांकि एम्स्टर्डम को अपनी विशिष्ट साइकिल संस्कृति विकसित करने में दशकों लग गए। इसे परिवहन का व्यावहारिक साधन बनाने में कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का प्रमुख योगदान रहा। द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) के दौरान ईंधन की उपलब्धता के प्रभावित होने से साइकिल ही आवागमन का सहारा बनी, जिससे साइकिल की मांग एकाएक बढ़ गई, लेकिन विश्वयुद्ध के खत्म होते-होते जीवाश्म ईंधन आधारित वाहनों की मांग में जबरदस्त उछाल आ गया। 1950-60 के दशक तक आते-आते वहां चार पहिया वाहनों की संख्या इस कदर बढ़ी कि साइकिल चालकों को शहर से बाहर निकाले जाने का खतरा महसूस होने लगा। हालांकि, 1973 के तेल संकट ने इस परिदृश्य को एक बार फिर बदल दिया। अरब निर्यातक देशों द्वारा नीदरलैंड समेत कई देशों पर प्रतिबंध लगाने के फलस्वरूप तेल की कीमत चौगुनी हो गई। इसी बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री जूप डेन उइल द्वारा डच नागरिकों से जीवनशैली में बदलाव लाने और ऊर्जा बचत के आह्वान ने लोगों को टिकाऊ परिवहन की ओर अग्रसर किया। साइकिल के प्रति बढ़ते क्रेज का नतीजा है कि आज एम्स्टर्डम में साइकिलों की संख्या वहां के निवासियों से अधिक हो गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, एम्स्टर्डम की आबादी लगभग आठ लाख है, जबकि साइकिलों की संख्या साढ़े आठ लाख से भी अधिक पहुंच चुकी है। इस अनूठी साइकिल संस्कृति से एम्स्टर्डम को यातायात की भीड़ एवं वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने और सतत विकास को बढ़ावा देकर 'नेट जीरो' के 2050 तक निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिली है। यह 'जीवन प्रत्याशा' को सुधारने और नागरिकों के लिए आर्थिक बचत का माध्यम भी बन रहा है।

साइकिल परिवहन का किफायती और पर्यावरणनुकूल साधन है। इसे प्राथमिकता देने से ईंधन की बचत होगी, निर्भरता घटेगी और प्रदूषण-मुक्त समाज की स्वप्न भी साकार हो पाएगा। ईंधन संकट के मौजूदा दौर में समाज को 'साइकिल संस्कृति' की ओर लौटना ही होगा।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

शिक्षा के स्तर में हो सुधार

'अविश्वास से घिरती जा रही परीक्षाएं' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में जगमोहन सिंह राजपूत ने परीक्षा व्यवस्था पर गहराते अविश्वास, नकल, प्रश्नपत्र लीक तथा नैतिक मूल्यों के क्षरण की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। निःसंदेह यह चिंता समयोचित है, किंतु इस संकट की जड़ें परीक्षा कक्षों से कहीं अधिक गहरी हैं। यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि सामाजिक अपेक्षाओं, आर्थिक असमानताओं और शिक्षा की बदलती प्राथमिकताओं का भी परिणाम है। वर्तमान समय में परीक्षा ज्ञानार्जन का साधन कम और आजीविका का प्रवेशद्वार अधिक बन गई है। करोड़ों युवा सीमित अवसरों के लिए संघर्षरत हैं। जब नियुक्तियां वर्षों तक लंबित रहें, प्रतियोगिता असंतुलित हो और सफलता का एकमात्र मानदंड अंक बन जाएं, तब व्यवस्था के प्रति संशय स्वाभाविक है। दुर्भाग्य यह है कि हम परिणामों पर विमर्श करते हैं, कारणों पर नहीं। एक तथ्य यह भी है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व निर्माण, विवेक और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास माना गया था, किंतु आज वह अंकों और प्रमाणपत्रों की प्रतिस्पर्धा में सिमटती जा रही है। कोचिंग-केंद्रित संस्कृति ने जिज्ञासा का स्थान स्मरणशक्ति को और ज्ञान का स्थान परीक्षा-कौशल को दे दिया है। ऐसी स्थिति में अनैतिक साधनों का आकर्षण बढ़ना अस्वाभाविक नहीं। समाधान केवल कठोर दंड में नहीं, बल्कि विश्वास की पुनर्स्थापना में निहित है। भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया जाए। विद्यालयों में नैतिक शिक्षा, तार्किक चिंतन और कौशल विकास को समान महत्व मिले। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाकर युवाओं की अनिश्चितता कम की जाए। परीक्षा तभी विश्वसनीय बनेगी, जब व्यवस्था निष्पक्ष, अवसर पर्याप्त और समाज ईमानदारी को सफलता से अधिक सम्मान देने लगेगा।

awanishg30@gmail.com

मेलबाक्स

रासायनिक उर्वरकों का उपयोग

'खेत बचाओ अभियान' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के नुकसान से अवगत कराया गया है। यह अत्यधिक उपयोग जिन कारणों से होता है उसमें सरकार द्वारा रासायनिक उर्वरकों पर दी जाने वाली भारी सब्सिडी है। जिसके कारण प्रति वर्ष सरकार को पौने दो लाख करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इसकी कीमत घट जाती है। किसान नासमझी में या यूं कहें जागरूकता के अभाव में अत्यधिक पैदावार के लोभ में दोगुना उर्वरकों का प्रयोग कर डालते हैं। जाहिर सी बात है यूरिया में एनपीके की मात्रा भी असंतुलित रहती है। आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का अनुपात 4:2:1 होना चाहिए। कहीं-कहीं अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी बंजर होने के कगार पर है।

मुकेश कुमार मनन, पटना

विकास या मौत का जाल

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का गिरना कोई सामान्य तकनीकी खराबी या प्राकृतिक हादसा नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर प्रशासनिक साठगांठ, भ्रष्टाचार और इंसानी जिंदगियों के साथ किया गया एक घिनौना खिलवाड़ है। इस पूरे मामले में जो सबसे गंभीर और आपराधिक लापरवाही सामने आई है, वह यह है कि तीन महीने पहले ही पिलर में आई दरार को तकनीकी रूप से ठीक करने के बजाय महज सीमेंट से पाटकर छिपा दिया गया। सोचने कि बात यह है कि अगर यह लापरवाही समय रहते सामने न आती और पुल बनकर तैयार हो जाता तो क्या होता? इससे भी बड़ा सवाल सरकार और नीति-निर्धारकों पर उठता है कि जिस कंपनी का पुल पहले बिहार में गिर चुका है, उसे ब्लैकलिस्ट करने के बजाय यूपी में दोबारा करोड़ों के टेंडर क्यों सौंप दिए गए? साफ है कि यहां जनता की सुरक्षा से ज्यादा महत्व कमीशनखोरी को दिया गया। जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक जनता के पैसे और उनकी जिंदगियों के साथ ऐसा खिलवाड़ जारी रहेगा।

निकिता जोशी, कानपुर

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एजीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

90 लाख भारतीय रहते हैं और काम करते हैं अकेले खाड़ी के देशों में। वे न केवल भारत में अपनी गाढ़ी कमाई भेजकर देश की अर्थव्यवस्था को सहारा देते हैं, बल्कि वे विदेश में भारत के सांस्कृतिक राजदूत भी हैं।

आजकल

वैश्विक मंच पर उभरता भारत

हाल में संपन्न प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पांच देशों-यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नार्वे और इटली की यात्रा केवल एक कूटनीतिक दौरा नहीं, बल्कि 21वीं सदी में भारत की वैश्विक महाशक्ति बनने की आकांक्षा का एक जीवंत घोषणापत्र है। यह यात्रा भारत के लिए सामरिक सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता, ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और आर्थिक संप्रभुता को मजबूत करने का एक ऐसा अवसर बनकर उभरी है, जिसका प्रभाव आने वाले कई दशकों तक महसूस किया जाएगा

पश्चिम एशिया में तनाव के बीच यूएई के साथ मिलकर अपनी ऊर्जा आपूर्ति लाइन को सुरक्षित करता भारत। फाइल

श्री राम शा
shriramshaw@nda.jagran.com

वैश्विक राजनीति और अर्थनीति आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां पुराने समीकरण बदल रहे हैं, और नए गठबंधनों का उदय हो रहा है। अमेरिकी विदेश नीति में आए बदलावों, रूस-यूक्रेन युद्ध के लंबे खिंचते संकट और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच पूरी दुनिया नए और भरोसेमंद साझेदारों की तलाश में है। ऐसे नाजुक और ऐतिहासिक मोड़ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पांच देशों - संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), नीदरलैंड्स, स्वीडन, नार्वे और इटली की यात्रा केवल एक कूटनीतिक दौरा नहीं, बल्कि 21वीं सदी में भारत की वैश्विक महाशक्ति बनने की आकांक्षा का एक जीवंत घोषणापत्र है। यह यात्रा भारत के लिए सामरिक सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता, ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और आर्थिक संप्रभुता को मजबूत करने का एक ऐसा त्रिवेणी संगम बनकर उभरी है, जिसका प्रभाव आने वाले कई दशकों तक महसूस किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस पांच दिवसीय यात्रा का पहला पड़ाव संयुक्त अरब अमीरात था, जो वैश्विक तेल बाजार में आए भूचाल और अमेरिका-इजरायल-ईरान संघर्ष के कारण बेहद संवेदनशील समय पर हुआ। जब पूरा पश्चिम एशिया अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, तब भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को एक मजबूत ढाल प्रदान की। यह तथ्य है कि भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग दसवां हिस्सा यूएई से आयात करता है और वह यूएई की तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का सबसे बड़ा खरीदार भी है।

इस यात्रा के दौरान हुए महत्वपूर्ण समझौते भारत की दूरदर्शिता को दर्शाते हैं। 'इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड' और यूएई की 'एड्नाक' के बीच हुए समझौते के तहत यूएई भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व में कच्चे तेल की आपूर्ति को बढ़ाकर तीन करोड़ बैरल करेगा। दोनों देशों ने भारत में रणनीतिक गैस रिजर्व स्थापित करने की संभावनाओं पर सहमति जताई, ताकि भविष्य में किसी भी वैश्विक आपूर्ति संकट से देश को बचाया जा सके। यूएई ने भारत में पांच अरब डालर (लगभग 41 हजार करोड़ रुपये) के नए निवेश की प्रतिबद्धता जताई, जो दोनों देशों के बीच पहले से चल रहे 85 अरब डालर के द्विपक्षीय व्यापार को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यात्रा का अगला चरण यूरोप के नवाचार और तकनीक के गढ़-नीदरलैंड्स और स्वीडन की ओर था। वर्तमान समय में यूरोप चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता को कम करना चाहता है और रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद अपनी रक्षा और ऊर्जा प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय कर रहा है। ऐसे में यूरोप भारत को एशिया में सबसे भरोसेमंद लोकतांत्रिक साझेदार के रूप में देख रहा है। नीदरलैंड्स की यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण तकनीकी क्षेत्र, विशेषकर सेमीकंडक्टर मिशन रहा। नीदरलैंड्स दुनिया की सबसे उन्नत लिथोग्राफी मशीनें बनाने वाली कंपनी एएसएमएल का घर है, जिसके बिना आधुनिक सेमीकंडक्टर चिप निर्माण असंभव है। इस यात्रा के दौरान गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जो भारत को वैश्विक चिप निर्माण का केंद्र बनाने के सपने को साकार करेगा। दोनों देशों ने बैटरी, इलेक्ट्रानिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवश्यक 'क्रिटिकल मिनरल्स' (महत्वपूर्ण खनिजों) की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समझौते किए। जल प्रबंधन और ग्रीन हाइड्रोजन में डच महारत का लाभ उठाने पर भी सहमति बनी।

गोटेबर्ग में स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन के साथ हुई बैठक ने भारत-यूरोप संबंधों को नया आयाम दिया। भारत और स्वीडन के संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' के स्तर पर ले जाया गया। दोनों देशों ने 'संयुक्त नवाचार साझेदारी 2.0' और 'भारत-स्वीडन प्रौद्योगिकी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कारिडोर' की शुरुआत की। अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का संकल्प लिया गया।

यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली पहुंचे। मोदी और मेलोनी के बीच द्विपक्षीय बैठक में भावी रणनीतिक साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा हुई। भारत-इटली संयुक्त कार्य योजना 2025-29 इस साझेदारी को एक व्यावहारिक एवं भविष्योन्मुखी ढांचा प्रदान करती है। साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत-ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा हुई। 2027 में 'इटली-इंडिया ईयर आफ कल्चर एंड टूरिज्म' मनाने की योजना का भी एलान किया, जिसका मकसद दोनों सभ्यताओं के लोगों के बीच रिश्तों को और मजबूत करना है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पांच देशों की यात्रा ने अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के बीच भारत को लेकर एक अभूतपूर्व विश्वास पैदा किया है। आज जब वैश्विक बाजार में अनिश्चितता और मंदी का माहौल है, निवेशक अत्यधिक सतर्क हैं और पूंजी सुरक्षित स्थानों की तलाश में है, तब भारत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) को आकर्षित करने में सफल रहा है। ज्ञात हो कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश केवल धन नहीं लाता, यह बिना ब्याज की ऐसी पूंजी है, जो देश में आधुनिक तकनीक लाती है, विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करती है और बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसरों का सृजन करती है।

सामने आईं चीन की रणनीतिक सीमाएं

धीरज यादव
भू-राजनीति, रक्षा और रणनीतिक मामलों के जानकार

हालिया वैश्विक संघर्षों ने दुनिया के सामने शक्ति संतुलन की एक नई तस्वीर पेश की है। जहां एक ओर अमेरिका ने ईरान की सैन्य शक्ति और नेतृत्व को भारी क्षति पहुंचाई है, वहीं दूसरी ओर खुद को सुपरपावर बताने वाले चीन की रणनीतिक निष्क्रियता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की संतुलित कूटनीति कारगर साबित हो रही है। चीन का रणनीतिक साझेदार ईरान आज अपने इतिहास के एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है।

भौगोलिक रूप से भी दोनों देशों के बीच केवल पाकिस्तान है, इसके बावजूद, चीन न तो ईरान को आधुनिक हथियारों की पर्याप्त आपूर्ति कर पाया और न ही उसके सैन्य बलों को ठोस सैन्य प्रशिक्षण या रणनीतिक सहायता दे पाया। यह विफलता इसलिए अधिक चौंकाने वाली है, क्योंकि ईरान तथा अमेरिका-इजरायल के बीच युद्ध के संकेत पिछले वर्ष 12-दिवसीय लड़ाई से ही मिल गए थे और दोनों पक्षों के बीच शत्रुता दशकों पुरानी है। चीन के विपरीत अमेरिका हजारों मील दूर से अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार वह 13000 से अधिक लक्ष्यों पर हमले कर ईरान की कमर तोड़ चुका है।

अमेरिका ने ईरान के शीर्ष नेतृत्व, सैन्य शक्ति और परमाणु ढांचे को भारी क्षति पहुंचाई है। अमेरिका, इजरायल और अन्य खाड़ी देशों को भी नुकसान हुआ है, पर वह तुलनात्मक रूप से काफी कम है। यह सही है कि अमेरिका इस समय कई मोर्चों पर एक साथ उलझा हुआ है- जहां एक ओर वह ईरान के साथ युद्ध में फंसा है, वहीं दूसरी ओर क्यूबा की तेल नाकाबंदी कर रखी है और 2022 से यूक्रेन को निरंतर समर्थन भी दे रहा है। इसके बावजूद चीन ने ताइवान के एकीकरण के लिए किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई से परहेज किया है। यह अमेरिका और चीन की सैन्य क्षमताओं के बीच बड़े अंतर को दर्शाता है। यह चीन की उस छवि को धूमिल करता है जिसमें उसे अमेरिका के विकल्प के रूप में देखा जा रहा था।

अमेरिका एक-एक करके चीन के सहयोगी देशों को परास्त कर एवं उनमें सत्ता परिवर्तन कर अपने सहयोगियों में बदल रहा है। अन्य देश देख रहे हैं कि चीन के हथियारों और उसकी रणनीतिक साझेदारी पर भरोसा करना कितना जोखिम भरा हो सकता है। इससे साफ हो रहा कि अब वे अमेरिकी एवं यूरोपीय हथियार ज्यादा खरीदेंगे और हर परिस्थिति में अमेरिका से अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करेंगे। ब्रिक्स सदस्य और कच्चा तेल उत्पादित करने वाले खाड़ी देश भी डी-डालराइजेशन जैसी किसी पहल का समर्थन करने से कतराएंगे।

इस समय भारत की राष्ट्रहित सर्वोपरि की नीति अत्यंत तर्कसंगत है- अमेरिका से अनावश्यक टकराव नहीं, लेकिन जहां राष्ट्रहित हो वहां दृढ़ता से खड़े रहना है। भारत ने अमेरिकी सैन्य कारवाई की खुली आलोचना नहीं की, परंतु साथ ही ईरान के युद्धपोत आइआरआइएस लवान को कोच्चि में शरण दी और उसके 100 से अधिक नौसैनिकों को अर्मेनिया के रास्ते सुरक्षित वापस भी भेज दिया। इस संतुलित नीति का ही परिणाम है कि आज भारत के अमेरिका से भी अच्छे संबंध हैं और ईरान ने भी 18 अप्रैल को हार्मुज जल मार्ग को दोबारा बंद करने से पहले जिन गिने चुने मित्र देशों के जहाजों को गुजरने की अनुमति दी थी उनमें भारत भी शामिल था। यह भारत की संतुलित विदेश नीति का प्रमाण है।

भारत अब संतुलित कूटनीति से अपने राष्ट्रीय हितों को साध रहा है यही रणनीतिक स्वायत्तता है और यही भारत को भविष्य में एक बड़ी शक्ति बनने की ओर अग्रसर कर रही है।

खरी-खरी

झालमूड़ी-मेलोडी संवाद

डा. प्रदीप मिश्र

एक दिन झालमूड़ी ने मेलोडी को तीखी जुबान में हड़काया, 'क्यों री! आजकल तू कुछ ज्यादा इतरा रही है? फारेन क्या हो आई, तेरे भाव ही नहीं मिल रहे हैं? दूकानों में तू आउट आफ स्टाक हो गई है। देख मूलतः तू मीठी-गोली है। लोगों ने तुझे टाफी क्या कह दिया, तू खुद को चाको-लावा केक समझने लगी? बिन्नो जरा पांव-पांव चल।'

'मैंने ऐसा क्या किया जिज्जी? मेरा स्वाद तो आपके बाद आता है...पहले तीखा फिर मीठा। तीखे के बिना मीठे को कौन पूछे? आपका दिव्य स्वाद शरीर को झंकृत करने में समर्थ होता है। मैं तो अपनी मिठास से आपकी झनझनाहट को शांत करती हूं।' मेलोडी की जुबान में मिठास घुली थी।

'तू मुझ पर तीखेपने का लेबल चिपकाने का षड्यंत्र कर रही है।' झालमूड़ी झल्लाई। मेलोडी मुस्काई, 'आपके तो नाम में ही स्वाद जैसा तीखापन है। मेरे नाम में मेरे स्वाद की मिठास है।'

'तेरी मिठास, मिठास नहीं महामारी है। फैलाती शक्कर की बीमारी है। तू फैशनबाजों की लाचारी है। जबकि जमीनी लोगों की पसंद झालमाड़ी है।' झालमूड़ी ने आरोपों की झड़ी लगाई। मेलोडी मीठी तो थी, लेकिन जवाब देने में मुंह तोड़ थी, 'ये सारी बातें घात और प्रतिघात हैं। डाक्टर अपने मरीज से पहले मिर्च-मसाला ही छुड़वाते हैं। तुझे खाकर जब अच्छे-अच्छे तीखाड़ू जब सिसियाते हैं, तब मेलाडी को ही मुंह लगाते हैं।'

'ये बता क्या है तेरा बायोडाटा? तूने कितनों को कितने चुनाव जितवाए हैं? मैं हूं देसी, लेकिन मेरा इफेक्ट है बड़ा विशेषी। दस रुपये में मुझे खरीदो। मेरे संग सेल्फी खिंचाओ और प्रचंड बहुमत से कुर्सी का सुख पाओ।'

'पर जिज्जी तुझे कोई किसी को गिफ्ट कर सकता है क्या? तू है लोकल, मैं हूं ग्लोबल। तेरे पास जनबल तो मेरे पास मिठास का मनोबल। मैंने संभाले हैं देशों से रिश्ते, तुझे खाकर लोग पानी को तरसते। छोड़ जिज्जी आपस के झगड़े। अपने-अपने क्षेत्र में हम दोनों ही हैं तगड़े?' मेलोडी ने बातों में मिठास घोली। अब झालमूड़ी भी स्वाद तो नहीं, लेकिन मन से मीठी हो चुकी थी।

पोस्ट

भारतीय इतिहास, राजनीति पर शोध करने वाले अधिकांश पश्चिमी शिक्षाविद शोधार्थी नहीं राजनीतिक कार्यकर्ता हैं।
अभिनव प्रकाश@Abhina_Prakash

पाठ्यक्रम और परीक्षा के बीच अंतर की भरपाई करने वाले तंत्र का नाम ही कोचिंग है। सरकार इस गैप को भर दे तो कोचिंग का क्या काम? लिहाजा कोचिंग वाले टीचर्स को गाली देने से कुछ नहीं होने वाला, सिस्टम में सुधार चाहते हैं तो दबाव नीति निर्धारकों पर बनाइए।
मधुरेंद्र कुमार@Madhurendra13

यह बात सोलह आने सच है कि टीवी पत्रकारों वाली बीमारी आनलाइन अध्यापकों को भी लग गई और वह बीमारी है लोकप्रियता का रोग। जबकि सही बात अलोकप्रिय भी होती है। वायरल के मोह से आगे बढ़ना ही होगा। तमाशा पत्रकारिता का विकल्प तमाशा शिक्षा नहीं। संकेत उपाध्याय@sanket

तमिलनाडु में अन्नामलाई को किनारे करके भाजपा सही नहीं कर रही। वैसे, यह पहली बार नहीं है जब पार्टी में अपनी प्रतिभाओं को उपेक्षित और दोयम दर्जे के बाहरी नेताओं को उपकृत किया जा रहा हो।
मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या अमेरिका-ईरान के बीच कायम युद्धविराम खतरे में पड़ता दिख रहा है?

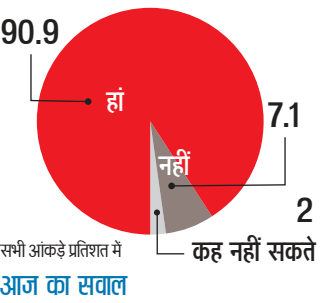

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने से तमिलनाडु में भाजपा की राह और मुश्किल होगी?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

साईं कबहुं न कीजिए 'इतने बढ़िया' काम,
हेलमेट में चलना पड़े हो करके बदनाम।
हो करके बदनाम लोग बरसाएं अंडे,
दौड़ाएं कुछ लोग हाथ में लेकर डंडे!
करि मनमाना काम स्वयं हित खोदे खाईं,
अब तो मालिक राम बचाएं 'उनको' साईं!!
-ओम प्रकाश तिवारी

रविंद्र बड़थ्वाल
उत्तराखंड राज्य ब्यूरो प्रमुख

उत्तराखंड डायरी

जीत की हैटट्रिक लगाने की चुनौती

उत्तराखंड में वर्ष 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में वर्ष 2017 का प्रदर्शन दोहराने का लक्ष्य रखा गया है। यानी विधानसभा सीटों की संख्या 47 से वापस 57 तक पहुंचाना भाजपा की धामी सरकार और प्रदेश संगठन के लिए नवीन टास्क है। विभिन्न प्रदेशों में बहुमत को प्रचंड बहुमत में बदलने में भाजपा को जिस प्रकार सफलता मिल रही है, पार्टी को इससे नया हौसला मिला है। बंगाल और असम में मिले प्रचंड बहुमत के बाद उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में भी भाजपा इसी प्रकार सांगठनिक कौशल में हाथ आजमाने जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने पहले तीन दिवसीय उत्तराखंड दौरे में बेहद सतर्कता से आगामी चुनाव में जीत की हैटट्रिक के लिए व्यूह रचना तैयार की। विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के फार्मूले को जमीन पर उतारने का दारोमदार विधायकों से लेकर सांसदों पर भी होगा। उनका प्रदर्शन आंकने का यह आधार बनेगा।

उत्तराखंड की रणभूमि में एक और प्रयोग आजमाने की तैयारी है। समान नागरिक संहिता, मदरसा बोर्ड समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण, बलवाइयों से संपत्ति क्षति की वसूली, मतांतरण पर सख्ती, धार्मिक प्रतीक चिह्नों की आड़ में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खेल पर शिकंजा कसने समेत अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के विरुद्ध मजबूत कानूनी आवरण तैयार करने का प्रयोग उत्तराखंड में सफल रहा है। सनातन और हिंदुत्व की भावभूमि में खड़ा किया गया यह माडल अन्य प्रदेशों के लिए अब मिसाल है। अन्य प्रदेशों में भी जनता ने इस माडल के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। इससे उत्साहित भाजपा ने प्रदेश में जीत के अंतर को भारी से प्रचंड बहुमत में बदलकर हैटट्रिक लगाने को अपना अगला मिशन बनाया है। इसके लिए जमीन तैयार करने में ताकत झोंकी जा रही है।

वर्ष 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। फाइल

राज्य के अगले चुनावी महासमर में उन सभी हथियारों का प्रयोग होने जा रहा है, जिनके बूते भाजपा ने अब तक अपनी विजय यात्रा को प्रचंड जीत में बदला है। बंगाल में विपरीत परिस्थितियों को लगातार सक्रियता और संघर्ष के बूते अपने पक्ष में करने में पार्टी को बड़ी सफलता मिली। वहीं असम में हैटट्रिक के लिए जमीनी तैयारी से लेकर आक्रामक रणनीति का कमाल देखने को मिला। देवभूमि का मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड सनातन को लेकर भाजपा की राजनीति के सशक्त केंद्र के रूप में उभरा है।

केंद्र की सत्ता में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रहते हुए उत्तराखंड में वर्ष 2027 में लगातार तीसरा विधानसभा चुनाव होगा। इस चुनाव को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की गंभीरता का अंदाजा इससे लग सकता है कि चुनावी वर्ष प्रारंभ होने के साथ ही शंखनाद के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं यहां आ चुके हैं। भाजपा के नए अध्यक्ष ने राज्य में चुनाव की तैयारियों के लिए पूरे तीन दिन का समय निकाला। जीत का दायरा व्यापक करने की इच्छाशक्ति मजबूत करने के लिए उन्होंने सरकार से लेकर संगठन में हर स्तर पर जिम्मेदारियां तय कीं। अगला चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इस पर भी मुहर लगा दी। विधायकों, सांसदों और सरकार के बीच किसी भी प्रकार के मनमुटाव दूर करने को नितिन नवीन की प्राथमिकता का अंदाजा इससे लग सकता है कि उनके देहरादून में रहते हुए ही ऊधम सिंह नगर के गदरपुर से विधायक अरविंद पांडेय गिले-शिकवे भुलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने उनके आवास पहुंचे। इसके बाद से संगठन की एकजुटता को लेकर उनके बयान इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं। सांसदों की जवाबदेही बढ़ाकर उसे हारी हुई सीटों पर जीत तक ले जाने के लिए साफ-साफ निर्देश दिए गए हैं। विधायकों के साथ सांसदों को विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करना सुनिश्चित किया गया है।

विशेष रूप से हरिद्वार, नैनीताल और अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों पर सांसदों के कौशल को परखा जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार जिले की 11 विधानसभा सीटों में से भाजपा के पास मात्र तीन ही हैं, जबकि वर्ष 2017 में भाजपा की झोली में आठ सीट आईं थीं। 2022 में नैनीताल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ऊधम सिंह नगर जिले की नौ में से पांच सीटें कांग्रेस को मिलीं, जबकि भाजपा को चार सीट पर संतोष करना पड़ा। वर्ष 2017 में इसी जिले में भाजपा को नौ में से आठ सीटें हासिल हुई थीं। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिले में भी भाजपा का प्रतिनिधित्व 2017 की भांति बढ़ाने की चुनौती है।

मंथन

बेचैन युवा भारत की अभिव्यक्ति

आज राजनीतिक विमर्श का बड़ा हिस्सा इंटरनेट मीडिया पर आकार ले रहा है। जनमत अब इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शाट्र्स, एक्स पोस्ट और वायरल मीम्स के जरिये भी निर्मित हो रहा है

डा. महुआ माजी
सदस्य, राज्यसभा

भारतीय लोकतंत्र आज एक गहरे सामाजिक और राजनीतिक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। यह परिवर्तन केवल संसद या चुनावी परिणामों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की मानसिक संरचना, संवाद की प्रकृति और जनमत निर्माण की प्रक्रिया तक फैल चुका है। आज राजनीतिक विमर्श का बड़ा हिस्सा इंटरनेट मीडिया पर आकार ले रहा है। जनमत अब पारंपरिक माध्यमों से आगे बढ़कर इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शाट्र्स, एक्स पोस्ट, वायरल मीम्स के जरिये निर्मित हो रहा है। इसी पृष्ठभूमि में ''काकरोच जनता पार्टी'' जैसी अचानक उभरी लोकप्रियता को सिर्फ डिजिटल ट्रेंड मान खारिज नहीं किया जा सकता। यह उस बेचैन युवा भारत की अभिव्यक्ति है, जो स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहा है।

समाजशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो जब किसी समाज की मुख्य संस्थाएं-राजनीति, प्रशासन, शिक्षा और मीडिया जनभावनाओं से दूरी बनाने लगती हैं, तब नए प्रतीक और नई राजनीतिक भाषाएं जन्म लेती हैं। कई बार ये प्रतीक व्यंग्य के रूप में सामने आते हैं, लेकिन इनके भीतर गहरी सामाजिक पीड़ा और असंतोष छिपा होता है। ''काकरोच जनता पार्टी'' इसी डिजिटल युग का एक ऐसा ही सांकेतिक प्रतिरोध है। काकरोच एक ऐसा जीव है, जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह जाता है। यह प्रतीक आज के उस युवा मानस को आकर्षित करता है, जो बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं की अनिश्चितता, आर्थिक असुरक्षा और सामाजिक दबाव के बीच किसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। भारत आज विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में है। देश की लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। शिक्षित बेरोजगारी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। आंकड़े बताते हैं युवाओं में बेरोजगारी की दर औसत से अधिक बनी हुई है। लाखों युवा वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रियाएं या तो विलंबित होती हैं या विवादों में उलझ जाती हैं। यह स्थिति केवल आर्थिक नहीं, बल्कि गहरे सामाजिक असंतोष का कारण बन रही है।

आज का युवा केवल रोजगार नहीं चाहता, वह सम्मानजनक भागीदारी चाहता है। वह यह महसूस करना चाहता है कि लोकतंत्र में उसकी आवाज सुनी जा रही है, लेकिन जब उसे मंचों पर केवल औपचारिक आश्वासन और इंटरनेट मीडिया पर केवल प्रचार दिखाई देता है, तब वह अपनी अभिव्यक्ति के नए माध्यम खोजता है। वर्तमान चुनावी परिदृश्य में यह प्रवृत्ति और अधिक स्पष्ट हो गई है। चुनाव अब केवल मतदान केंद्रों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़े जा रहे हैं। राजनीतिक दलों के डिजिटल अभियान, आइटी सेल और इंटरनेट मीडिया रणनीतियां जनमत निर्माण में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं, लेकिन इस डिजिटल राजनीति के बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार अनुत्तरित है-क्या हम वास्तव में युवा भारत की मूल चिंताओं को समझ पा रहे हैं? आज का युवा पहले की तरह केवल परंपरागत राजनीतिक निष्ठाओं से बंधा नहीं है। वह प्रश्न पूछता है, तुलना करता है, तथ्य जांचता है और तुरंत प्रतिक्रिया देता है। इंटरनेट मीडिया ने उसे अभूतपूर्व अभिव्यक्ति की शक्ति दी है। यह लोकतंत्र के विस्तार का भी संकेत है और उसकी नई चुनौती भी।

इंटरनेट मीडिया की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने लोकतंत्र को अधिक सहभागी बनाया है। छोटे शहरों और दूरदराज क्षेत्रों के युवा भी अब राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन रहे हैं। जो आवाजें पहले अनसुनी रह जाती थीं, वे अब सीधे लाखों लोगों तक पहुंच रही हैं। भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विफलता और सामाजिक अन्याय पर तुरंत प्रतिक्रिया संभव हुई है। यह लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी गंभीर है। इंटरनेट मीडिया ने राजनीति को अत्यधिक तात्कालिक और भावनात्मक बना दिया है। अब विचारों की गहराई से अधिक उनकी वायरल क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। कई बार नीतिगत बहसें पीछे छूट जाती हैं और प्रतीकात्मक राजनीति आगे बढ़ जाती है। एल्गोरिदम आधारित इस व्यवस्था में वही सामग्री अधिक फैलती है, जो उत्तेजना पैदा करे। इससे सामाजिक ध्रुवीकरण और वैचारिक टकराव बढ़ता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि युवाओं की वास्तविक समस्याएं कहीं डिजिटल मनोरंजन में न बदल जाएं। बेरोजगारी, शिक्षा की गुणवत्ता, अवसरों की असमानता और भविष्य की अनिश्चितता जैसे गंभीर प्रश्न कई बार मीम संस्कृति में सीमित हो जाते हैं। यह लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं है।

जब संवाद कमजोर होता है, तब प्रतिरोध असामान्य रूप ले लेता है।

प्रतीकात्मक

इंटरनेट मीडिया युग में यह प्रवृत्ति और तेज हुई है, क्योंकि यहां प्रतिक्रिया तत्काल मिलती है, लेकिन समाधान नहीं। राजनीतिक दलों के लिए यह समय आत्ममंथन का है। यदि युवा व्यंग्यात्मक प्रतीकों और डिजिटल आंदोलनों के माध्यम से अपनी राजनीतिक अभिव्यक्ति खोज रहा है तो यह संकेत है कि मुख्यधारा की राजनीति उसके विश्वास को पूरी तरह जीत नहीं पाई है। केवल प्रचार और नारों से यह दूरी कम नहीं होगी। इसके लिए रोजगार, शिक्षा, पारदर्शिता और वास्तविक सहभागिता को केंद्र में लाना होगा।

बिजनेस

बाटलिंग सब्सिडियरी का आइपीओ ला सकती है कोका कोला

नई दिल्ली : वैश्विक बेवरेज दिग्गज कोका कोला कंपनी अपने भारत स्थित बाटलिंग सब्सिडियरी हिंदुस्तान कोका कोला होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (एचसीसीएच) का अगले वर्ष आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) लाने पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी एचसीसीएच में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने पर भी विचार कर रही है। कोका कोला ने करीब एक वर्ष पहले एचसीसीएच में अपनी 40 प्रतिशत हिस्सेदारी जुबिलेंट भरतिया समूह को बेची थी। हालांकि, अभी तक इसका वित्तीय विवरण सामने नहीं आया है। (प्रेट्र)

भारत आयातित तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ऐसे में ओमान के साथ व्यापार समझौता भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
– शिशिर प्रियदर्शी, प्रेसिडेंट, सीआरएफ

सेंसेक्स	74,649.84 ▲ 382.50	निफ्टी	23,483.55 ▲ 100.95	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 1,61,450 ▲ ₹ 1,050	चांदी प्रति किलो ग्राम	₹ 2,71,000 ▲ ₹ 1,300	$ डालर	₹ 95.36 ▲ ₹ 0.17	क्रूड प्रति बैरल	$ 93.76

एक नजर में

आइटी शेयरों में खरीदारी से सेंसेक्स 382 अंक बढ़ा

नई दिल्ली : आइटी शेयरों की खरीदारी की बदौलत लगातार चार दिन से गिरावट का सामना कर रहा सेंसेक्स मंगलवार को 382.50 अंक बढ़कर 74,649.84 के स्तर पर बंद हुआ। दिनभर के कारोबार के दौरान इसमें 1,047.07 अंक का उतार-चढ़ाव रहा। इसी तरह, एनएसई का निफ्टी 100.95 अंक की तेजी के साथ 23,483.55 अंक पर जाकर बंद हुआ।

ओयो को सेबी से मिली आइपीओ लाने की मंजूरी

नई दिल्ली : ट्रेवल टेक्नोलाजी प्लेटफार्म ओयो की पैरेंट कंपनी प्रिज्म को कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर सेबी से आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) लाने की मंजूरी मिल गई है। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि कंपनी आइपीओ के जरिये 6,650 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। कंपनी के 7-8 अरब डालर के मूल्यांकन पर यह राशि जुटाई जा सकती है। (प्रेट्र)

केंद्र सरकार ने चांदी आयात पर और सख्ती बढ़ाई

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने चांदी आयात को लेकर मंगलवार को सख्ती और बढ़ा दी। अब केवल आरबीआइ द्वारा नामित एजेंसियां, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा अनुमोदित संस्थाएं और इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के माध्यम से योग्य जौहरी ही वैध प्रमाणन के जरिये चांदी का आयात कर सकेंगे। (प्रेट्र)

केंद्र ने बोर्ड आफ ट्रेड में 29 सदस्य नामित किए

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने बोर्ड आफ ट्रेड में 29 गैर-आधिकारिक सदस्यों को नामित किया है। इसमें एसबीआइ के चेयरमैन सीएस शेट्टी, एपल इंडिया के प्रबंध निदेशक विराट भाटिया और महिंद्रा के प्रबंध निदेशक अनीश शाह प्रमुख हैं। इस बोर्ड में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि तथा सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। (प्रेट्र)

रुपये की गिरावट थामने पर होगी बाजार की नजर

आरबीआइ की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज से, गवर्नर पांच जून को देंगे फैसलों की जानकारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : आरबीआइ गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक आज शुरू होगी। समिति के फैसलों की जानकारी पांच जून को दी जाएगी। इसमें विशेषज्ञों और बाजार की नजर ब्याज दरों (रेपो रेट) से ज्यादा रुपये की स्थिरता को लेकर केंद्रीय बैंक की भावी रणनीति पर होगी। आरबीआइ का अभी तक स्पष्ट रुख है कि वह रुपये को किसी खास स्तर पर रोकने का पक्षधर नहीं है, बल्कि केवल अत्यधिक अस्थिरता और भारी गिरावट को रोकने के लिए ही वह हस्तक्षेप करेगा। गवर्नर मल्होत्रा ने पहले कहा भी है कि किसी बैंड या स्तर को लक्षित करने के लिए उनकी नीति नहीं होगी।

समाचार एजेंसी प्रेट्र के एक सर्वेक्षण के मुताबिक, एमपीसी की आगामी बैठक में ब्याज दरों को प्रभावित करने वाले बेंचमार्क रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने की संभावना है। सर्वेक्षण में शामिल ज्यादातर अर्थशास्त्रियों और ट्रेजरी प्रमुखों का मानना है कि केंद्रीय बैंक वित्त वर्ष 2027 के अंत में महंगाई के बढ़ते जोखिम को देखते हुए बाद में सख्त नीति शुरू कर सकता है। एसबीआइ व कुछ अन्य आर्थिक एजेंसियों की रिपोर्ट भी यह बताती है कि चूंकि महंगाई की दर अभी आरबीआइ के लक्षित बैंड (चार प्रतिशत) के करीब है, इसलिए केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को लेकर अभी कोई फैसला नहीं करेगा।

जेपी मार्गन के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन हाल में रुपये की लगातार कमजोरी को देखते हुए आरबीआइ महंगाई नियंत्रण और रुपये की अस्थिरता को अलग-अलग नजरिए से देखेगा। यानी ब्याज दरों का इस्तेमाल आर्थिक विकास और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा और रुपये की स्थिरता को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार की बिक्री या कुछ दूसरी नीतियों का इस्तेमाल किया जाएगा।

बता दें कि पिछले कुछ दिनों में कई अर्थविदों ने तमाम आलेखों के जरिए कहा है कि रुपये की कमजोरी से महंगाई की स्थिति धीरे-धीरे ज्यादा खराब हो सकती है। लिहाजा ब्याज दरों को लेकर अभी से सोचने की जरूरत है।

एसबीआइ व क्रिसिल ने हाल ही में जारी अपनी रिपोर्टों मे यह बताया है कि किस तरह से रुपये की कमजोरी से भारत में इलेक्ट्रानिक्स, ईंधन, प्लास्टिक, दवाइयों के कच्चे माल आदि महंगे हो गए हैं जिसका असर धीरे-धीरे आम जनता की जेब पर पड़ेगा। असल में पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के बाद एशिया के अन्य प्रमुख देशों के मुकाबले डालर की तुलना में भारतीय रुपये की गिरावट ज्यादा तेज रही है।

वर्ष 2026 की शुरुआत से अब तक रुपये 7.5 प्रतिशत तक कमजोर हो चुका है। मई 2026 में एक समय रुपया 96-97 प्रति डालर के रिकार्ड निचले स्तर के करीब पहुंच चुका है। अभी यह 95 के आसपास है। रुपये को संभालने के लिए आरबीआइ ने सिर्फ मई माह में पांच अरब डालर-रुपया क्रय-बिक्री स्वैप जारी किया है। इसके तहत बैंक आरबीआइ को डालर देते हैं और फिर इसके बदले उन्हें रुपया दिया जाता है। इससे पहले मार्च 2026 में आरबीआइ ने 29.6 अरब डालर की बिक्री की थी। इस बिक्री से विदेशी मुद्रा भंडार मई के अंत में 681.4 अरब डालर रह गया है, जो एक साल का निचला स्तर है।

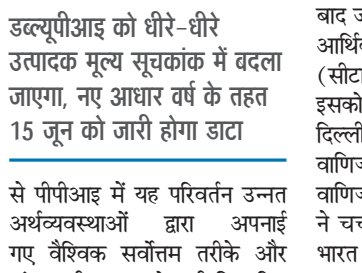

- विशेषज्ञों का अनुमान, अपरिवर्तित रखा जा सकता है रेपो रेट
- महंगाई को ध्यान में रखकर फैसले कर सकती है एमपीसी

7.5 प्रतिशत तक कमजोर हो चुकी है भारतीय मुद्रा वर्ष 2026 में अभी तक

96-97 प्रति डालर के करीब पहुंच चुका है रुपया मई की शुरुआत में

भारत में घरों और मंदिरों में बड़ी मात्रा में सोना रखा हुआ है। इसके बावजूद देश जरूरत का अधिकांश सोना विदेश से आयात करता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बढ़ते आयात बिल और विदेशी मुद्रा पर दबाव को देखते हुए नागरिकों से एक वर्ष तक सोने की गैर-जरूरी खरीद टालने की अपील की। ऐसे में कहा जा रहा है कि जब देश के पास पहले से ही हजारों टन सोना मौजूद है, तो इसको बाहर निकालकर अर्थव्यवस्था को मजबूत क्यों नहीं बनाया जा सकता। आइए जानते हैं भारत में मौजूद सोने की स्थिति और विशेषज्ञों की राय...

30-32 हजार टन सोना है भारतीय परिवारों और मंदिर ट्रस्टों के पास

35,000 टन तक हो सकती है परिवारों-मंदिर ट्रस्टों के सोने की मात्रा

3.8 ट्रिलियन डालर के करीब है देश में रखे सोने का अनुमानित मूल्य

72.4 अरब डालर रहा वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के सोने का आयात बिल

क्या है गोल्ड रिसाइक्लिंग

इसके तहत पुराने आभूषण, टूटे गहने, सिक्के, सोने की बिस्कुट, औद्योगिक स्क्रैप और इलेक्ट्रानिक उपकरणों से प्राप्त सोने को दोबारा शुद्ध कर उपयोग के योग्य बनाया जाता है। इसके तहत सबसे पहले सोने की शुद्धता जांची जाती है। फिर इसे पिघलाया जाता है। पिघलाए जाने के बाद इसे 99.9 प्रतिशत तक शुद्ध बनाया जाता है। इसके बाद नए आभूषण, सिक्के और अन्य सराफा उत्पाद बनाए जाते हैं।

सरकार क्यों दे रही रिसाइक्लिंग पर जोर

भारत अपनी सोना जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, जिस पर बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम से निष्क्रिय सोने को औपचारिक आर्थिकी में लाने का प्रयास कर रही है। इससे घरेलू संसाधनों का बेहतर उपयोग व आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सकता है।

सरकार को म्युचुअल फंड की गोल्ड योजनाओं में निवेश पर एक-दो वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाना चाहिए क्योंकि इनमें निवेश काफी बढ़ गया है और यह योजनाएं 100 प्रतिशत भौतिक सोने से समर्थित रहती हैं। इसके अलावा रिसाइक्लिंग पर सब्सिडी एवं रिसाइक्लिंग सर्टिफिकेट देकर सरकार नागरिकों को प्रोत्साहित कर सकती है। – **डीडी शर्मा**, प्रबंध निदेशक, एमएफ किंग

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि घरों और मंदिरों में मौजूद कुल सोने का केवल एक प्रतिशत हिस्सा भी हर वर्ष रिसाइक्लिंग के लिए लाया जाए तो भारत का सोना आयात 25 से 30 प्रतिशत तक कम हो सकता है। कुछ आकलनों में यह कमी 33 प्रतिशत तक बताई गई है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

जागरण रिसर्च

थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष बदलकर 2022-23 किया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वस्तुओं व अन्य सेवाओं के थोक मूल्य में होने वाली बढ़ोतरी के व्यापक एवं उचित मूल्यांकन के लिए अब थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) की जगह उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआइ) की शुरुआत की जा रही है। हालांकि, अभी अगले पांच साल तक डब्ल्यूपीआइ जारी किया जाएगा और उसके बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल डब्ल्यूपीआइ के आधार वर्ष में बदलाव करते हुए इसे 2011-12 की जगह 2022-23 कर दिया गया है। 15 जून को नए आधार वर्ष पर डब्ल्यूपीआइ जारी किया जाएगा। इसके साथ पहली बार पीपीआइ भी जारी होगा।

डब्ल्यूपीआइ के व्यापक उपयोग को देखते हुए संशोधित श्रृंखला के जारी होने की तारीख से पांच वर्षों तक पीपीआइ के साथ यह सूचकांक जारी किया जाएगा। उद्योग विभाग के मुताबिक डब्ल्यूपीआइ से पीपीआइ में यह परिवर्तन उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनाई गए वैश्विक सर्वोत्तम तरीके और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सिफारिश के अनुरूप है। इनपुट (कच्चे माल) और आउटपुट (अंतिम उत्पाद) दोनों पीपीआइ जारी किए जाएंगे। इससे यह पता लग सकेगा कि इनपुट के मूल्य में बढ़ोतरी का कैसे अंतिम उत्पाद के मूल्य बढ़ोतरी पर असर पड़ता है। नए आधार वर्ष में वस्तुओं की संख्या को 697 से बढ़ाकर 957 कर दिया गया है। बैंकिंग, प्रतिभूति लेनदेन, बीमा, पेंशन निधि प्रबंधन, रेलवे, हवाई यात्रा के पीपीआइ भी 15 जून को जारी किए जाएंगे।

डब्ल्यूपीआइ को धीरे-धीरे उत्पादक मूल्य सूचकांक में बदला जाएगा, नए आधार वर्ष के तहत 15 जून को जारी होगा डाटा

ब्रिटेन से व्यापार समझौते पर अमल जल्द

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : ओमान के साथ व्यापार समझौते पर अमल के बाद जल्द ही ब्रिटेन के साथ व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीटा) पर अमल हो सकता है। इसको लेकर मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिटेन के व्यापार व वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चर्चा की। सूत्रों का कहना है कि भारत ने स्टील को लेकर ब्रिटेन के रुख पर चिंता जाहिर की है।

वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि अगर ब्रिटेन भारतीय स्टील के निर्यात को लेकर अपने बाजार को पूरी तरह नहीं खोलता है और शुल्क में पूरी रियायत नहीं देता है तो भारत भी ब्रिटेन से आने वाली विभिन्न वस्तुओं के शुल्क में दी गई रियायत को कम कर सकता है। इसमें ब्रिटेन से आने वाली स्काच के अलावा अन्य वस्तुएं भी शामिल हो सकती है। ब्रिटेन भारत से स्टील आयात पर शुल्क में पूरी तरह से छूट नहीं देना चाहता है ताकि वह घरेलू उद्योग की रक्षा कर सके। वहीं भारतीय स्टील के आयात को लेकर कोटा भी निर्धारित किया जा रहा है।

सीटा के तहत भारत ने ब्रिटेन के स्काच पर लगने वाले शुल्क को 150 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत कर दिया है जो अगले दस साल में 40 प्रतिशत हो जाएगा। व्यापार समझौते पर वार्ता के दौरान ब्रिटेन ने भारतीय बाजार में स्काच बेचने के लिए शुल्क में कमी पर खासा जोर दिया था। दोनों देशों के बीच सीटा पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और अगले एक-दो महीनों में इस पर अमल शुरू हो सकता है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का आकार भारत से छोटा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय 40,000 डालर से अधिक होने की वजह से यहां के लोगों की क्रय शक्ति अधिक है। इसलिए सीटा पर अमल के बाद ब्रिटेन में भारत का निर्यात तेजी से बढ़ेगा।

- दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने समझौते के अमल को लेकर चर्चा की
- स्टील आयात को लेकर ब्रिटेन के सख्त रुख पर भारत ने चिंता जताई

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

राष्ट्रीय फलक

महाराष्ट्र सरकार ने नरीमन प्वाइंट स्थित एअर इंडिया भवन का किया अधिग्रहण

राज्य ब्यूरो, जागरण • मुंबई

यह इमारत देश की राष्ट्रीय विमानन महत्वाकांक्षाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिष्ठा का बनी प्रतीक

मुंबई के नरीमन प्वाइंट स्थित प्रतिष्ठित एअर इंडिया भवन अब औपचारिक रूप से महाराष्ट्र सरकार के स्वामित्व में आ गया है। यह अधिग्रहण इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मंत्रालय से चंद कदमों की दूरी पर स्थित यह इमारत देश की राष्ट्रीय विमानन महत्वाकांक्षाओं व सार्वजनिक उपक्रमों की प्रतिष्ठा का प्रतीक बनी रही।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को महाराष्ट्र लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के बीच "डीड आफ सरेंडर" पर हस्ताक्षर प्रक्रिया की अध्यक्षता की। करीब 1,601 करोड़ रुपये के इस सौदे को केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में मंजूरी दी थी, जबकि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने नवंबर 2025 में इसे अंतिम स्वीकृति प्रदान की थी। अरब सागर के किनारे स्थित प्रसिद्ध मरीन ड्राइव (क्वीन्स नेकलेस) के सामने खड़ी 23 मंजिला यह इमारत पिछले पांच दशकों से अधिक समय से मुंबई की पहचान का हिस्सा रही है। देश के पहले केंद्रीय व्यावसायिक जिले नरीमन प्वाइंट के हृदय स्थल में स्थित यह भवन कभी एअर इंडिया के मुख्यालय के रूप में जाना जाता था और नागरिक उड्डयन के स्वर्णिम दौर में प्रमुख विमानन कंपनी की प्रतिष्ठा का प्रतीक था। यह अधिग्रहण केवल एक रियल एस्टेट सौदा नहीं, बल्कि मुंबई के बदलते आर्थिक और संस्थागत परिदृश्य का भी द्योतक है। महाराष्ट्र सरकार इस भवन का उपयोग उन विभागों व कार्यालयों के लिए करेगी, जो वर्तमान में मुंबई के अलग-अलग हिस्सों में किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं। इससे न केवल किराये पर होने वाला नियमित खर्च कम होगा, बल्कि मंत्रालय और विधान भवन के निकट विभिन्न विभागों के एकत्र होने से प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी।

दो हजार करोड़ की धोखाधड़ी में अर्थ ग्रुप के चार निदेशक दोबारा किए गए गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

निवेशकों से धोखाधड़ी का आरोप, ईडी ने पांच दिन के रिमांड पर लिया

चारों निदेशकों को पहले दिल्ली पुलिस भी कर चुकी है गिरफ्तार

एनसीआर समेत लुधियाना और लखनऊ जैसे कई बड़े शहरों में हाउसिंग और कामर्शियल प्रोजेक्ट लांच कर 19,425 खरीदारों से 2004 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी के चार शीर्ष अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। ईडी के दिल्ली जोनल कार्यालय ने सोमवार को कंपनी के चार प्रमोटर्स व निदेशक अवधेश कुमार गोयल, रजनीश मित्तल, अतुल गुप्ता और विकास गुप्ता की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। इन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश कर गहन पूछताछ के लिए पांच दिन के रिमांड पर लिया गया है।

ईडी ने चारों को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज पांच एफआइआर के आधार पर शुरू हुआ है। जांच के बाद आर्थिक अपराध शाखा ने चारों को अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद इन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन अब ईडी ने इन्हें दोबारा गिरफ्तार किया है। यह मामला भले नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में चला गया हो लेकिन 18 महीने में खत्म होने वाली प्रक्रिया छह साल में भी खत्म नहीं हो पाई है। वर्षों से यह मामला अधर में लटका होने के कारण किसी को भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। खरीदार वर्षों से न्यायालयों के ही चक्कर काट रहे हैं। ईडी और ईओडब्ल्यू के अलावा गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआइओ) ने भी अर्थ ग्रुप के निदेशकों के खिलाफ कंपनी अधिनियम की धारा 447 के तहत एक आपराधिक शिकायत दर्ज की थी।

निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूबी : ईडी की जांच में सामने आया है कि अर्थ ग्रुप ने आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों की समय पर डिलीवरी और निश्चित रिटर्न का वादा करके 19,425 से अधिक खरीदारों और निवेशकों से लगभग 2004 करोड़ रुपये जुटाए थे।

अप्रैल में एनसीआर में मारे गए थे छापे

बीते अप्रैल में ईडी ने एनसीआर में अर्थ ग्रुप से जुड़े कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। उस कार्रवाई में 6.30 करोड़ रुपये कैश, 8.78 करोड़ रुपये के गहने और 100 से अधिक अचल संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए गए थे, जिनकी अनुमानित कीमत 100 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

हवा से मार करने वाली मिसाइल रुद्र एम-2 का सफल परीक्षण

जागरण संवाददाता, बालेश्वर

मिसाइल की रेंज लगभग 350 किमी, लक्ष्यों पर अत्यंत सटीकता के साथ किया प्रहार

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय वायु सेना ने मंगलवार को ओडिशा के चांदीपुर में हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्र एम-2 का सफल परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान प्रक्षेपित की गईं सभी मिसाइलों ने पूर्वनिर्धारित लक्ष्यों पर अत्यंत सटीकता के साथ प्रहार किया। परीक्षण रेंज में तैनात उन्नत ट्रैकिंग व रेंज उपकरणों से प्राप्त उड़ान आंकड़ों ने पुष्टि हुई कि परीक्षण के सभी निर्धारित उद्देश्य सफलतापूर्वक और पूर्ण रूप से हासिल कर लिए गए। इस मिसाइल की रेंज 350 किमी है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रुद्र एम-2 के सफल परीक्षणों के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायु सेना, रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों व उद्योग जगत के सभी सहयोगियों को बधाई दी। कहा कि इन परीक्षणों ने स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों की परिपक्वता, विश्वसनीयता व क्षमता को प्रदर्शित किया है। यह उपलब्धि उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगी व रक्षा तैयारियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भूमिका निभाएगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने परीक्षण से जुड़ी सभी वैज्ञानिक, तकनीकी व परिचालन टीमों को बधाई दी।

ओडिशा के चांदीपुर में रुद्र एम-2 मिसाइल के परीक्षण का दृश्य। स्रोत : डीआरडीओ

मृत मरीजों के नाम पर दवाइयां खरीदने में तीन बर्खास्त, एक निलंबित

जागरण संवाददाता, लखनऊ : किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) ने भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और मृत मरीजों के नाम पर दवाइयां खरीदने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। संस्थान प्रशासन ने यूरोलाजी विभाग में असाध्य रोग के इलाज व धांधली के मामले में तीन संविदा कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है, जबकि एक चीफ फार्मासिस्ट को निलंबित कर उनके और एक डाक्टर के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है।

डाक्टर को छोड़कर अन्य चारों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। सभी से रिकवरी भी की जाएगी। विभागाध्यक्ष अपुल गोयल को हटा दिया गया है। प्रो. गोयल की जगह जनरल सर्जरी विभाग के प्रो. एचएस पहवा को कार्यवाहक विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

10वीं फेल युवक ने ठग लिए यूपी-बिहार के पुलिस अफसर

जागरण संवाददाता, बागपत

पुलिसकर्मियों पर करता था रौब, आरोपित बिहार का मूल निवासी, दो अन्य साथियों की तलाश

लालमोहन राय

10वीं फेल एक युवक लाल मोहन राय ने यूपी व बिहार के 20 पुलिस अधिकारियों को आनलाइन ठगी कर चूना लगाया। बागपत में चौकी इंचार्ज से 25 हजार रुपये की ठगी करने के बाद आरोपित पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मूल रूप से बिहार का रहने वाला आरोपित वर्तमान में फरीदाबाद में रह रहा था। पुलिस उसके दो साथियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है।

बागपत चौकी इंचार्ज अमित कुमार से एसपी क्राइम बताकर अज्ञात व्यक्ति ने 25 हजार रुपये की आनलाइन ठगी की थी। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। साइबर थाने के इंस्पेक्टर संत शरण सिंह के मुताबिक विवेचना में बिहार के मोतिहारी के थाना लखौरा के गांव लक्ष्मीपुर कटहारिया के मूल निवासी लाल मोहन राय का नाम प्रकाश में आया। वह वर्तमान में परिवार के साथ फरीदाबाद रह रहा था। दिखाने के लिए वह प्राइवेट बस बुकिंग का काम करता था। पूछताछ में उसने बताया कि वह 10वीं फेल है। उसने अपने साथी अजय चौबे निवासी गोपालगंज, बिहार और विकास के साथ मिलकर बिहार के जमुई के सिमुलतला थाना प्रभारी रूबी कुमारी से 50 हजार ठगे। सिद्धार्थनगर के मोहाना चौकी इंचार्ज सुदीप कुमार यादव से 30 हजार रुपये की ठगी की।

इंडिगो 31 अगस्त से बंद कर देगी मैनचेस्टर के लिए उड़ानें

नई दिल्ली, प्रेट्र : इंडिगो ने बढ़ती परिचालन लागत और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण 31 अगस्त से मैनचेस्टर के लिए अपनी उड़ानें बंद करने की मंगलवार को घोषणा की। इस निर्णय के बाद, एयरलाइन कंपनी लीज पर लिए गए बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर विमान को नार्स अटलांटिक एयरवेज को वापस कर देगी। इस समय इंडिगो दिल्ली और मुंबई से मैनचेस्टर (ब्रिटेन) के लिए उड़ानें संचालित करती है।

एयरलाइन ने बयान में कहा, लगातार अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र संबंधी प्रतिबंधों के कारण उड़ान की अवधि में भारी वृद्धि और लागत संबंधी चुनौतियों के मद्देनजर इंडिगो को 31 अगस्त 2026 से मैनचेस्टर आने-जाने वाली अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ रही हैं। मैनचेस्टर के लिए सेवाएं पिछले साल जुलाई में शुरू की गई थीं।

18.96 करोड़ की जीएसटी चोरी में दिल्ली के दो जालसाज गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर

- बोगस फर्मों और जाली बिलिंग के जरिये लंबे समय से चल रहा जीएसटी चोरी का खेल
- वाट्सएप ग्रुप, फर्जी दस्तावेज और सर्कुलर ट्रेडिंग के जरिये चल रहा था संगठित नेटवर्क

फर्जी बिलिंग और बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) के जरिये 18.96 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के आरोप में पुलिस ने 50-50 हजार रुपये के दो इनामी जालसाजों को दिल्ली के हरिनगर क्लाक टावर से गिरफ्तार किया। आरोपितों में नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर-17 स्थित समृद्धि अपार्टमेंट निवासी सौरभ अग्रवाल उर्फ सन्नी तथा साउथ-वेस्ट दिल्ली के सागरपुर थाना क्षेत्र की कैलाशपुरी एक्सटेंशन, पालन कालोनी निवासी अजीत शामिल हैं।

पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने बताया कि राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त अरविंद कुमार ने तीन जुलाई 2025 को कोतवाली खलीलाबाद में तहरीर देकर बताया था कि यादव इंटरप्राइजेज नामक फर्म द्वारा बिना वास्तविक खरीद-बिक्री के केवल कागजों पर लेन-देन दर्शाकर भारी मात्रा में फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया।

जांच में मई 2025 के जीएसटी रिटर्न में करीब 18.96 करोड़ रुपये की बोगस आइटीसी दर्शाए जाने का मामला सामने आया था। आरोपितों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जाली आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल और अन्य कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अस्तित्वहीन फर्मों का पंजीकरण कराया। गिरोह के सदस्य वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज और डाटा साझा करते थे।

इन पैमानों पर होगा चयन

प्रथम पृष्ठ से आगे

- पांच लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों और राज्य की राजधानियों को 2025-26 के लिए अनुमानित जनसंख्या के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। 10 किमी के दायरे में स्थित दो या अधिक कस्बों के शहरी समूह, जिनकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के एक लाख से कम जनसंख्या वाले कस्बों-शहरी केंद्रों पर मामले-दर-मामले विचार किया जा सकता है।
- शहरों से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात जाम का आकलन करने के लिए एक अध्ययन किया जाएगा। यह आकलन शहर या कस्बे से गुजरते समय राजमार्ग पर यातायात की गति में गिरावट और शहर या कस्बे के बाहर स्थित राजमार्ग के खंडों पर यातायात की गति में गिरावट के आधार पर किया जाएगा।

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

पश्चिम बंगाल आगीतून फुफाट्यात?

‘प. बंगालमध्ये भाजपदेखील डावे, तृणमूलच्या वाटेने?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२ जून) वाचला. पश्चिम बंगाल आणि हिंसा हे समीकरण नवीन नाही. त्यामुळेच काँग्रेससारखा मध्यममार्गी पक्ष प्रवाहाबाहेर फेकला गेला. ‘गारुड्याचा मृत्यू त्याच्याच पेटाऱ्यातील सापा’मुळे होतो, ही म्हण पश्चिम बंगालला तंतोतंत लागू पडते. साम्यवाद्यांचे सरकार असताना कारखानदारीला, उद्योगांना युनियन्सच्या माध्यमातून त्रास दिला जात होता. हिंसक कारवाईत सामील संघटना इथेच जन्माला आल्या. सिंगूर येथे टाटा प्रकल्प उभा राहत असताना तृणमूलने त्याला विरोध करून प्रकल्प बाहेर हलविण्यास बाध्य केले तेव्हाही हिंसाचार झालाच होता. एकूणच बंगालमध्ये राज्य मिळविण्याची पहिली अट हिंसाचार आहे, हे लक्षात येते.

तृणमूलच्या कार्यकाळात ममता बॅनर्जी यांच्या कार्याचे कितीही उदात्तीकरण करण्यात येत असले तरी त्यांच्या आक्रस्ताळेपणाचा अनुभव भाजपच्या आधीच्या नेतृत्वाने घेतला होता. तृणमूलच्या काळात कार्यकर्त्यांवर वचक ठेवण्याची काळजी घेण्यात आली नसल्याने कार्यकर्ते स्वैर सुटले आणि त्यांनी सरकार पाठीशी असल्याच्या धुंदीत विरोधी मतांच्या नागरिकांना वेठीस धरण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे तटस्थ आणि समंजस मतदारसुद्धा सतर्क झाला आणि हा सत्तेचा उन्माद आपल्यालाही त्रासदायक ठरेल, असा विचार करून भाजपच्या पाठीशी उभा ठाकला. त्याला विविध यंत्रणांची मिळालेली जोडही महत्त्वाची ठरली. कदाचित देशातील ही अशी एकमेव निवडणूक असावी ज्यात अभूतपूर्व अशी सुरक्षा यंत्रणा तैनात केली गेली होती. आज दिसणारे हिंसेचे चित्र सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या मनातील खदखद आणि सत्तेच्या आशीर्वादातून निर्माण होत आहे. लोकांची स्थिती आगीतून फुफाट्यात अशी झाली तर ही भावना पुढच्या निवडणुकांत निर्णायक ठरू शकते. त्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी समन्वय ठेवून या अन्यायाविरुद्ध लढा देणे काळाची गरज आहे.

■ **अनिरुद्ध कांबळे,** राजर्षीनगर (नागपूर)

भाजप पूर्वसुरींपेक्षा कमी नाही

‘प. बंगालमध्ये भाजपदेखील डावे, तृणमूलच्या वाटेने?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२ जून) वाचला. तसे पाहू जाता देशभरात भारतीय जनता पक्ष, मग तो नवनवीन रस्ते, पूल यांच्या कंत्राटांच्या निविदांतील टक्केवारी असो वा देशातील किंवा एखाद्या राज्यातील ढिसाळ कायदा सुव्यवस्थेचा मुद्दा असो तो पक्ष, आपल्या पूर्वसुरींपेक्षा (आधीचे राज्यकर्ते) कोठेही मागे पडल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये सिद्धार्थ शंकर रेंच्या करकीर्दीपासून असणारी हाणामारीची परंपरा तो पक्ष मोडणे अशक्यच. ‘अमृतकाळा’त राज्यात केवळ सत्ता मिळवायची नसते, तर प्रस्थापित पक्षाचे अस्तित्वच पुसायचे असते आणि या कामास त्याच पक्षातून आणलेल्यांपेक्षा योग्य व्यक्ती मिळणे कठीण. आसाम, महाराष्ट्र यांची उदाहरणे याबाबत देता येईल. तात्पर्य : पश्चिम बंगालबाबत फारशा अपेक्षा बाळगण्यात अर्थ नाही. तेथील व्यवस्थादेखील उत्तर प्रदेश, बिहारप्रमाणे आधी होती तशीच पुढे सुरू राहणार, असे आज तरी वाटते.

■ **शैलेश पुरोहित,** मुंबई

पत्रकार परिषद न घेणे भूषणावह?

‘अग्निपथावरील देशसेवेचे एक तप’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेख (२ जून) वाचला. एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान मोदी पत्रकार परिषदांमध्ये वेळ घालवत नाहीत, असे अभिमानाने सांगितले आहे. खुली पत्रकार परिषद हे लोकशाही जिवंत असल्याचे प्रतीक असते. हेच प्रतीक आता लोप पावल्याचे शिंदेंनी कबूल केले आहे.

‘२०१४ नंतरचा भारत’ आणि ‘आधीचा भारत’ असे जगातील लोक म्हणतात, हा लेखातील मुद्दा बरोबरच आहे. आधीचा भारत कसाही का असेना, पण तिथे आपली मते मांडण्याची, बोलण्याची मुभा होती. २०१४ नंतर ती मुभा कायम आहे का, असा प्रश्न पडतो. ‘घर मे घुसकर...’ वगैरे वल्गना केल्या जातात त्या वेळी सत्तरीच्या दशकात झालेले पाकिस्तानचे तुकडे सहजरीत्या विसरले जावेत असा डाव असतो. ‘त्या’ भारताचा आणि तुमचा संबंध नाही असे मनात ठसवण्याचा हा भाग आहे. आपली उपयुक्तता दाखवून देण्यासाठी, नजरेत भरण्यासाठी असे लेख लिहिणे ही काळाची गरज झालेली दिसते, इतकाच याचा अर्थ.

■ **विक्रम अवसरीकर,** पुणे

राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी स्तुती!

‘अग्निपथावरील देशसेवेचे एक तप’ हा लेख वाचला (२ जून). उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेले मोदींचे बेसुमार कौतुक वाचताना ‘अच्छे दिन आलेच नाहीत’ हा लेख (लोकसत्ता- ३१ मे) आठवत होता. लेखात शिंदे यांनी मोदींचे गुजरात मॉडेल, नमामी गंगे प्रकल्प, लाडकी बहीण योजना या आणि अशा अनेक गोष्टींचे तोंडभर कौतुक केले आहे, पण हे कौतुक आपला राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी केले आहे, असे वाटते. शिंदे यांच्या दिल्लीवाऱ्यांतूनही हेच स्पष्ट होते.

■ **दिनेश पांथरे,** धाराशिव

जातीयता संपली की आरक्षणही संपेल

‘आरक्षण हळूहळू बंद करण्याचा विचार?’ (लोकसत्ता- २ जून) हा लेख वाचला. अलीकडे सरकारला संविधान व सांविधानिक मूल्यांचा विसर पडल्याचे दिसते. ‘नाही रे’ वर्गाकडे डोळेझाक केली जात आहे. आरक्षण पूर्णपणे संपविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुळातच नोकऱ्या नाहीत. अनेक सरकारी विभागांत वर्षोनुवर्षे हंगामी, कंत्राटी कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत. अनुसूचित जाती-जमातींना असलेल्या आरक्षणाची अंमलबजावणी कधी झालीच नाही. आरक्षणाबद्दल अनेक गैरसमज आहेत.

आरक्षण केवळ एका जातीने घेतले आहे, त्यामुळे त्यांना आरक्षणाची आवश्यकता उरलेली नाही, असा समज पसरवला जात आहे. परिणामी अनुसूचित जाती-जमातींचा नेहमी द्वेष करण्यात येतो. परंतु कित्येक कुटुंबांत एकही सदस्य नोकरीला नाही. पराकोटीची बेरोजगारी आहे. आरक्षण कधी नष्ट होणार, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. मात्र जातीयतेचा अंत कधी होणार, असा प्रश्न कोणी विचारत नाही. जातीयता संपली तर आरक्षणाची गरज राहणार नाही याकडे सोयीने दुर्लक्ष केले जाते. आरक्षणामुळे विषमता वाढते, असा एक आक्षेप असतो. परंतु आरक्षणाचा लाभ देऊन सन्मानाने जीवन जगण्याची संधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे विषमता कशी वाढू शकते? कोणत्याही पदावरील नियुक्ती गुणवत्तेशिवाय केलीच जात नाही. त्यासाठी विविध स्पर्धा परीक्षा द्याव्याच लागतात. उलट अशा परीक्षांत अनेकांना केवळ जातीद्वेषामुळे डावलण्यात आल्याचा अनुभव येतो. आरक्षण समाप्त करायचे असेल तर ‘नाही रे’ वर्गाची उन्नती झाली आहे का याची तपासणी केली पाहिजे. हजारो वर्षांपासून असलेला भेद नष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू होऊन जेमतेम ७० वर्षे झाली आहेत, याचाही विचार झाला पाहिजे.

■ **श्रीराम बनसोड,** नागपूर

महाराष्ट्र गायपट्ट्याला जोडण्याची योजना?

‘हिंदीविरोधाने सत्ता मिळेल, पण ज्ञान खुंटेल’ हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे वक्तव्य (लोकसत्ता- २ जून) वाचले. आपला मूळ धूर्त हेतू आदर्शवादाच्या मागे लपवून कसा ठेवावा, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. वास्तविक पहिलीपासून हिंदी सक्ती करण्यामागे ज्ञानवृद्धीची आस आहे की मुंबईत व महाराष्ट्रातील अन्य शहरांत आता लक्षणीय संख्येने असलेल्या हिंदी भाषकांच्या मतांची बेगमी करायची आहे? महाराष्ट्र उत्तरेतल्या गायपट्ट्याला जोडून हिंदुत्ववादी मतांचे विस्तारीकरण व मजबुतीकरण करायचे आहे का?

विरोधक करतात ते सत्ताकारण व आपण करतो ती राष्ट्रसेवा, समाजसेवा या भाजपच्या खाक्याला सुसंगत असेच मुख्यमंत्र्यांचे ताजे वक्तव्य आहे. भाषा म्हणून हिंदीला कुणाचाही विरोध नाही. विरोध आहे तो मराठी भाषक विद्यार्थ्यांवर त्यांच्या कोवळ्या वयात आणखी एका भाषेची सक्ती करण्याला. कोवळ्या वयात अतिरिक्त भाषेची सक्ती करणे नुकसानकारक कसे आहे, याविषयी तज्ज्ञांची मतेही प्रसिद्ध झाली आहेत. पण त्यांच्या वस्तुनिष्ठ मतांचे, आक्षेपांचे तितकेच सप्रमाण व तर्कसंगत निरसन न करताच हिंदी भाषा सक्ती कशी योग्य आहे हेच पालुपद मुख्यमंत्री जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा लावत असतात. खऱ्या मुद्द्यांना व प्रश्नांना स्पर्शही न करता मुख्यमंत्री केवळ आदर्शवाद घोकत आहेत.

■ **अनिल मुसळे,** ठाणे

पहिल्या ‘बंदसम्राटा’चं स्मरण...

जॉर्ज फर्नांडिस हयात असते, तर आज (३ जून) त्यांनी वयाची ९५ वर्षं पूर्ण केली असती! या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या बेधडक नेतृत्वशैलीबद्दल आत्मीयतेने लिहिलेलं हे टिपण; त्यावेळच्या राजकारण व समाजकारणातील मोकळेपणाचीही जाणीव करून देणारं...

मिलिंद कोकजे
kokjemilind@gmail.com

जॉर्ज फर्नांडिस या बेफाम व्यक्तिमत्त्वाची (एकतर्फी) ओळख झाली पत्रकारितेत येण्यापूर्वी खूप खूप आधी, शाळेत साधारण तिसरी-चौथीत असताना. मुलुंड उपनगरात तेव्हा वसंत व्याख्यानमाला व्हायची आणि त्या व्याख्यानांना जायचं हा घरचा प्रघात होता. १९६७च्या निवडणुकीत स. का. पाटलांसारख्या (‘अनक्राऊन्ड किंग ऑफ मुंबई’ म्हणून प्रसिद्ध) काँग्रेस नेत्याचा दक्षिण मुंबईत पराभव करून ‘जायंट किलर’चं लेबल मिरवत मुंबईतल्या अनेक प्रकारच्या कामगारांचा नेता जॉर्ज लोकसभेत निवडून आला होता. त्यामुळे वसंत व्याख्यानमालेच्या चोखंदळ आयोजकांनी त्याचं भाषण ठेवलं होतं.

जॉर्ज (वयाने, पदाने कितीही मोठी असला तरी आमच्या पिढीकरता जॉर्ज हा जॉर्जच, मि. फर्नांडिस वगैरे नाही.) आपली पत्नी लैला यांच्याबरोबर आला. आम्ही मुलं पुढे बसलो होतो. लैला नेमक्या माझ्या शेजारीच येऊन बसल्या. जॉर्जचं भाषण सुरू झालं आणि त्यानं काय गारुड केलं ते कळलचं नाही. पण भाषण संपलं तेव्हा ग्रेट माणूस आज आपण ऐकला हीच भावना मनात होती. त्या भाषणातला अजूनही आठवणारा तपशील म्हणजे त्यानं तोंडी गणित करून लोकसभेत प्रत्येक खासदाराला बोलायला सरासरी किती वेळ मिळतो ते मांडलं होतं.

खरं तर घरचं राजकीय वातावरण समाजवाद्यांच्या बाजूचं नाही. त्यामुळे जॉर्ज अगदी शत्रू नसला तरी फार प्रियही नाही. पण वातावरण काँग्रेसधार्जिणं असल्यानं घरात राजकीय मोकळेपणा होता. काँग्रेसविराधी जॉर्जला नेता मानायला वडलांचा विरोध नव्हता. त्यामुळे त्यानंतरही जॉर्ज भेटत राहिला तो बंदच्या रूपानं. मुंबईतला तो पहिला बंदसम्राट. त्याने पुकारलेला बंद म्हणजे जणू काही तो आमचाच बंद इतका जॉर्ज डोक्यात फिट बसला होता.

प्रत्यक्षात नाही तरी तो वर्तमानपत्रांतल्या बातम्यांमधून, फोटोंमधून भेटतच राहिला, कधी भाषण करताना, कधी अटक करवून घेताना, कधी गाडीपुढे आडवा पडून ‘रेल रोको’ करताना. वर्तमानपत्रातला त्याचा रुळावर आडवं पडून रेल्वे गाडी अडवल्याचा आणि त्याला उठवण्याकरता पोलिसांनी लाठ्यांनी जोरदार मारहाण केल्याचा फोटो गाजला होता. त्या प्रसंगाची खूप चर्चा त्या वेळी होती. त्या प्रसंगाने त्याची लोकप्रियता वाढली.

कॉलेजला गेल्यावर तो अरुण साधूंच्या ‘मुंबई दिनांक’ कादंबरीत ‘युनियन लीडर डी कास्टा’च्या रूपात तो भेटला. प्रत्यक्ष उद्योगमंत्र्याची मुलगी ज्याच्या प्रेमात आहे आणि स्मगलिंगविरोधात जोरदार मोहीम उघडउघड बिनधास्तपणे जो चालवतो अशा डी कास्टावरचं कादंबरीतलं प्रकरण परत परत वाचायला मजा यायची. वृत्तपत्रविद्येचं शिक्षण घेताना दिल्ली ट्रिपच्या वेळी लोकसभा दाखवायला नेलं तेव्हा शून्य प्रहरात जॉर्ज जोरजोरात कोणता तरी मुद्दा मांडताना दिसला. पण प्रत्यक्ष भेट मात्र झाली नाही.

१९८१ साली पत्रकारितेत- ‘फ्री प्रेस’मध्ये आलो आणि एक दिवस जॉर्जच्या प्रत्यक्ष भेटीचं स्वप्न पूर्ण झालं. दत्ता सामंतांचा जगप्रसिद्ध गिरणी संप सुरू झाला होता. जॉर्ज कोणत्या तरी मोर्चाकरिता आझाद मैदानावर आला होता. मी पुढे होऊन ओळख करून दिली आणि सहज गिरणी संपाबद्दल विचारलं. तर त्यानं थेट हेडलाइनच दिली. गरज पडली तर सामंतांना पाठिंबा द्यायला महानगरपालिकेचा आणि टॅक्सीवाल्यांचा संप घडवून आणेन. ‘फ्री प्रेस’ बुलेटीननंही दुसऱ्या दिवशी ‘जॉर्ज, सामंत ॲक्सिस टू क्रिपल दी सिटी’ अशी जोरदार हेडलाइन देऊन ती छापली. आणि तेव्हापासून मग जॉर्ज प्रत्यक्षच भेटू लागला. प्रत्येक वेळी त्याची काही तरी जोरदार घोषणाच असायची. ही त्याची खासियत होती. तो दणकून बोलायचा, सडकून टीका करायचा, पण कधीच मी असं बोललो नव्हतो वगैरे म्हणायची पाळी त्याच्यावर त्यानं येऊ दिली नाही. पत्रकारांशी संबंध इतके चांगले की एखाद्या सभेच्या आधी जाऊन त्याला सांगितलं की डेडलाइन आहे, तर चक्क सभेत आपण काय बोलणार आहोत, हे आधीच सांगायचा.

पुढे चांगली ओळख झाली. तोही नावाने ओळखू लागला. त्याचे मुंबईतले सहकारी रणजित भानू यांच्या घरी किंवा अरुण नाईक यांच्या वडाळ्याच्या प्रेसमध्ये भेटी होत. नाही तर पत्रकार परिषदा, जाहीर सभा असायच्याच. त्याच्या दिल्लीच्या बंगल्यातही भेटी झाल्या. एकदा पीटीआयकरता त्याची मुलाखत हवी होती. त्याने मोठा बंद पुकारला होता. त्याच्या आदल्या दिवशी तो मुंबईत येणार होता. त्याने नेपियन सी रोडवरच्या भानूंच्या घरी जेवायला बोलावले. जेवणापूर्वी भानूंच्या गॅलरीत बसून मुलाखत दिली. गॅलरीतून खाली कुठली तरी एक झोपडपट्टी दिसत होती. तो म्हणाला, खरी मुंबई या इमारतीत, फ्लॅटमध्ये राहत नाही, त्या झोपडपट्टीत राहते. त्याच मुलाखतीत त्यानं सणसणीत बातमी दिली की, उद्याच्या बंदमध्ये रेल्वे सुरू राहिली तर तो दादरला रेल्वेसमोर आडवा पडून सत्याग्रह करणार.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी दिनू रणदिवे, जगन फडणीस, प्रकाश अकोलकर (हेही सगळे जॉर्ज फॅनच) अशा ज्येष्ठांसह अनेक वार्ताहर दादर स्टेशनवर हजर होते. पोलिसांचा प्रचंड बंदोबस्त होता. इतक्या बंदोबस्तात जॉर्ज बाहेरून येणार कुठून. तो रुळापर्यंत पोहोचायच्या आतच पोलीस पकडतील अशी खात्री होती. इतक्यात त्याच्या सहकाऱ्याने निवडक पत्रकारांना हळूच सांगितले की अमुक अमुक प्लॅटफार्मवर जा. सर्व जण त्या प्लॅटफॉर्मवर एकदम पुढे जाऊन उभे राहिले. उत्तरेकडे बाहेरगावी जाणारी एक गाडी नऊच्या सुमारास आली. त्याच्या एका डब्याच्या संडासातून एकदम जॉर्ज बाहेर आला, पटकन दरवाजा उघडून प्लॅटफॉर्मच्या विरुद्ध बाजूला गाडी आणि रेलिंगच्या फटीतून खाली उतरून पोलिसांच्या लक्षात यायच्या आत धावत जाऊन इंजिनापुढे आडवा पडला. परत एकदा तो जुनाच सीन. पोलीस धावले, त्यांनी प्लॅटफॉर्मवरून रुळावर खाली उड्या मारल्या आणि त्याला उचलून बाजूला करायला लागले. त्यात त्याचे कपडे फाटले. जे पूर्वी केवळ फोटोत पाहिलं होतं ते दृश्य प्रत्यक्ष पाहायला मिळालं.

नंतर एकदा तो नाशिकला जाणार होता. एक दिवस आधी मला विचारलं, येतोस का. दुसऱ्या दिवशी भानूंच्या गाडीतून पुढे मी आणि ड्रायव्हर, मागे जॉर्ज आणि नितीश कुमार असे नाशिकला गेलो आणि दुसऱ्या दिवशी परतलो. तिथल्या सभेत त्याने जैन हवाला डायरीतल्या मजकुरासंबंधीचा आरोप केला. शंकरराव चव्हाण गृहमंत्री असताना दिल्लीत ते बंगल्याबाहेर पडण्यापूर्वी सुरक्षा व्यवस्था आजूबाजूच्या सर्व बंगल्यांचं फाटक लावून घेऊन कोणालाही बाहेर पडण्यास बंदी करत असे. त्यात जॉर्जचा ३, कृष्ण मेनन मार्ग हा बंगलाही होता. सुरक्षा व्यवस्थेच्या या जाचाला कंटाळून जॉर्जने एक दिवस त्याच्या बंगल्याचं फाटकच उखडून टाकलं आणि ते परत लावूच दिलं नाही. एक प्रकारे सुरक्षा व्यवस्थेला आव्हानच दिलं की आता फाटक बंद करून मला बाहेर पडण्यापासून कसे रोखता ते दाखवा. रेल्वेमंत्री असताना रोह्याला अडकलेली कोकण रेल्वे त्याने श्रीधरन यांच्या मदतीने वेगाने पुढे कर्नाटक आणि केरळला नेली. संरक्षणमंत्री असताना सियाचीनच्या दुर्गम भागात सैनिकांना संपर्काकरता सॅटेलाइट फोन देण्याच्या प्रस्तावावर याची गरज काय असा शेरा मारणाऱ्या दिल्लीतल्या कोणा उपसचिवाची खरंच गरज काय हे शोधण्याकरता त्याने थेट सियाचीनलाच बदली केल्याची एक कथा दिल्लीत कानावर आली.

जॉर्जच्या जोरदार वक्तृत्वामुळे अगदी लहानपणापासून त्याचा फॅन झालो. पुढे अनेक सभांत त्याचं ते जोरदार वक्तृत्व परत परत ऐकलं.

पण नंतर दोन प्रसंगांत मात्र त्याच्या बोलण्यात एकदम एक विषाद जाणवला. कांडल्याला कारगिल कंपनीला मिठाच्या प्रकल्पाकरता दिलेल्या जमिनीविरुद्ध त्यानं सत्याग्रह संघटित केला होता. रोज (ठिकठिकाणाहून आलेले) काही सत्याग्रही मोर्चा काढून स्वतःला अटक करून घेत होते. तो सत्याग्रह बघायला मुंबईहून काही पत्रकारांना नेण्यात आलं होतं. नेमका जॉर्जही त्या दिवशी कांडल्यात होता. जॉर्ज या सर्व प्रश्नाकडे सुरक्षा, बहुराष्ट्रीय कंपनीचा मिठासारख्या साध्या उत्पादनाच्या क्षेत्रात प्रवेश वगैरे व्यापक दृष्टिकोनातून बघत होता. स्थानिक छोट्या मिठागरांचा प्रश्नही त्यात होता. पण स्थानिक लोकांशी बोलल्यावर लक्षात आलं की, त्यांना बाकी कशाचं काही पडलेलं नव्हतं. त्यांना फक्त त्यांच्या मिठागरांना स्पर्धा नको होती. कारगिल दुसरीकडे कुठे गेले तर त्यांचा काही विरोध नव्हता. त्याला अनुषंगून जॉर्जला विचारलं की तुम्ही जे व्यापक मुद्दे मांडता आहात त्या संदर्भात लोकांचं प्रबोधन करण्यात कमी पडलात असं वाटत नाही का. अत्यंत विषादपूर्ण स्वरात जॉर्ज म्हणाला, लोकांचं सोड, आम्ही आमच्या कार्यकर्त्यांचं शिक्षण नीट करू शकलो नाही.

त्यानंतर काही वर्षांनी एका रविवारी दुपारी मुंबईत त्याने अचानक गिरगावातल्या म्युनिसिपल मजदूर युनियनच्या ऑफिसमध्ये पत्रकार परिषद बोलावली होती. रविवार असल्याने आणि अचानक निमंत्रण आल्याने फार पत्रकार नव्हते, अगदी दोन-चारच होते. त्यात एका वृत्तसंस्थेची एक अगदी नवखी वार्ताहर होती. परिषद संपल्यावर चहा पिताना तिची अगदी उस्फूर्त प्रतिक्रिया आली, ही कोणती जागा, इथे कुठे पत्रकार परिषद बोलावली. तिचं बोलणं जॉर्जने ऐकलं आणि तो एकदम म्हणाला, ‘ही कोणती जागा? तुला माहीत नाही, पण एके काळी मुंबई दोनच ठिकाणांहून चालवली जायची. एक महापालिका आयुक्तांचं ऑफिस आणि दुसरं हे युनियनचं ऑफिस. त्याला त्याचा मुंबईतला सुवर्णकाळ बहुधा आठवत असावा. पण या ऑफिसचं ते पूर्वीचं महत्त्व आता पत्रकारांना राहिलेलं नाही, या जाणिवेतून आलेला त्याच्या बोलण्यातला विषाद लपला नाही. जॉर्ज नंतर परत मंत्री वगैरे झाला पण त्याच्यातल्या तडफदार नेत्याचा उत्तरार्ध सुरू झाल्याचं मात्र त्या वेळी जाणवलं होतं.

मुंबईतला जॉर्जचा सुवर्णकाळ जरी त्याच्या हातातून नंतर काहीसा निसटला तरी कामगार विश्वात, विशेषतः महानगरपालिका, बेस्ट कामगार, टॅक्सी चालक आणि राजकारणातही त्यानं केलेल्या कामाची नोंद घेऊन एका महत्त्वाच्या चौकाला त्याचं नाव देऊन त्याच्या मुंबईशी असलेल्या नात्याची स्मृती जपली जात आहे, हे महत्त्वाचं.

कुतूहल

हवेचा दाब म्हणजे काय?

हवा दिसत नसली तरी तिला वजन असतं. वातावरणातल्या हवेच्या वजनाने पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर पडणारा जोर म्हणजेच हवेचा दाब. समुद्रसपाटीपासूनची उंची, तापमान आणि आर्द्रता यांचा परिणाम हवेच्या दाबावर होत असतो.

गुरुत्वाकर्षणामुळे हवेतल्या वायूंचे रेणू, धूलिकण आणि बाष्प, पृथ्वीच्या पृष्ठभागाकडे खेचले जातात आणि त्यांचं प्रमाण जमिनीलगत वाढल्यानं तिथल्या हवेची घनता जास्त होते. परिणामी हवेचा दाब सर्वाधिक राहतो. जसजसे उंच जाऊ, तसा गुरुत्वाकर्षणाचा प्रभाव कमी झाल्याने हवेची घनता कमी होते, ती विरळ होते आणि तिचा दाब कमी होत जातो. सूर्यापासून पृथ्वीला मिळणारी उष्णता सर्व ठिकाणी सारखी नसते. विषुववृत्तावर सर्वात जास्त तर विषुववृत्तापासून जसजसे उत्तर ध्रुवाकडे व दक्षिण ध्रुवाकडे जाऊ तशी ती कमी होते. त्यामुळे पृथ्वीवर तापमानाचे पट्टे निर्माण होतात आणि या तापमानाच्या पट्ट्यांनुसार हवेच्या दाबाच्या पट्ट्यांची निर्मिती होते. तापमानाचा परिणाम हवेच्या घनतेवर होतो आणि पर्यायाने हवेच्या दाबावरही होतो. उबदार हवा प्रसरण पावल्याने तिची घनता कमी होते आणि त्यामुळे तिचा दाब कमी होतो. त्याउलट थंड हवा आकुंचन पावल्याने तिची घनता वाढून दाब वाढतो. हवेतली आर्द्रता म्हणजेच पाण्याची वाफ ही कोरड्या हवेपेक्षा हलकी असते. कोरड्या हवेत जड वायू जास्त असल्याने ती जड असते आणि दाब जास्त असतो. हवेतल्या वाढलेल्या आर्द्रतेमुळे हवेची घनता कमी होते आणि हवेचा दाब कमी होतो.

हवेचा दाब मोजण्यासाठी वायुभारमापक म्हणजेच ‘बॅरोमीटर’ हे यंत्र वापरलं जातं. मिलिबार म्हणजे एमबी किंवा हेक्टोपास्कल म्हणजे एचपीटी हे त्याचं एकक आहे. हवेचा दाब समुद्रसपाटीवर सुमारे १०१३ मिलिबार असतो. वातावरणातील तपांबरामध्ये दर आठ मीटर उंचीला अंदाजे एक मिलिबार दाब कमी होतो.

समुद्रसपाटीपासूनच्या उंचीप्रमाणे सूर्याच्या उष्णतेमध्ये फरक पडतो. त्यामुळे हवेच्या दाबातही फरक निर्माण होतो. जास्त दाबाकडून कमी दाबाकडे हवा वाहते. पृथ्वीच्या स्वतःभोवती फिरण्याने आणि हवा उच्च दाबाकडून कमी दाबाकडे वाहात असल्याने तिला गती मिळून वारे तयार होतात. वायूचे वस्तुमान, पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे असमान तापमान आणि वारे या सर्वांचा हवेच्या दाबावर परिणाम होतो.

हवेचा उच्चदाब साधारणपणे स्वच्छ, निरभ्र आकाश आणि शांत हवामान दर्शवतो. याउलट हवेचा कमी दाब वादळी वारे, ढगाळ वातावरण व पाऊस निर्माण करतो. कमी दाबाच्या ठिकाणी हवा गरम होऊन वर जाते. त्यामुळे ती थंड होऊन ढगांची निर्मिती होते आणि पाऊस पडतो.

– **अनघा शिराळकर**
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

व्यक्तिवेध

झटपट लोखंडी पूल उभारणे किंवा दुर्गम रस्ते बांधणे ही महत्त्वाची कामे लष्करी अभियंते करतातच; पण विजेची गरज कमी असलेली किंवा कमी वेळात काम करणारी उपकरणे घडवणे, इंधन वाचवण्याचे उपाय शोधणे, कमी वजनाची- वाहून नेण्यास हलकी पण भक्कम साधने तयार करणे... असा लष्करी अभियांत्रिकीचा पसारा आहे. तो आणखी वाढवून, पर्यावरणाची कमीत कमी हानी होईल याचीही काळजी घेण्याचे व्यवधान लष्करी अभियांत्रिकी विभागाचे माजी प्रमुख (इंजिनीअर-इन-चीफ) लेफ्टनंट जनरल बी. एस. धालीवाल यांनी रुळवले. या लष्करी उच्च पदावर मे २००६ मध्ये त्यांची नियुक्ती झाली आणि ऑगस्ट २००७ मध्ये ते निवृत्त झाले. यानंतर, पंजाबचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांनी त्यांना ‘मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख तांत्रिक सल्लागार’ या पदावर नेमले आणि पुढे मुख्यमंत्री बदलले तरी, २०१८ पर्यंत ते या सल्लागारपदी कायम राहिले. या लष्करी आणि नागरी क्षेत्रांतीलही कामगिरीसाठी त्यांना पुरस्कार मिळाले; तसेच ‘बदल व्यवस्थापना’च्या क्षेत्रात त्यांचा अधिकार सर्वमान्य झाला. अशा कृतार्थ आयुष्याची अखेर अवघ्या ७८ व्या वर्षी, ३० मे रोजी झाली.

ले. जन. बी. एस. धालीवाल

लेफ्ट. जन. धालीवाल हे पुण्याच्या राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे (एनडीए) स्नातक. इथून ते आधी ‘बेंगॉल सॅपर्स’मध्ये गेले, मग लष्करी अभियांत्रिकी सेवेच्या अनेक तुकड्यांमध्ये अधिकारपदी राहून, पुढे ‘बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन’ या दुर्गम रस्ते व आनुषंगिक पायाभूत सोयी उभारण्याच्या विभागातही त्यांना वरिष्ठ पदे मिळाली. ‘त्यांच्या दीर्घ कारकीर्दीत त्यांना मिळालेली काही पदे विशेष प्रतिष्ठेची मानली जात नसूनही, त्यांच्या नेतृत्वामुळे त्यांची तिथली कारकीर्दही झळाळली’ असा अभिप्राय त्यांच्या काही परिचितांनी नोंदवला आहे. या अभिप्रायांचे कारण ठरले ते ‘द जनरल कॉल्ड त्सुनामी’ हे त्यांचे ४०० हून अधिक पानी आत्मचरित्र! या पुस्तकात लष्करी विनोदाची पखरण आहे, पण हेवेदावे किंवा विषाद यांचा मागमूसही नाही. तांत्रिक सुधारणांची संधी हुडकणे आणि ती सुधारणा प्रत्यक्ष करणे हा प्रवास, त्यातले इतरांचे सहकार्य, असे बारकावे मात्र पुस्तकात भरपूर आहेत. पुण्यातल्याच कॉलेज ऑफ मिलिटरी इंजिनीअरिंगचे प्रमुखपद म्हणजेच ‘कमांडंट’पद त्यांनी ऑक्टोबर २००४ मध्ये स्वीकारले आणि डिसेंबर २००४ हा तमिळनाडूत त्सुनामी-संहाराचा महिना ठरला. मदतकार्यावर देखरेखीसाठी तातडीने त्यांना चेन्नईकडे रवाना करण्यात आले आणि तिथे कामाचा झपाटा आणि उत्तुंग झेप हे दोन्ही दिसल्यामुळेच त्यांना अनौपचारिकपणे ‘त्सुनामी जनरल’ हे टोपणनाव मिळाले! लष्कराचे इंजिनीअर-इन-चीफ झाल्यावर त्यांनी पर्यावरणनिष्ठ अभियांत्रिकीचा पुरस्कार हिरिरीने केला, परिणामी लष्करी अभियांत्रिकी विभाग २००७ च्या ‘गोल्डन पीकॉक पर्यावरणनिष्ठ उद्योग पुरस्कारां’पैकी नवोन्मेष पुरस्काराचा मानकरी ठरला. इतरांना प्रोत्साहन देणाऱ्या लेफ्ट. जन. धालीवाल यांनी, अगदी एका तळावर ‘कमी वीज वापरून अधिक वेगाने कपडे धुणे/ वाळवण्याचे काम करणारे यंत्र’ बनवल्याचेही कौतुक केले. नौकानयन (रोविंग-वल्हवणे), समुद्रातील डायव्हिंग या अनवट खेळांमध्ये ते निपुण होते. नौकानयन संघटनेचे नेतृत्वही त्यांनी केले. त्यांच्या निधनाने, लष्कराच्या इंजिनीअर-इन-चीफ पदाला वलय मिळवून देणारे व्यक्तिमत्त्व लोपले आहे.

राजवाडे विचारविश्व

कर्जबाजारी होऊनही स्वप्नरंजन सुरूच!

ऐतिहासिक साधनांच्या सहाव्या खंडाला राजवाड्यांनी लिहिलेल्या प्रदीर्घ प्रस्तावनेतल्या काही प्रमुख मुद्द्यांचा आपण अगदी थोडक्यात परिचय करून घेतला. त्या प्रस्तावनेबद्दलच्या विवेचनाचा समारोप करताना त्यांनीच उघड केलेल्या त्यांच्या कर्जबाजारी अवस्थेबद्दल आणि त्याही अवस्थेमध्ये त्यांच्या मनात घोळत असलेल्या भावी कार्याच्या रूपरेषेबद्दल थोडक्यात माहिती देणे आवश्यक आहे.

राजवाड्यांनी त्या प्रस्तावनेच्या शेवटी शेवटी आपल्या तोपर्यंतच्या कामाचा संक्षिप्त जमाखर्च वाचकांसमोर प्रामाणिकपणे ठेवला. पहिला खंड एकूण तीन वेळा छापला गेला, त्याबद्दलची तपशीलवार माहिती यापूर्वीच देऊन झाली आहे. ती सांगून झाल्यावर राजवाड्यांनी पुढे लिहिले, ‘चौथा खंड चित्रशाळेचे मालक वासुदेवराव जोशी यांनी आपल्या जबाबदारीवर प्रसिद्ध केला. दुसरा, तिसरा, पाचवा, सहावा (व आठवाही) असे पाच खंड प्रो. विजापूरकर यांनी ग्रंथमालेतून स्वतःच्या खर्चाने छापून काढले. पैकी ग्रंथकाराच्या मेहनतीचा अल्पस्वल्प मोबदला म्हणून ग्रंथमालाकार प्रत्येक खंडाच्या पन्नास प्रती मला देतात. त्या विकून शोधनाचा व प्रवासाचा खर्च मी मोठ्या काटकसरीने करतो. या पुस्तकविक्रीपासून आतापर्यंत सरासरी सहाशे रुपये प्राप्ती मला झालेली आहे. या अवधीत सुमारे ५०० रुपये श्रीमंत बाबासाहेब इचलकरंजीकर, पांडोबा शिराळकर, रावजी भिडे या तिघांनी आपखुशीने उदारपणे दिले. शिवाय दोघा-तिघा स्नेह्यांकडून प्रवासाकरिता सहाशे रुपये मी कर्ज काढले. मिळून आजपर्यंत स्वतःच्या खर्चाने व लोकांच्या देणग्यांनी मी सुमारे ३६०० रुपये या कामी खर्चिले आहेत. पैकी देण्याचे व पुस्तकविक्रीचे २१०० रुपये वजा जाता सध्या मला १५०० कर्ज आहे. ते पुढील खंडांच्या विक्रीने फेडावयाचे आहे... माझे धनको माझ्यावर प्रेम करीत असल्यामुळे त्यांच्या अडचणींच्या प्रसंगीही त्यांनी मला फारशी कधी निकड लाविली नाही, हे खरे आहे; परंतु कर्ज आहे, ही कठोर बाब विसरता येत नाही.’

त्यानंतरच्या परिच्छेदात आपल्याच कार्याचा आढावा घेत राजवाड्यांनी लिहिले, ‘वेगवेगळ्या रूपांत आजपर्यंत मी सुमारे ४४०० पृष्ठांचा नवा मजकूर शोधून विवेचनासह प्रसिद्ध केला आहे. या स्तुत्य उठाठेवीत १५०० रुपयांचे कर्ज म्हणजे नुकसान झालेले आहे. (गंमत म्हणजे हा सर्व बारीक-सारीक तपशील बिनचूक नोंदवणाऱ्या राजवाड्यांनी आपण खर्चलेले ३६०० रुपये व विजापूरकर-जोशी यांनी छापलेल्या खंडांसाठी खर्च झालेले २४०० रुपये अशा दोन रकमांची बेरीज मात्र चुकवलेली दिसते. तिचा उल्लेख त्यांनी सर्वत्र ६००० ऐवजी ५००० रुपये असाच केलेला आढळतो. समग्र राजवाडे साहित्य, खंड १०, पृष्ठ क्र. ३४२) जर एवढेसे काम करावयाला १५०० रुपये कर्ज झाले, तर शंभरपट काम अद्याप व्हावयाचे आहे, त्याला सुमारे दीड लाख रुपये कर्ज होईल व पाच लाख रुपये खर्च लागेल, कारण सध्या मजजवळ हजार बाराशे अप्रकाशित ग्रंथ व सुमारे ४०-५० हजार महत्त्वाची ऐतिहासिक कागदपत्रे जमा झालेली आहेत. त्यापैकी बराच भाग प्रसिद्ध होणे अगत्याचे आहे...’

राजवाडे केवळ ही इच्छा व्यक्त करून थांबले नाहीत, त्यांनी मराठ्यांच्या इतिहाससाधनांच्या संशोधन-प्रकाशनकार्याबद्दलचे आपले मनोराज्यही वाचकांसमोर ठेवले. त्यांनी लिहिले, ‘ती साधने शोधून काढावयास प्रथमारंभी निदान दहा तज्ज्ञ गृहस्थ लावले, तर प्रत्येकी अन्नखर्च व प्रवासखर्च मिळून वर्षाला ६०० रुपये धरल्यास ६०,००० रुपये पाहिजेत. शोधून आणलेल्या साधनांचा संग्रह करण्यास इमारत पाहिजे. तिचा खर्च सुमारे १०,००० रुपये. दरवर्षाला १०,००० अष्टपत्री पृष्ठे ऐतिहासिक अस्सल साधने प्रकाशित करण्यासाठी १०,००० रुपये लागतील. इमारत व साधनसंग्रह यांच्या व्यवस्थेसाठी एका कारकुनाचा व एका हमालाचा वार्षिक पगार (१५ व १० रुपये दरमहाप्रमाणे) ३०० रुपये आणि दिवा, बत्ती, कागद वगैरे खर्च ५०० रुपये... चालक मंडळींनी व तज्ज्ञांनी साधने निवडण्याचे, संपादण्याचे व प्रकाशनार्थ तयार करण्याचे काम फुकट करावयाचे आहे... हा सर्व अंदाज स्थूल आहे. अभिमानी मंडळींच्या सल्ल्याप्रमाणे यात योग्य फेरफार करणे जरूर पडेल...’

– **आनंद हर्डीकर**
anand47.hardikar@gmail.com

मूल्य नाही; मान तरी!

निश्चलनीकरण जाहीर झाले तेव्हा चलनातील रोख रकमेचे मूल्य फक्त १७ लाख ९७ हजार कोटी रु. इतके होते; तर आता ते जवळपास ४३ लाख रु.- म्हणजे अडीचपट अधिक!

अवघ्या पाच महिन्यांनी, ८ नोव्हेंबर २०२६ या दिवशी अर्थक्रांतीच्या शालेय बुद्धिमत्तेचे दर्शन घडवणाऱ्या निश्चलनीकरणाचा दशकपूर्ती दिन. एरवी उत्सवांसाठी असे काही 'दिन' शोधत असणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांकडून हा दशकपूर्ती सोहळा साजरा केला जाईल किंवा कसे याचे औत्सुक्य समस्त विकासेच्छू भारतीयांस निश्चितच असेल. कारण दहा वर्षांपूर्वी २०१६ साली या दिवशी साक्षात पंतप्रधानांनी 'सव्वासो क्रोर' देशवासीयांसमोर काळ्या पैशाच्या निर्मूलनार्थ पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा यापुढे 'कागज के टुकडे' होणार असल्याचे शुभवर्तमान सुहास्यवदने सादर केले. नंतर काही तासांत 'पेटीएम'ने पंतप्रधानांचे आभार मानत असल्याच्या जाहिराती सर्वदूर प्रसृत केल्या आणि ही डिजिटल इंडियाच्या भरारीची आणि त्याचमुळे कागदी नोटांच्या अंताची सुरुवात असल्याचे आपणास सांगितले गेले. त्यापुढच्या काळात काळा पैसा कायमचा अंतर्धान पावता पावता कागदी चलनी नोटा हद्दपार होणार, सीमेपलीकडून बनावट नोटांचा पुरवठा आटणार, परिणामी काश्मिरातील हिंसाचार संपणार असे बरेच काही होणार असल्याची द्वाही फिरवली गेली. त्यानंतरच्या काळात काय काय झाले ते भारतीयांनी अनुभवले. त्याच्या उजळणीची आणि याही मुद्द्यावर 'लोकसत्ता'चे भाष्य किती अचूक ठरले याच्या पुनरुक्तीची अजिबात गरज नाही. त्यातच, गेली काही वर्षे सरासरी १५ टक्के इतक्या मोठ्या गतीने रोख रकमेचा सुळसुळाट वाढत चालल्याचे प्रतिपादन चलन व्यवहारावर नियंत्रण असलेली रिझर्व्ह बँक करत असेल तर त्या द्रष्ट्या निर्णयाच्या यशापयशाची वेगळी चिकित्सा करण्याचे कारण नाही. तथापि नव्याने या विषयास स्पर्श करण्याचे कारण म्हणजे रिझर्व्ह बँकेचा ताजा निर्णय.

तो आहे यापुढे कागदाऐवजी प्लास्टिकच्या नोटा चलनात आणण्याचा. कागदी नोटा लवकर खराब होतात आणि त्यांच्या निर्मितीचा खर्चही अधिक आहे असे कारण रिझर्व्ह बँक या संदर्भात देते. ते खरे असेलही. त्याच वेळी देशातील एक बडा सरकारस्नेही 'अ'द्योगपती प्लास्टिक नोटांसाठी आवश्यक रसायनांच्या उत्पादनात प्रवेश करत असल्याचे आरोप काहींकडून होतात. तेही खरे असतील. रिझर्व्ह बँकेस प्लास्टिक नोटांची गरज वाटणे आणि या 'अ'द्योगपतीच्या संभाव्य प्लास्टिक रसायनांस गिऱ्हाईक हवे असणे हे दोनही मुद्दे एकाच वेळी तितकेच सत्य असू शकतात. तशीही भारतीयांस गेल्या दहा वर्षांत अशा योगायोगांची सवय आहेच. (पाहा : सौर ऊर्जेवर केंद्राचा धोरणात्मक भर आणि त्याच वेळी काही 'अ'द्योगपतींचे या क्षेत्रात पदार्पण इत्यादी) तेव्हा हे दोनही खरे असले वा नसले तरी रिझर्व्ह बँकेकडून जो काही तपशील प्रसृत झाला त्यावरून एक बाब मात्र निश्चित निर्विवाद खरी असल्याचे स्पष्ट दिसते. ती म्हणजे नोटा वापरणाऱ्यांच्या संख्येत होत असलेली लक्षणीय वाढ. आणि त्याबरोबर नोटा छापण्याच्या खर्चात झालेली वाढ. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातच याबाबतचा तपशील असून तो थक्क करणारा आहे. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षी केवळ नोटा छापण्यावर सुमारे पाच हजार कोटी रु. खर्च केले. तर यंदा हाच खर्च ६,३७८ कोटी इतका झाला. गेल्या वर्षी खराब झालेल्या, फाटलेल्या इत्यादी २३०० कोटी नोटा देशभर बँकेत जमा झाल्या. त्याआधीच्या वर्षात हीच संख्या २१०० कोटी इतकी होती. यातही हास्यास्पद वाटेल अशी बाब म्हणजे बँकेत बदलीसाठी आलेल्या बहुतांश नोटा या नव्या, २०१६ सालातील निश्चलनीकरणानंतर प्रसृत झालेल्या आहेत. यावरून या नोटांच्या छपाईचा, कागदाचा दर्जा काय हे ध्यानात यावे.

या सर्व तपशिलाचा अर्थ एकच. आपल्या देशात

दहा वा वीस रुपयांच्या नोटांच्या मागणीत गेल्या काही वर्षांत वाढच होत असताना, नोटा छापण्याचा खर्चही वाढतो आहे. यावर उपाय प्लास्टिक नोटांचा...

रोखीचे व्यवहार कमी होण्याचे काही नाव नाही. हे प्रमाण दरवर्षी ११.५ टक्क्यांनी वाढते असून १५ मे या एकाच दिवशी चलनात असलेल्या नोटांचे एकत्रित मूल्य ४२ लाख ८६ हजार कोटी रु. इतके आहे. यातील खरा धक्का हा की दहा वर्षांपूर्वी जेव्हा निश्चलनीकरण जाहीर झाले तेव्हा चलनातील रोख रकमेचे मूल्य फक्त १७ लाख ९७ हजार कोटी रु. इतके होते. आता ते जवळपास ४३ लाख रु. इतके आहे. म्हणजे गेल्या दहा वर्षांत चलनातील रोख रकमेचे प्रमाण जवळपास अडीच पटींनी वाढले. गेल्या एका वर्षापुरती ही झालेली 'चलनवाढ' एक लाख १५ हजार कोटी रुपयांची आहे. आपल्याकडे भाजीवालाही डिजिटल पेमेंट स्वीकारतो इत्यादी कौतुक नेहमी सांगितले जाते. ते ठीक. पण त्यामुळे रोख रकमेच्या गरजांत तसूभरही फरक पडलेला नसून उलट दहा वा वीस रुपयांच्या नोटांच्या मागणीत गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वाढच होत असल्याचे दिसते. गेली काही वर्षे नोटांऐवजी नाणी लोकप्रिय करण्याचा प्रयत्न रिझर्व्ह बँकेने करून पाहिला. अगदी वीस रुपयांचीही नाणी बँकेने प्रसृत केली. हे नाणे इतक्या रकमेचे आहे हेच कळत नाही, अशी भले नागरिकांची तक्रार असेल. पण बँकेने प्रयत्न केला. गेल्या वर्षी विविध मूल्यांची १५० कोटी नाणी बँकेने चलनात आणली. त्यात ८० कोटी नाणी ही पाच रुपयांची आहेत आणि ४० कोटी २० रु. मूल्याची. या सर्व खर्चाचा मोबदला तितक्या प्रमाणात मिळत नाही असे बँकेस वाटते.

म्हणून मग आता प्लास्टिकच्या नोटा चलनात आणण्याची टूम. विकसित जगातील इंग्लंड, सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांत अशा नोटा चलनात आहेत. या लवकर खराब होत नाहीत, हे उघड आहे. विशेषतः पाऊसपाण्यात नोटा भिजणे हे आपल्याकडील मोठे संकट. प्लास्टिकच्या नोटांमुळे त्यावर सहज मात करता येईल. दुसरे असे की अन्य अनेक प्लास्टिक चिजांप्रमाणे या नोटांस दीर्घायुष्य लाभते. एकदा छापल्या की वर्षानुवर्षे या नोटा 'चालतात'. तथापि प्लास्टिक म्हटले की पर्यावरण दुष्टतेचा आरोप ओघाने आलाच. प्लास्टिकच्या नोटा यास अपवाद ठरतात. याचे कारण खराब झालेल्या नोटांचा पुनर्वापर करता येणे तंत्रदृष्ट्या शक्य होते. म्हणजे नोटा देऊन पुन्हा नोटा छापता येतात. तसेच या नोटा 'एटीएम'स्नेही देखील असतात. निश्चलनीकरणानंतर नव्या नोटा प्रसृत करताना आपल्याकडे नव्या नोटांचा आकार बदलण्याचा निश्चलीकरणाइतकाच अनाकलनीय निर्णय घेतला गेला. परिणामी बँकांस हजारो कोटींचा भुर्दंड केवळ नव्या नोटांच्या आकाराप्रमाणे एटीएम यंत्रांची फेररचना करण्यासाठी पडला. आता तसे होणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे.

रिझर्व्ह बँकेची व्याजदराबाबतची तिमाही बैठक येत्या आठवड्यातच भरेल. आखाती युद्ध, त्याचा अर्थव्यवस्थेस बसलेला फटका इत्यादी कारणांमुळे आणि मुख्य म्हणजे खनिज तेलाचे दर वाढल्यामुळे अर्थव्यवस्थेसमोर चलनवाढीचा धोका संभवतो. अशा वेळी व्याजाचे दर वाढवणे हा जालीम इलाज. पण तसे केल्याने सरकार दुखावते. कारण कर्जे, पतपुरवठा महाग होतो आणि वाढीचा वेग अधिकच मंदावतो. तेव्हा रिझर्व्ह बँकेच्या विद्यमान नेतृत्वाचा चेहरामोहरा लक्षात घेतल्यास व्याजदर वाढवला जाण्याची शक्यता तशी कमीच. बँक व्याजदराबाबत 'जैसे थे' धोरण अंगीकारेल, हीच शक्यता अधिक. तेव्हा नोटांच्या दरांबाबत काही निर्णय होवो वा न होवो. त्यांच्या रंगरूपाबाबत मात्र लवकरच निर्णय होईल असे दिसते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रुपयाचे मूल्य वाढणार नाही, हे खरे. पण हा कागज का टुकडा प्लास्टिकचा झाला की निदान त्याचा मान तरी वाढेल, ही आशा.

'धोरणात्मक दिवाळखोरी' लोकशाहीला कुठे नेते?

लेख

निखिल संजय-रेखा अडसुळे
कायदेविषयक, समष्टी-आर्थिक आणि घटनात्मक मुद्द्यांचे विश्लेषक
nikhil15adsule@gmail.com

न्यायालयांमध्ये अपयशीच ठरणारा शासन निर्णय जाहीर करून मग अवघ्या २४ तासांत गोठवून त्यावर महाअधिवक्त्यांचे मत मागवण्याची वेळ सत्ताधाऱ्यांवर येते; त्याअर्थी काहीतरी बिनसले आहे! ते काय असू शकते, याचा अंदाज हॅना आरेंट, डॉ. आंबेडकर, एमिल डर्खिम, मिल्टन फ्रीडमन यांसारख्या विचारवंतांनी आधीच दिलेला आहे...

प्रख्यात लेखक अरुण साधू यांनी त्यांच्या 'सिंहासन' या अजरामर कादंबरीत लिहून ठेवलेले एक वाक्य आजच्या महाराष्ट्राच्या राजकीय सर्कशीला तंतोतंत लागू पडते : '*मंत्रालयाचे निर्णय आता कायद्याच्या चौकटीत नाहीत, तर रात्रीच्या अंधारात, राजकीय अस्तित्वाच्या भीतीने आणि सोयीच्या गणिताने ठरतात...*' गेल्या १४ मे रोजी राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घाईघाईने एक कार्यकारी आदेश काढला काय आणि मग त्यावर महाअधिवक्त्यांचे मत मागवण्याची वेळ आली काय... हे केवळ राजकीय कोलांटउड्यांचे नेहमीचे उदाहरण नाही, तर ती महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय यंत्रणेची संपूर्ण पीछेहाट आणि धोरणात्मक दिवाळखोरीची जाहीर कबुली आहे. आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून, मतांचे गणित जुळवण्यासाठी केलेला हा एक केविलवाणा प्रयत्न होता. पण हा निर्णय घेताना प्रस्थापित घटनात्मक मार्ग आणि कायदेशीर चौकटींना ज्या पद्धतीने वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या, त्याचा शेवट अपरिहार्यपणे न्यायालयीन भिंतीवर डोके आपटण्यातच होणार होता, हे उघड होते.

या संपूर्ण गोंधळाच्या मुळाशी घटनात्मक न्यायशास्त्राची अत्यंत ढोबळ आणि अपुरी समज आहे. शासनाने 'खुल्या प्रवर्गा'ची (ओपन कॅटॅगरी) थेट जात-आधारित आरक्षणाच्या चौकटीशी गल्लत केली. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजवरच्या अनेक निकालांनी हे वारंवार ओरडून सांगितले आहे की, खुला प्रवर्ग म्हणजे काही कोणताही विशिष्ट जातीय कोटा नव्हे! तो केवळ गुणवत्तेवर आधारित एक मुक्त प्रवाह आहे, जो कोणत्याही लोकसंख्येच्या किंवा सामाजिक स्तराच्या पलीकडे जाऊन देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी खुला असतो. एका अवास्तव शासन निर्णयाद्वारे (जीआर) या प्रवाहाची दिशा बदलण्याचा प्रयत्न करून महाराष्ट्राच्या राजकीय नेतृत्वाने मनमानी कारभाराचे एक नवे आणि हास्यास्पद उदाहरण समोर ठेवले.

कार्यपद्धतीच्या तत्त्वांनाच हरताळ

हा १४ मेचा शासन निर्णय घटनात्मक वैधतेशी पूर्णपणे फारकत घेणारा होता. राजकीय तत्त्ववेत्त्या हॅना आरेंट यांनी 'मनमानी शक्ती' आणि 'संस्थात्मक अधिकार' यांमधील जो फरक स्पष्ट केला आहे, त्याचीच प्रचीती यातून येते. एखादी शासनव्यवस्था क्लिष्ट सामाजिक-कायदेशीर समीकरणे सोडवण्यास असमर्थ ठरते, तेव्हा ती अशा अनधिकृत कार्यकारी आदेशांचा आसरा घेते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वीच 'छाया विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य' या ऐतिहासिक खटल्यात सरकारचे कान टोचताना दिलेल्या निकालाचे थेट उल्लंघन करतो. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, खुल्या प्रवर्गाची रचना अशी काही गणिती किंवा रचनात्मक पद्धतीने फिरवता येणार नाही, ज्यायोगे त्यातून कोणाला मागच्या दाराने बाहेर काढले जाईल.

भारताच्या संविधान सभेतील चर्चेदरम्यान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अशा संस्थात्मक गैरकारभाराविषयी आधीच इशारा दिला होता. लोकशाहीचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी घटनात्मक मार्गांचे काटेकोर पालन करणे अनिवार्य असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. मात्र, प्रस्तुत प्रकरणात मंत्रिमंडळाने मसुदा तयार करताना विधि व न्याय विभागाला पूर्णपणे अंधारात ठेवले. परिणामी, 'कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या कार्यपद्धती'च्या मूलभूत तत्त्वांनाच हरताळ फासला गेला. कोणत्याही राज्यस्तरीय रोजगार धोरणाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी त्याची सखोल कायदेशीर छाननी होणे आवश्यक असते, जेणेकरून ते धोरण न्यायालयीन पुनरावलोकनात टिकू शकेल. दीर्घकालीन घटनात्मक नैतिकतेपेक्षा तात्कालिक राजकीय फायद्याला प्राधान्य देऊन राजकीय नेतृत्वाने स्वतःचे हसे करून घेतले आणि हे धोरण कायदेशीररीत्या किती कच्चे होते, यावर स्वतःच शिक्कामोर्तब केले.

नोकरशाहीवर दुष्परिणाम

या कायदेशीर पेचामुळे महाराष्ट्राच्या नोकरशाहीच्या संरचनेतही मोठी उलथापालथ झाली आहे. सध्या राज्यातील नागरी सेवा अभूतपूर्व स्तब्धतेचा सामना करत आहेत. महाराष्ट्र पोलीस, महसूल विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील जवळपास ९० हजार पदोन्नतीची पदे सध्या गोठलेली आहेत.

समाजशास्त्रज्ञ एमिल डर्खिम यांच्या 'ॲनोमी' (ॲनोमी) म्हणजेच नियामक अनिश्चिततेमुळे निर्माण होणाऱ्या संस्थात्मक गोंधळाच्या सिद्धांताशी ही परिस्थिती साधर्म्य दर्शवते. महाराष्ट्राची नागरी सेवा सध्या याच प्रशासकीय अराजकतेचा सामना करत आहे. जेव्हा वारंवार बदलणाऱ्या धोरणांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या कारकीर्दीतील प्रगतीचे मार्ग रोखले जातात, तेव्हा सार्वजनिक प्रशासनाचा कणाच मोडून पडतो. आज अनेक शासकीय विभाग कायमस्वरूपी आणि कायदेशीरदृष्ट्या सुरक्षित नियुक्त्यांऐवजी प्रभारी, हंगामी किंवा तदर्थ (ॲड-हॉक) नेतृत्वावर चालवले जात आहेत. या अस्थिरतेमुळे राज्याची प्रशासकीय कार्यक्षमता घटते, सार्वजनिक कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळे येतात आणि संपूर्ण यंत्रणेत असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण होते.

अवैध धोरणांची आर्थिक किंमत

कार्यकारी अधिकारांचा हा अतिरेक केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही. राजकीय अस्तित्वासाठी जेव्हा राज्ये संस्थात्मक गुणवत्तेशी तडजोड करतात, तेव्हा कशी अस्थिरता निर्माण होते, याचे अनेक दाखले जागतिक इतिहासात आहेत. वस्तुनिष्ठ निकष आणि कायदेशीर वैधतेचा विचार न करता जेव्हा धोरणे आखली जातात, तेव्हा संपूर्ण व्यवस्था कोलमडते. श्रीलंकेतील आर्थिक आणि प्रशासकीय संकट हे याचेच उदाहरण आहे; जिथे संस्थात्मक सल्लामसलत न करता घेतलेल्या तडकाफडकी निर्णयांनी देशाची प्रशासकीय यंत्रणा उद्ध्वस्त केली.

या धोरणात्मक गोंधळामुळे निर्माण झालेला सामाजिक-राजकीय असंतोष उघड्या डोळ्यांनी दिसत असला, तरी त्याचे समष्टी-आर्थिक (मॅक्रोइकॉनॉमिक) दुष्परिणाम तितकेच गंभीर आहेत, ज्यावर फारशी चर्चा होत नाही. अर्थतज्ज्ञ मिल्टन फ्रीडमन यांचे प्रसिद्ध आर्थिक सूत्र आहे की, 'प्रत्येक सार्वजनिक धोरणात्मक निवडीची एक छुपी पण अपरिहार्य किंमत असते.' जेव्हा सरकार पुरेशा अभ्यासाशिवाय नवीन नियम लागू करते, तेव्हा त्याला अनेक न्यायालयीन याचिकांचा सामना करावा लागतो. ही कमकुवत धोरणे न्यायालयात टिकवण्यासाठी सरकारला नामवंत वकिलांवर जनतेच्या करातून गोळा झालेला प्रचंड पैसा खर्च करावा लागतो. हा निधी पायाभूत सुविधा, दुष्काळ निवारण किंवा ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेसाठी वापरता आला असता.

दुसरीकडे, नोकरशाहीत जेव्हा अनिश्चितता आणि भीतीचे वातावरण असते, तेव्हा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया, प्रकल्पांना मंजुरी आणि खरेदी प्रक्रिया कमालीची मंदावते. या विलंबामुळे राज्याच्या कार्यक्षमतेला खीळ बसते आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळीत होतो. हजारो महत्त्वाची पदे दीर्घकाळ रिक्त ठेवल्यामुळे प्रशासनात तीव्र असंतुलन निर्माण झाले आहे. काही विभागांमध्ये अधिकाऱ्यांची संख्या गरजेपेक्षा जास्त आहे, तर काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांची तीव्र टंचाई आहे. यामुळे अर्थसंकल्पीय निधीचा अपव्यय होतो. जेव्हा एखादे राज्य आपले मोठे धोरणात्मक निर्णय अवघ्या २४ तासांत फिरवते, तेव्हा ते आर्थिक बाजाराला आणि गुंतवणूकदारांना राज्यातील अनागोंदी, गोंधळ आणि तीव्र संस्थात्मक अस्थिरतेचाच संकेत देत असते.

राजकीय स्वार्थ हवा की संविधानाधारित स्थैर्य?

महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय इतिहासात १४ मेचा तो शासननिर्णय (जीआर) एक मोठा धडा देऊन गेला आहे. केवळ राजकीय सोयीसाठी आणि मतांच्या हव्यासापोटी जेव्हा घटनात्मक मर्यादा ओलांडल्या जातात, तेव्हा व्यवस्थेचे कसे धिंडवडे निघतात, याचे हे एक जिवंत उदाहरण! मुळात घटनात्मक दृष्टिकोनातून विचार केला, तर खुला प्रवर्ग (अनरिझर्व्हड् कॅटॅगरी) हा केवळ आणि केवळ गुणवत्तेचाच मुक्त मंच राहिला पाहिजे. ती काही कोणाला सत्तेने वाटलेली खैरात किंवा राजकीय भीक नाही. तात्कालिक राजकीय स्वार्थासाठी या खुल्या प्रवाहाशी खेळ करण्याचा कोणताही प्रयत्न अखेर समाजात जातीय ध्रुवीकरण घडवून आणतो आणि कायद्याच्या राज्याला सुरुंग लावतो, हे आता तरी सरकारने समजून घ्यायला हवे.

या उथळ धोरणामुळे निर्माण झालेली ही संस्थात्मक कोंडी खरोखरच सोडवायची असेल, तर मग राजकीय नेतृत्वाला या तात्पुरत्या मलमपट्टीच्या आणि 'रात्रीच्या अंधारात निर्णय घेण्या'च्या चौकटीतून बाहेर पडावेच लागेल. रखडलेल्या नागरी सेवा पूर्वपदावर आणायच्या असतील आणि जवळपास ९० हजार शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा करायचा असेल, तर सरकारने एक पारदर्शक आणि कायदेशीररीत्या भक्कम अशी चौकट उभी करण्याची गरज आहे. हे काम केवळ राजकीय रणनीती आखणाऱ्या आणि वातानुकूलित केबिनमध्ये बसणाऱ्या नेत्यांच्या मर्जीवर न सोडता, विधि विभागातील कायदेतज्ज्ञ आणि प्रशासकीय विश्लेषकांच्या हाती सोपवायला हवे. जोपर्यंत सरकार कायद्याच्या राज्याप्रति आणि संविधानाप्रति आपली निष्ठा कागदावरून उतरवून प्रत्यक्षात सिद्ध करत नाही, तोपर्यंत प्रशासनाची गेलेली अब्रू परत मिळवणे आणि महाराष्ट्रातील जनतेची प्रामाणिकपणे सेवा करणारी एक स्थिर नोकरशाही निर्माण करणे निव्वळ अशक्य आहे.

अन्वयार्थ

अपात्र बहिणींचेही लाड!

मतांसाठी राजकीय नेते कोणत्याही थराला जातात. तिजोरीचा अंदाज न घेता लोकप्रिय घोषणांचा सपाटा लावला जातो. निवडणुकीत यश मिळवल्यावर लोकप्रिय योजनांना एक तर कात्री लावली जाते किंवा त्या बंद केल्या जातात. शेतकऱ्यांना मोफत वीज योजनेपासून ते लाडकी बहीण योजनेपर्यंत हे महाराष्ट्रात अनुभवास आले. राज्यात गेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या यशात महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेतून पावणेदोन वर्षांनी जवळपास ८० लाख लाभार्थींना वगळण्यात आले आहे. खरे तर याबद्दल महाराष्ट्र सरकारचे अभिनंदन. कारण दरमहा ठरावीक रक्कम मिळवून देणाऱ्या योजनेतून लाभार्थींना वगळणे हे तसे आव्हानात्मक होते. पण देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने विलंबाने का होईना हे धाडस केले.

कोणतीही योजना सुरू करण्यापूर्वी सरकारच्या पातळीवर योजनेचा तिजोरीवर येणारा भार तसेच परिणामांचा विचार करणे आवश्यक असते. लाभार्थींसाठी अटी तयार करून त्याची कसोशीने अंमलबजावणी करणे, ही तर सरकारकडून किमान अपेक्षा असते. पण विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेची घोषणा करून महिलांकडून अर्ज मागवले. दरमहा १५०० रु. मिळणार असल्याने २१ ते ६५ या वयोगटातील महिलांनी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज दाखल केले. सत्ताधारी महायुतीच्या घटक पक्षांच्या कार्यालयांमधून अर्ज भरून घेऊन, सरकारी कार्यालयांमध्ये जमा करण्यात आले. आलेले सर्व अर्ज मंजूर करण्याचे 'अनौपचारिक फर्मान' असल्यामुळे सरकारी यंत्रणांनी छाननीची 'औपचारिकता' पार पाडली. बहुतेक अर्ज मंजूर झाले. यानुसार अडीच कोटींच्या आसपास महिला मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्र ठरल्या व त्यांच्या खात्यात एकदम तीन महिन्यांचे ४५०० रुपयांचे अनुदान जमा झाले. या योजनेपायी महिला वर्गाची मोठ्या प्रमाणावर मते सत्ताधारी महायुतीला मिळाली. पहिल्या वर्षी सुमारे ४० हजार कोटी रुपये लाडक्या बहिणींवर. मग राज्याच्या तिजोरीवर येणारा बोजा लक्षात घेता खर्च कसा कमी करता येईल यावर सखोल विचारविनिमय झाला. सरकारने प्राप्तिकर भरणाऱ्या, वयाचे, उत्पन्नाचे निकष पूर्ण न करणाऱ्या बहिणींना या योजनेतून टप्प्याटप्प्याने वगळले. वाहन नावावर असलेल्या महिलांची माहिती प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून मागविण्यात आली. तसेच अन्य सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या बहिणींना या योजनेतून बाद करण्यात आले. महिलांसाठीच्या या योजनेचा १४ हजार पुरुषांनी लाभ घेतला. हे तर अधिक धक्कादायक. महिलांच्या खोट्या नावाने पुरुषांनी सादर केलेले अर्ज मंजूर झाले कसे, हा खरा प्रश्न. सुमारे पाच लाख सरकारी कर्मचारीही या योजनेचा लाभ घेत होते. अशा प्रकारे ८० लाखांपेक्षा अधिक नावे या योजनेतून बाद करण्यात आली आहेत. ग्रामपंचायतींपासून महानगरपालिकांपर्यंतच्या सर्व निवडणुका आटोपल्यानंतर नावे वगळण्यास वेग आला, पण योजना सुरू करताना अर्जांची कठोरपणे छाननी झाली असती तर सरकारी पैसा अपात्र लाभार्थींसाठी खर्च झाला नसता. अपात्र लाडक्या बहिणींकडून पैसे वसूल केले जाणार नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याने सरकारने वाटप केलेली १५ हजार कोटींच्या आसपास रक्कम 'बोगस बहिणीं'च्या खिशात गेली आहे.

लोकशाही आघाडी सरकारच्या म्हणजेच सुशीलकुमार शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात विधानसभा निवडणुकीआधी शेतकऱ्यांसाठी मोफत विजेचा निर्णय घेण्यात आला होता. निवडणुकीत त्याचा काँग्रेस - राष्ट्रवादीला फायदाही झाला. पुन्हा सत्तेत येताच तिजोरीवरील बोजा वाढू लागल्याने तत्कालीन विलासराव देशमुख सरकारने ती योजना गुंडाळली होती. तर या वेळी एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने सुरू केलेल्या लाडक्या बहिणींच्या योजनेत फडणवीस सरकारने काटछाट करून सरकारवरील आर्थिक बोजा कमी केला आहे. बोगस लाभार्थींची इतक्या मोठ्या प्रमाणात नोंद उघड झाल्याचे राज्याच्या इतिहासातले हे पहिलेच प्रकरण असल्याने योजनेचा गैरफायदा घेतलेल्या बहिणींना आता दोष दिला जात आहे. पण हे सारे सरकारचेच पाप. योजना सुरू करताना अर्जांची छाननी झाली असती तर ही वेळ आली नसती. विलंबाने का होईना, सरकारने बोगस लाभार्थींना अपात्र ठरवले ते चांगलेच झाले. पण काँग्रेसकाळात हाच घटनाक्रम घडला असता तर, 'अपात्र लाभार्थींना अद्दल घडवा' असा धोषा भाजपने लावला असता... आता कुणीच कुणाला अद्दल वगैरे घडवणार नाही... कारण अपात्र ठरलेल्या बहिणींकडून एका पैचीही वसुली न करता त्यांचेही लाड पुरवले जाणार आहेतच!

आमदाराने राजीनामा दिला तरी अपात्रतेची कारवाई सुरू राहते का?

विश्लेषण

संतोष प्रधान
santosh.pradhan@expressindia.com

एखाद्या आमदाराच्या विरोधात अपात्रतेची कारवाई सुरू असताना त्याने राजीनामा दिल्यास कारवाई थांबते का, यावरील मतमतांतरे तमिळनाडूतील प्रकरणामुळे पुन्हा उफाळली आहेत...

तमिळनाडूतील पेच काय आहे?

तमिळनाडू विधानसभेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत तिथल्या कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे सर्वाधिक १०८ जागा जिंकलेल्या चित्रपट अभिनेते जोसेफ विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाने काँग्रेस, डावे व अन्य पक्षांच्या साहाय्याने सरकार स्थापन केले. सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावावर ४७ आमदार निवडून आलेल्या अण्णा द्रमुकच्या २५ आमदारांनी पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेच्या विरोधात, सरकारच्या बाजूने मतदान केले. अण्णा द्रमुकने या २५ आमदारांना दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार अपात्र ठरवण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांकडे याचिका सादर केली आहे. या सर्व घडामोडी घडत असतानाच अण्णा द्रमुकच्या चार आमदारांनी सदस्यत्वाचा राजीनामा अध्यक्षांकडे सादर केला. विधानसभा अध्यक्षांनी या चारही आमदारांचे राजीनामे स्वीकृत केले. परिणामी हे चारही जण आता आमदार राहिलेले नाहीत. परंतु, 'या आमदारांचे स्वीकृत केलेले राजीनामे रद्द करावेत, कारण या आमदारांच्या विरोधात अपात्रतेची कारवाई सुरू झाली आहे', अशी मागणी अण्णा द्रमुकने अध्यक्षांना पत्र पाठवून केली आहे. याच दरम्यान काही आमदारांनी पुन्हा पक्षात प्रवेश करीत माजी मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांना पाठिंबा जाहीर केला. त्यांच्या विरोधातील अपात्रतेची कारवाई पक्षाने मागे घेतली आहे.

आमदारांचा राजीनामा विधानसभा अध्यक्षांना स्वीकारावाच लागतो?

भारतीय राज्यघटनेच्या १९० (३)(ब) मध्ये आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. यानुसार आमदाराने स्वहस्ते लिहिलेल्या पत्राद्वारे राजीनामा सादर केल्यास अध्यक्षांना तो स्वीकृत करावा लागतो. या परिस्थितीत विधानसभा अध्यक्षांकडे मर्यादित पर्याय आहेत. आमदाराने स्वखुशीने उपस्थित राहून राजीनामा पत्र सादर केल्यास अध्यक्षांना त्यावर निर्णय घ्यावा लागतो. 'आमदारांनी स्वखुशीने राजीनामा सादर केल्यास अध्यक्षांना स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नसतो', असे सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकातील आमदारांच्या राजीनाम्यावरील याचिकेवर स्पष्ट केले होते. महाराष्ट्रात आमदारांना राजीनामा द्यायचा असल्यास विधानसभा नियमावलीत राजीनामा पत्राचा नमुना निश्चित करण्यात आला आहे. या नमुन्यानुसारच राजीनामा पत्र अध्यक्षांकडे सादर करावे लागते.

आमदाराने राजीनामा दिल्यास 'अपात्रते'चे काय?

एखाद्या आमदाराच्या विरोधात अपात्रतेची कारवाई सुरू असताना त्याने राजीनामा दिल्यास त्याच्याविरोधातील अपात्रतेची कारवाई थांबते का, यावर कायदेशीर पातळीवर वेगवेगळी मते मांडली गेली आहेत. तसेच, किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातही विसंगती आढळते. कर्नाटकात २०१९ मध्ये काँग्रेसच्या काही आमदारांनी सदस्यत्वाचे दिलेले राजीनामे विधानसभा अध्यक्षांनी लगेच स्वीकृत केले नव्हते. या आमदारांच्या विरोधात तेव्हा अपात्रतेची सुनावणी सुरू होती. विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षादेशाच्या आदेशाचा भंग केल्यावरून या आमदारांना अपात्र ठरवून, विधानसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत त्यांना निवडणूक लढवता येणार नाही, असा आदेश दिला होता. या आदेशाच्या विरोधात आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांची अपात्रता कायम ठेवली, पण निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्याचा आदेश रद्दबातल ठरवला होता. 'आमदाराने राजीनामा दिला तरी अपात्रतेची कारवाई रद्द होत नाही,' असा दाखला त्या वेळी देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने, आमदाराने दिलेला राजीनामा स्वीकारण्याच्या अध्यक्षांच्या अधिकाराच्या खोलात जाण्याची विनंती मात्र मान्य केली नव्हती. मग १९९२च्या नागालॅण्डमधील किहोटो होलोहॉन विरुद्ध झाचीलुहू खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या राजीनाम्यानंतर, 'अपात्र ठरवण्याच्या विधानसभाध्यक्षांच्या अधिकाराचा फेरविचार करण्याची गरज नाही' असा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने विविध खटल्यांमध्ये वेगवेगळे निकाल दिल्याने, राजीनामा दिला तरी अपात्रतेची कारवाई सुरू राहते का, यावर घोळ आहे.

मात्र, विधानसभा अध्यक्षांनी राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार दिलेल्या कोणत्याही निकालाचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन करता येते हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना व राष्ट्रवादीतील फुटीनंतर दोन्ही पक्षांच्या आमदारांच्या विरोधात अपात्रतेवरील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. फक्त फरक एवढाच की, बंड केलेल्या आमदारांपैकी कोणी सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला नव्हता. तमिळनाडूत आमदारांच्या राजीनाम्यामुळे पेच निर्माण झाला आहे.

संपादकीय

१७ जागांसाठी सावळागोंधळ

सध्या तशा कोणत्याही निवडणुका नाहीत; पण ज्येष्ठांच्या सभागृहात (विधानपरिषद) जाण्यासाठी १७ जागांची निवडणूक रंजक बनली आहे. आपलेच आपल्याविरोधात उभे ठाकल्याचे चित्र काही ठिकाणी दिसत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून १७ जण आमदार म्हणून विधानपरिषद गाठणार आहेत. जनतेतून थेट निवडून जाण्याची हिंमत वा ताकद नसलेल्यांसाठी अशी निवडणूक ही एक संधी असते. अर्थसत्तेच्या आधारे राजसत्ता गाठण्याची महत्त्वाकांक्षा असलेले काही लक्ष्मीपुत्रही मैदानात उतरले आहेत. अशा महत्त्वाकांक्षेला प्रादेशिक मर्यादा नसतात. वर्षानुवर्षे अमाप संपत्ती मिळालेल्यांना आपली अर्थसत्ता अधिक व्यापक करण्यासाठी राजकारणाचा आधार हवा असतो आणि हा आधार आमदारकीच्या माध्यमातून मिळत असेल तर त्यासाठी मर्यादित मतदारसंख्या असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक हा आणखीच सोपा मार्ग वाटतो. काही कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात मिळणारी आमदारकी नंतर आणखी काही कोटी रुपये कमावण्यासाठी आणि उभारलेल्या साम्राज्याचे संरक्षण करण्यासाठी उपयोगी पडणार असेल तर अशी संधी कोण सोडणार? अशा धनदांडग्यांना आमदारकीची तिकिटे का दिली जात असतील? त्यामागेही अर्थपूर्ण व्यवहार होत असतील का? अर्थात, त्यासाठी कोणतेही पुरावे नसले तरी चर्चा तर तशीच होत असते. पुण्यातील एका माजी आमदाराने तेथील तिकीट वाटपाबाबत तसा आरोपदेखील केला आहे. एक मात्र खरे की केवळ धनदांडग्यांनाच तिकिटे दिली गेली आहेत असे मात्र नाही. वर्षानुवर्षे पक्षासाठी काम करणाऱ्यांना भाजप आणि विरोधकांनीही आमदारकी देऊ केली आहे. अर्थात, महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांना आपल्या कार्यकर्त्यांना तिकिटे देण्याची जी उपरती आज जिंकण्याची शक्यता नसताना झाली आहे तशी उपरती त्यांना त्यांच्याकडे बहुमत असताना आणि निवडणूक जिंकण्याची पूर्ण खात्री असताना झाली असती का, हा प्रश्न आहेच. बहुमत असते तर बड्या नेत्यांच्या निकटच्या नातेवाइकांचा उमेदवारांमध्ये मोठा भरणा नक्कीच राहिला असता. त्याचवेळी भाजपचे चार-पाच उमेदवार असे आहेत की जे काही वर्षांपूर्वी काँग्रेस वा अन्य पक्षांमध्ये होते. विधानसभेतून विधानपरिषदेवर संधी देताना पक्षातील निष्ठावंतांची निवड करणाऱ्या भाजपने यावेळी मात्र, इकडून तिकडून आलेले; पण आता पक्षात पुरते स्थिरावले आहेत अशांना अधिक संधी दिली आहे. लोकसभा वा विधानसभा निवडणुकीपूर्वी किंवा त्याहीआधी जे नेते भाजपमध्ये गेले तेव्हा त्यांना दिलेला शब्द आता आमदारकीच्या निमित्ताने पाळला आहे. यामुळे इच्छुक असलेल्या जुन्या निष्ठावंतांचा नक्कीच भ्रमनिरास झाला असेल. महायुतीच्या या निवडणुकीतील जागावाटपाचा फॉर्म्युला ११-४-२ असा आधीच ठरला असला तरी काही ठिकाणी महायुतीतील दोन पक्षांचे उमेदवार एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकल्याचे चित्र आज दिसत आहे. ४ जून ही उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख आहे, तोपर्यंत वर चर्चा होऊन बंडोबांना थंडोबा केले जाईल, त्यासाठी काही 'व्यवहार'देखील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा व्यवहारांचे स्वरुप वेगवेगळे असते. विधानपरिषदेची निवडणूक बरेचदा विचारांच्या नव्हे तर व्यवहारांच्या ताकदीची परीक्षा असते. मात्र, जागावाटप नक्की झालेले असतानाही विरोधात उमेदवार उभे केले जातात याचा अर्थ महायुतीत सगळेच आलबेल नाही हे स्पष्ट आहे. राज्यपातळीवरील नेत्यांमध्ये समन्वय असला तरी खालचे नेते एकतर त्यांचे ऐकत नाहीत असा त्याचा अर्थ होतो. महायुतीतच एकमेकांबाबतची कटुता हेही प्रमुख कारण आहे. सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडणुकीच्या वेळी ही स्थानिक कटुता प्रकर्षाने समोर आली होती; पण कमीअधिक प्रमाणात ती अनेक ठिकाणी आहेच. या निवडणुकीच्या निमित्ताने ती पुन्हा एकदा समोर आली आहे. उद्या वरच्या नेत्यांच्या आदेशावरून माघार वगैरे होईलही, पण या माघारीने कटुतादेखील संपेल, अशी हमी देता येणार नाही. महायुतीमध्ये भाजपचे विधानसभेतील संख्याबळ अपक्षांसह १३६ इतके आहे. त्याआधारे विधानसभेतून विधान परिषदेवर पाठवावयाच्या जागा त्यांनी वाढवून घेतल्या. यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत भाजपने क्रमांक एकचे यश मिळवले आणि विधानपरिषदेच्या १७ पैकी ११ जागा पदरी पाडून घेतल्या आहेत. शिंदेसेनेला चार तर राष्ट्रवादीला (अजित पवार) दोनच जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. ताकद वाढवत चाललेला भाजप हा काँग्रेससह विरोधी पक्षांना शक्तिहीन करत आहेच; पण मित्रांचाही संकोच करत असल्याचे हे निदर्शक मानावे लागेल.

हवाई दलाने सीमा सांभाळायच्या की 'नीट'चे पेपर?

'नीट' फेरपरीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका विविध केंद्रांवर पोहोचविण्यासाठी वायुदलाची मदत घेण्याची धर्मेंद्र प्रधान यांची घोषणा वादात सापडली आहे.

हरीष गुप्ता
नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

मोदी सरकारमधील शिक्षण मंत्रालयाने जेवढे वाद निर्माण केले, तेवढे फार थोड्या मंत्रालयांनी केले असतील. स्मृती इराणी, रमेश पोखरीयाल निशांत यांच्यापासून सध्या हे खाते सांभाळत असलेले धर्मेंद्र प्रधान यांच्यापर्यंत प्रत्येकच मंत्री परीक्षांच्या व्यवस्थापनावरून वादाच्या भोवऱ्यात सापडले. धोरणांची अंमलबजावणी, अर्थसंकल्पीय प्राधान्य, सुधारणा प्रत्यक्षात आणणे या काही बाबी टीकेचे लक्ष्य ठरल्या. प्रकाश जावडेकर हे एकच मंत्री दिसतात ज्यांच्याबाबत मोठा काही वाद झाला नाही.

'नीट'च्या फेरपरीक्षेसाठी वायुदलाच्या विमानांनी प्रश्नपत्रिका पोहोचविण्याचा प्रस्ताव अलीकडेच वादंग निर्माण करून गेला. २१ जूनला ही फेरपरीक्षा व्हावयाची आहे. परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये विश्वास निर्माण व्हावा, यासाठी उचलले गेलेले हे पाऊल प्रत्यक्षात टीकेचा विषय ठरले. विरोधी पक्ष, शिक्षण खात्यातील तज्ज्ञ आणि इतरांनी टीकेचा भडीमार सुरू केला. सरकारला वायुदलाची मदत घ्यावी लागते, यावरून हा पेचप्रसंग किती गंभीर आहे हेच उघड होते; प्रशासकीय कार्यक्षमता तर यातून काहीच दिसत नाही, असे त्यांचे म्हणणे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीमध्ये नेमके कुठे चुकले हे सरकारला ठरवता न आल्याने सरकारने हा मार्ग अवलंबिला आहे. प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे ३ मे रोजी 'नीट'ची परीक्षा रद्द करावी लागली होती.

शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी संस्था पातळीवर चूक झाल्याचे मान्य केले. छापखान्यातून प्रश्नपत्रिका उचलून विविध केंद्रांवर पोहोचवण्यासाठी वायुदलाची मदत घेण्याची त्यांची घोषणा वादात सापडली. राष्ट्रीय सुरक्षा हे भारतीय हवाई दलाचे काम आहे. त्यांनी सीमा सांभाळायच्या आहेत, परीक्षेची प्रक्रिया नव्हे!

भारत-अमेरिकेच्या मधुर मैत्रीचे रहस्य

अमेरिकेचा धोरणात्मक भागीदार देश म्हणून मागचे वर्ष भारताला काही फार चांगले गेले नाही. वॉशिंग्टनकडून सतत टीकेचे सूर उमटतच राहिले. भारताची रशियाकडून तेल खरेदी असो किंवा व्यापारातील असमतोल; वरिष्ठ अमेरिकी अधिकाऱ्यांकडून सातत्याने टीकात्मक शेरेबाजी होत राहिली. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हेही त्यात सहभागी होते. त्यानंतर सर्जिओ गोर आले. भारतातील अमेरिकेचे राजदूत म्हणून जानेवारी २०२६ मध्ये सूत्रे हाती घेण्याच्या तीन महिने आधीच त्यांनी पंतप्रधान

नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. राजनैतिक वर्तुळात याचा अर्थ असाच काढला गेला की गोर यांचे ट्रम्प यांच्या प्रशासनात खूप वरपर्यंत चालते.

गोर भारतात आल्यापासून भारत आणि अमेरिका यांच्या संबंधांचा सूर लक्षणीयरीत्या बदलला. वॉशिंग्टनकडून भारतावर होणारी जाहीर टीका गायब झाली आणि व्यापार, तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि धोरणात्मक व्यवहारांच्या बाबतीत सहकार्याची भाषा बोलली जाऊ लागली. द्विपक्षीय संबंधांना झाकोळून टाकणाऱ्या कटकटीच्या गोष्टी बऱ्याच सुरळीत झाल्या.

आता या उभय देशांच्या मैत्रीबाबत पुढच्या मोठ्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले जात आहे; तो म्हणजे कोण कोणाला आधी भेट देते? अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबीयो यांनी अध्यक्ष ट्रम्प यांचे व्हाइट हाऊसला भेट देण्याचे निमंत्रण पंतप्रधान मोदी यांना दिले. मात्र, मोदी यांनी त्यावर काहीच प्रतिसाद दिलेला नाही.

राजनैतिक वर्तुळात असे म्हटले जाते की, शिष्टाचाराप्रमाणे ट्रम्प यांनी आधी भारताला भेट दिली पाहिजे. शक्यतो क्वाड नेत्यांच्या आगामी शिखर बैठकीला ते येऊ शकतात. पण, एक नक्की की, भारत-अमेरिका संबंधांच्या सुरळीतपणात गोर यांचे महत्त्व मुळीच नजरेआड करता येणार नाही.

ल्युटेन्स दिल्लीतील क्लब अडचणीत

दिल्ली जिमखाना क्लबची २७.३ एकराची जमीन पुन्हा ताब्यात घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे इतर अशा क्लबना कापरे भरले आहे. ल्युटेन्स दिल्लीच्या मध्यभागात हे क्लब आहेत. त्यांच्या ताब्यात असलेल्या मोक्याच्या सार्वजनिक जागांवर सगळ्यांची नजर पडली. दिल्ली गोल्फ क्लब, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इंडियन वुमन्स प्रेस कोअर अँड जेम्सफोर्ड क्लब या त्यातल्या काही संस्था. प्रेस क्लब ऑफ इंडिया आणि इंडियन वुमन्स प्रेस कोअर यांना पूर्वीच सरकारने जागा खाली करून देण्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत. परंतु, प्रकरणे न्यायालयात गेली, प्रशासकीय दिरंगाई आणि संस्थात्मक आळस यामुळे जागा त्यांच्याच ताब्यात राहिल्या.

सेंट्रल व्हिस्टा कन्स्ट्रक्शन योजना सध्या जोशात असून, संसदेची नवी इमारतही उभी राहिली आहे. जिमखाना क्लबविरुद्धची मोहीम ही दिल्लीतल्या शक्ती केंद्रांना नवा आकार देण्याच्या मोहिमेचा भाग आहे. ल्युटेन्स दिल्लीतील अभिजनांच्या क्लबना सरकार सांगत आहे - आजवर जे हक्क भोगलेत त्याला धक्का लागणार नाही, असे समजू नका.

harish.gupta@lokmat.com

कामगारनामा

'स्मार्ट' शहरांनी हाकलण्यापेक्षा 'स्मार्ट' गावात काम मिळणे उत्तम!

गावांमध्येच रोजगार, उद्योजकता, दर्जेदार शिक्षण, मूलभूत सुविधा मिळाल्या, तर कामगारांसाठी स्थलांतर हा मजबुरीचा नव्हे, निवडीचा पर्याय ठरेल.

डॉ. कुलदीपसिंह राजपूत
स्थलांतर, कामगार विषयांचे अभ्यासक

भारतातील विकासाचा नकाशा गेल्या दोन दशकांत मोठ्या प्रमाणावर शहरांच्या भोवती रेखाटला गेला आहे. उंच इमारती, मेट्रो, एक्स्प्रेस-वे, स्मार्ट तंत्रज्ञान आणि आधुनिक नागरी सुविधा यांना विकासाचे प्रतीक मानले गेले. परंतु, एक मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित राहतो तो म्हणजे जर देशाची लाखो गावे रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि मूलभूत सेवांपासून वंचित असतील, तर केवळ 'स्मार्ट सिटी' उभारून भारत खऱ्या अर्थाने विकसित होऊ शकतो का? पुण्यातील एका कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी 'स्मार्ट व्हिलेज'ची गरज अधोरेखित करताना याच मूलभूत प्रश्नाला हात घातला आहे. भारताच्या पुढील विकास प्रवासात आणि आत्मनिर्भरतेसाठी शहरांइतकीच गावेही केंद्रस्थानी आणण्याची वेळ आता आली आहे, हे ध्यानात घेतले पाहिजे.

२००५ मधील 'जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी नूतनीकरण अभियान'पासून ते २०१५ च्या 'स्मार्ट सिटी मिशन'पर्यंतच्या धोरणांनी शहरांना देशाच्या आर्थिक विकासाच्या केंद्रस्थानी आणले. गेल्या दोन दशकांत शहरे ही विकासाची 'ग्रोथ इंजिन' बनली आणि शहर-केंद्रित विकासाचे मॉडेल प्रस्थापित झाले. उद्योग, गुंतवणूक, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांचा मोठा वाटा शहरांकडे वळत असताना ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषी क्षेत्र आणि स्थानिक रोजगारनिर्मितीकडे तुलनेने कमी लक्ष दिले गेले. परिणामी, ग्रामीण आणि निम-शहरी भागातील लाखो कामगारांना उपजीविकेच्या शोधात शहरांकडे स्थलांतर करावे लागले. आज देशातील व्यापक कामगार स्थलांतर हे ग्रामीण भागातील संधींच्या कमतरतेचे आणि विकासातील असमतोलाचे प्रत्यक्ष प्रतिबिंब आहे. जेव्हा रोजगाराची केंद्रे काही मोजक्या शहरांमध्ये एकवटतात, तेव्हा ग्रामीण कामगारांसाठी स्थलांतर ही अपरिहार्यता बनते.

'शहरे खरंच सर्वसमावेशक आहेत का?' - याचा अनुभव कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात प्रकर्षाने समोर आला. या काळात शहरी गरीब, असंघटित आणि स्थलांतरित कामगारांची फरपट देशाने पाहिली. हजारो किलोमीटर पायी चालत आपल्या गावाकडे परतणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांचा लोंढा आजही आपल्या स्मरणात असेल. ज्या स्थलांतरित कामगारांनी शहरांच्या उभारणीत महत्त्वाची भूमिका बजावली, त्यांनाच आपत्तीच्या काळात शहरांनी परके ठरवले होते. या वास्तवाचा थेट संबंध ग्रामीण विकासाशी आणि गावांच्या 'स्मार्ट' असण्याशी आहे.

वाड्या, वस्त्या आणि गावांकडून शहरे व महानगरांकडे होणारे कामगारांचे स्थलांतर हे अनेकदा अनियोजित, हंगामी, तणावपूर्ण आणि विवशतेतून घडणारे असते. महाराष्ट्रात तर अशा स्थलांतरित कामगारांची संख्या देशात सर्वाधिक असल्याचे सरकारी आकडे सांगतात. चांगल्या रोजगाराचे आणि आर्थिक उन्नतीचे स्वप्न घेऊन शहरांकडे आलेले लाखो कामगार अखेरीस शहरी असंघटित क्षेत्रातील असुरक्षित, कमी वेतनाच्या आणि सामाजिक संरक्षणापासून वंचित रोजगारात अडकून पडतात. शहरे त्यांना काम देतात; पण सन्मान, सुरक्षितता आणि स्थैर्य देत नाहीत. दुसरीकडे, हे कामगार 'स्थलांतरित' असल्याने शहरांत त्यांना उपरेपणाचाही सामना करावा लागतो.

खरे तर, 'कामगारांचे स्थलांतर' हे आव्हान नाही; आव्हान आहे ते नाईलाजाने, विवशतेने आणि अनियोजितपणे होणाऱ्या स्थलांतराचे. नागरिकांनी अधिक चांगल्या संधी, कौशल्यविकास आणि आर्थिक प्रगतीसाठी जरूर स्थलांतर करावे; केवळ जिवंत राहण्यासाठी नव्हे. गावांमध्येच रोजगार, उद्योजकता, कौशल्यविकास, दर्जेदार शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि मूलभूत सुविधांचे सक्षम जाळे उभे राहिले, तर बहुतांश कामगारांसाठी स्थलांतर हा मजबुरीचा नव्हे, तर निवडीचा पर्याय ठरेल. म्हणूनच 'स्मार्ट व्हिलेज' ही केवळ ग्रामीण विकासाची आणखी एक योजना न ठरताअधिक समतोल, न्याय्य आणि सर्वसमावेशक विकसित भारत घडविण्याची विकासदृष्टी ठरली पाहिजे.

ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर 'स्मार्ट व्हिलेज' संकल्पना अधिक महत्त्वाची ठरते. बायोगॅस, इथेनॉल, सौरऊर्जा आणि कृषी-आधारित उद्योगांच्या माध्यमातून गावे ऊर्जा आणि रोजगाराची स्थानिक केंद्रे बनू शकतात. त्यामुळे ग्रामीण कामगारांसाठी गावातच रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. रोजगारासाठी शहरांवरील अवलंबित्व कमी झाल्यास तणावपूर्ण आणि अनियोजित स्थलांतराचे प्रमाणही घटू शकते.

'स्मार्ट व्हिलेज'ची संकल्पना यशस्वी करायची असेल, तर केवळ पायाभूत सुविधा पुरेशा नाहीत. ग्रामीण भागात कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, किमान वेतन, कौशल्यविकास आणि सन्मानजनक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणारी श्रमबाजार व्यवस्था विकसित करणे हे मोठे आव्हान असेल. महात्मा गांधींच्या ग्रामस्वराज्याच्या कल्पनेपासून ते अब्दुल कलामांच्या प्रोव्हायडिंग अर्बन फॅसिलिटी टू रूरल एरिया (पुरा) मॉडेलपर्यंत एक समान धागा दिसून येतो, तो म्हणजे भारताचा शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकास हा गावांना सक्षम, स्वयंपूर्ण आणि रोजगारक्षम बनवल्याशिवाय शक्य नाही.

rajputkdr@gmail.com

जगभर

वर्ल्ड सेंट्रल किचन-गाझात निम्माच स्वयंपाक!

युद्धस्य कथा रम्य- असं आपण नेहमीच म्हणतो. युद्धातला थरार, लष्करी कारवाया, त्यात होणारी जीवित आणि इतर हानी, राजकीय वार-पलटवार याबाबत नेहमी वाचायला मिळतं. पण या सगळ्याच्या मागे युद्धभूमीवर अनेक गोष्टी सुरू असतात. युद्धात विस्थापित झालेल्या, युद्धाची झळ बसलेल्या नागरिकांना मदत करण्यासाठी अनेक मानवतावादी संस्थाही मोठ्या प्रमाणात काम करत असतात. अशीच एक संस्था म्हणजे वर्ल्ड सेंट्रल किचन.

नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्तींमध्ये पोळलेल्या लोकांना दररोज गरम, ताजं आणि पौष्टिक जेवण मिळावं यासाठी ही संस्था २०१० पासून काम करते. मात्र, एका युद्धाची झळ जशी तिथल्या स्थानिक नागरिकांना बसते तशी ती उर्वरित जगालाही बसते, याचा अनुभव इराण-इस्रायल-अमेरिका युद्धाच्या निमित्ताने सगळेच घेत आहेत. इराण-इस्रायल-अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे संपूर्ण जग इंधन तुटवड्याचा सामना करत आहे. वर्ल्ड सेंट्रल किचनही त्याला अपवाद नाही. महाग झालेल्या इंधनामुळे यापुढे गाझामधील लोकांसाठी केलं जाणारं गरम जेवण निम्म्यावर आणायचा कठोर निर्णय या किचनने नुकताच घेतला आहे. या निर्णयामुळे गाझातील नागरिक दुःखात आहेत, युद्धामुळे आयुष्याची घडी विस्कटलेली असताना किमान दोन वेळचं गरम जेवण तरी आम्हाला विनासायास मिळत होतं, आता किचनने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आमच्यावर उपासमारीची वेळ येईल.. ते युद्धापेक्षा भयंकर असेल, असं गाझातील नागरिक म्हणत आहेत.

गाझात युद्ध सुरू झाल्यापासून वर्ल्ड सेंट्रल किचनकडून दररोज सुमारे एक कोटी लोकांसाठी गरम, ताजा, पौष्टिक स्वयंपाक केला जातो. या जेवणाची पाकिटं गरम असतानाच जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावीत यासाठी या किचनमध्ये काम करणारे कर्मचारी आणि स्वयंसेवक जिवाचं रान

करतात. मात्र, आता इंधनाचे भाव गगनाला भिडल्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर स्वयंपाक करणं परवडणारं नाही, त्यामुळे हे प्रमाण निम्म्यावर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

गाझातील लोकांची जेवणाची गरज अजिबात कमी झालेली नाही, उलट आमच्यासमोरील अडचणी आणि मर्यादांमुळे अक्षरशः मनावर दगड ठेवून हा निर्णय घेत आहोत, असं या किचनचे संस्थापक आणि अमेरिकन-स्पॅनिश शेफ जोस अँड्रेस यांनी नुकतंच स्पष्ट केलं आहे. २०१० मध्ये हैतीमध्ये झालेल्या महाप्रचंड भूकंपाची दृश्यं बातम्यांमध्ये पाहत असताना, आजारी लोकांसाठी डॉक्टर पोहोचवले जातात, मग उपासमारीने तळमळणाऱ्या लोकांसाठी त्यांना जेऊ घालणारे व्यावसायिक 'शेफ' का पाठवायचे नाहीत, या विचारातून जोस अँड्रोस आणि त्यांची पत्नी पॅट्रिशिया यांनी या किचनची स्थापना केली. त्यात व्यावसायिक शेफ्स आणि स्वयंसेवक यांची नियुक्ती करण्यात आली. भूकंप, महापुरासारख्या नैसर्गिक आपत्ती किंवा युद्धासारख्या मानवनिर्मित आपत्तीच्या काळात कसं काम करावं, मोठ्या प्रमाणात स्वयंपाक कसा करावा, तो जास्तीत जास्त गरजूंपर्यंत कमीत कमी वेळेत कसा पोहोचवावा याचं प्रशिक्षणही या सगळ्यांना दिलं जातं.

गाझा पट्टीत युद्ध सुरू झाल्यापासून वर्ल्ड सेंट्रल किचन तिथे जेवणाची सुमारे एक कोटी पाकिटं तयार करत आहे. आता वाढत्या महागाईमुळे ही संख्या ५० लाखांवर आणण्याचा निर्णय या किचनकडून घेण्यात आला आहे. एका बाजूला गाझातल्या नागरिकांना बॉम्बहल्ले आणि भूसुरुंगांपासून स्वतःला वाचवायचं आहेच, तर दुसरीकडे आता हाता-तोंडाची लढाईही लढायची आहे.

जनमन

कायद्यावरील विश्वास उडणे धोकादायक

आजच्या आधुनिक आणि वेगवान युगात विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि शिक्षणाच्या क्षेत्रात प्रगती होत असताना समाजात गुन्हेगारीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. चोऱ्या, दरोडे, खून, फसवणूक, सायबर गुन्हे, महिलांवरील अत्याचार, अमली पदार्थांची तस्करी यांसारख्या घटना समाजासाठी गंभीर चिंता निर्माण करत आहेत. वाढती गुन्हेगारी केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या नसून ती राज्याच्या विकासासाठी मोठा धोका ठरत आहे. गुन्हेगारी वाढण्यामागे अनेक कारणे आहेत. बेरोजगारी, गरिबी, व्यसनाधीनता, सामाजिक असमानता, शिक्षणाचा अभाव आणि नैतिक मूल्यांची घसरण ही त्यातील प्रमुख कारणे मानली जातात. काही युवक चुकीच्या संगतीत जाऊन गुन्हेगारीकडे वळतात. सोशल मीडियाचा गैरवापर आणि इंटरनेटद्वारे होणारे सायबर गुन्हेही वाढले आहेत. त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गुन्हेगारी वाढल्यामुळे समाजात भीती आणि असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण होते. उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणुकीवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. महिलांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मुक्तपणे वावरणे कठीण बनते. कायद्यावरील लोकांचा विश्वास कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो. ही समस्या रोखण्यासाठी शासन, पोलिस प्रशासन आणि समाज या तिन्ही घटकांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे. युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, व्यसनमुक्ती अभियान राबवणे, कठोर कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि नैतिक शिक्षणावर भर देणे गरजेचे आहे. पालकांनीही मुलांकडे लक्ष देऊन योग्य संस्कार करणे आवश्यक आहे.

- कैलास कोल्हे, गुरुपिंपरी, जि. जालना

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : **janman@lokmat.com**

पर्पजफुल

आयुष्यातला 'पर्पज' शोधायचा, म्हणजे नेमके काय करायचे?

'लाइफ'ची व्याख्या करणे अवघड; पण त्याचा सर्वात महत्त्वाचा गुणधर्म म्हणजे स्वत:ची प्रतिकृती भिन्नतेसह निर्माण करणे.

अमृत बंग
'निर्माण' या युवा उपक्रमाचे प्रमुख

'ऑन द वॉटरफ्रंट' चित्रपटात मार्लन ब्रांडोचा प्रसिद्ध डायलॉग आहे, "आय कुड हॅव बीन समबडी, चार्ली". एका युवकाचा दिशाहीन पद्धतीने चालू असलेला जीवनप्रवास, त्याला माहिती नसतानादेखील त्याचा उपयोग करून घेऊन स्थानिक गुंडांद्वारे एका व्यक्तीचा होणारा खून, नंतर एक फादर आणि नायकाची मैत्रीण यांच्यामुळे जागृत होणारी त्याची सद्सद्विवेकबुद्धी, स्वतःच्या मूल्यांविषयीची जाणीव व अन्यायाची चीड, यातून तो घेत असलेले निर्णय आणि त्यांचा परिणाम अशी चित्रपटाची कथा जाते.

चित्रपट तर सुंदर आहेच, पण सोबतच जगण्याला काही व्यापक अर्थ नसल्यास व असल्यास काय होतं हे देखील आपल्याला कळायला मदत होते. म्हणूनच सत्तर वर्षे झालीत तरीही हा डायलॉग यादगार आहे.

'पर्पजफूल लाइफ' कसे जगता येईल याची विस्तृत चर्चा पुढच्या काही लेखांत आपण करणार आहोत. त्यासाठी पर्पज म्हणजे नेमके काय हे जसे आपण समजून घेऊ तसेच 'लाइफ'बाबतचे वैज्ञानिक सत्य काय हे समजून घेणेही उपयुक्त राहील. आपल्या प्रत्येकाला आपापला 'पर्पज इन लाइफ' शोधायचा आहे. 'पर्पज ऑफ लाइफ' हा मात्र असा व्यक्तिपरत्वे भिन्न नाही. उत्क्रांती जीवशास्त्राच्या भाषेत असं म्हणता येईल की 'पर्पज ऑफ लाइफ इज टू सर्वाइव्ह अँड रिप्रोड्यूस', जगणे आणि पुनरुत्पादन करणे.

सुमारे ३.८ अब्ज वर्षांपूर्वी महासागराच्या तळाशी ज्वालामुखीच्या उघड्या छिद्रांमध्ये सुयोग्य वातावरण, तापमान व रासायनिक प्रक्रियेसाठी आवश्यक द्रव्ये मिळाल्यामुळे काही विशेष केमिस्ट्री घडली, त्या केमिस्ट्रीची बायलॉजीमध्ये परिणीती झाली आणि

म्हणून पृथ्वीवर लाइफची, जीवनाची सुरुवात झाली असे आपल्याला विज्ञान सांगते.

ही सुरुवात कदाचित अनेकवेळा झाली असेल; परंतु या विविध घटनांपैकी केवळ एकदाच जीवन टिकले आणि त्यानंतर सातत्याने टिकून राहिले. जीवनाची बेसिक केमिस्ट्री व प्रणाली आश्चर्यकारकपणे सारखी आहे. डीएनएचे मूळ स्वरूप सर्व प्रजातींमध्ये समान आहे; जेनेटिक कोडची अक्षरे व एन्क्रिप्शन समान आहे; रेणूंची अभिमुखतादेखील समान आहे. बॅक्टेरियामध्ये जे खरे आहे ते ब्लू व्हेलमध्ये खरे आहे. केवळ एकच उगम असलेली प्रणाली असे संवर्धन प्रदर्शित करू शकते.

लाइफची व्याख्या करणे अवघड आहे, तरीही त्याचा सर्वात महत्त्वाचा गुणधर्म म्हणजे 'सेल्फ रेप्लिकेशन विथ व्हेरिएशन', स्वत:ची प्रतिकृती भिन्नतेसह निर्माण करणे. आपण सगळेच आपापल्या पालकांची तंतोतंत कार्बनकॉपी नाही आहोत ही गोष्ट लाइफला एका स्फटिकापासून वेगळी करते, कारण एक क्रिस्टलदेखील स्वतःची कॉपी तयार करतो. वडिलोपार्जित स्वरूपापासून वेगळे वैविध्य प्राप्त होण्याची प्रवृत्ती ही सजीवांच्या यंत्रणेतच अंतर्भूत आहे. वारसा आणि विविधता या दोन पूरक प्रवृत्ती आहेत आणि जीवनाच्या अस्तित्वासाठी दोन्ही अपरिहार्य आहेत.

हे जसे डीएनएच्या पातळीवर आहे तसेच आपल्या जीवनाच्या स्वप्नांमध्ये, आपल्या निर्णयांमध्ये व जीवनशैलीतदेखील काय वेगळेपण आणता येईल? आपल्या कुटुंबातून मूल्यांचा व संस्कारांचा वारसा आपण जरूर घ्यावा, पण त्यासोबतच आपली करिअरची, जोडीदाराची निवड, इ. बाबतीत जर व्हेरिएशन केले नाही तर मात्र आपल्यामध्ये आणि अजीव अशा स्फटिकामध्ये फारसा काही फरक नाही. आपला पर्पज स्वतः शोधणे व पर्पजफूल लाइफ जगणे हे म्हणूनच आत्यंतिक महत्त्वाचे आहे; कारण त्यातूनच आपण 'लाइफ'ला आणि आपल्या सजीव असण्याला न्याय देऊ शकतो.

amrutabang@gmail.com

तिरकस आणि चौकस

गजानन घोंगडे

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८१८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०४१७८४
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५९३०, ०२२- ४७५०७९४६ ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न व्ह्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४१९०५, २५३८१७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय :** पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : ०२२ ४६०४१७८४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.)
'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

चिंतन

सरकार को परीक्षा तंत्र मजबूत करना ही होगा

देश के जेन जेड पर अपराधियों की बुरी नजर है। ये अपराधी येन-केन प्रकारेण युवाओं को भड़काना चाहते हैं। सीबीएसई, सीयूईटी-यूजी और नीट-यूजी जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है। इसमें सरकार को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह भी इन परीक्षाओं को लेकर पूरी तैयारी से बुरी तरह चूकी है। कुछ एथिकल हैकर्स ने कमियों को उजागर भी किया है। इसके बाद सतर्क सरकार ने सभी परीक्षाओं के लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। करोड़ों छात्र-छात्राएं हर वर्ष विभिन्न बोर्ड, प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से अपने भविष्य की दिशा तय करते हैं। ऐसे में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता केवल शैक्षणिक विषय नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय विकास का भी प्रश्न है। हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं को लेकर सामने आई गड़बड़ियों, पेपर लीक, तकनीकी बाधाओं और साइबर हमलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश के परीक्षा तंत्र को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी तथा तकनीकी रूप से और अधिक सक्षम बनाने की जरूरत है। सीबीएसई में 12वीं के री-इवैल्यूएशन (पुनर्मूल्यांकन) को लेकर सीबीएसई का पोर्टल सोमवार को शुरू नहीं हो पाया। कड़ी मशक्कत के बाद आईआईटी दिल्ली और कानपुर के साइबर एक्सपर्ट ने पूरे दिन मेहनत कर पोर्टल को मंगलवार को शुरू किया। काफी हैरानी की बात है कि पोर्टल के चालू होते ही इस पर 2 मिनट में ही 15 लाख एक्सेस अटेंप्ट हुए, जबकि 1 लाख से ज्यादा बार सिस्टम की फाइलों तक बिना अनुमति पहुंचने की कोशिश की गई। इस तरह के प्रयास बताते हैं कि कुछ बाहरी शक्तियां सीबीएसई के पोर्टल को चलने ही नहीं देना चाहती थी। यानी ये शक्तियां किसी भी तरह से जेन जेड को व्यवस्था के प्रति भड़काना चाहती हैं, ताकि युवा सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर जाएं और मोर्चा खोल दें। हाल ही में कथित तौर पर अमेरिका में बने एक इंटाग्राम ग्रुप के इरादे भी जग जाहिर हो चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा सीबीएसई में प्रशासनिक स्तर पर किए गए बदलाव और ओएसएम प्रक्रिया की जांच के लिए समिति का गठन जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम माना जा सकता है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि परीक्षा प्रणाली की संपूर्ण समीक्षा की जाए और तकनीकी, प्रशासनिक तथा कानूनी स्तर पर व्यापक सुधार लागू किए जाएं। सबसे पहले, सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षा संस्थाओं के लिए एक मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। नियमित सुरक्षा ऑडिट, एथिकल हैकिंग परीक्षण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी और डेटा सुरक्षा के आधुनिक उपाय अनिवार्य किए जाने चाहिए। दूसरा, परीक्षा संचालन से जुड़े प्रत्येक चरण में पारदर्शिता बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में तथ्य तुरंत सार्वजनिक किए जा सकें। तीसरा, पेपर लीक, साइबर हमले और परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। सरकार को गड़बड़ियों को हर हाल में रोकना होगा और परीक्षा तंत्र को मजबूत करना ही होगा, ताकि साल भर मेहनत कर रहे होनहारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा कोई मौका अपराधियों को न दें, जिससे परीक्षाओं की शुचिता पर सवाल उठे और सालभर मेहनत करने वाले युवाओं का सिस्टम से भरोसा उठे, इसलिए सरकार को पूरे परीक्षा तंत्र को मजबूत बनाना ही होगा।

विश्लेषण

राजेश जैन

बदलते भारत-नेपाल संबंधों की कहानी

भारत और नेपाल का रिश्ता सबसे अनोखा, जटिल और सबसे भावनात्मक रिश्तों में से एक माना जाता है। दुनिया में बहुत कम ऐसे पड़ोसी देश हैं, जिनके बीच सीमाएं भी खुली हों और समाज भी इतने गहरे स्तर पर जुड़े हों।भारत–नेपाल संबंधों की आधुनिक संरचना काफी हद तक 1950 की भारत–नेपाल शांति और मैत्री संधि पर आधारित है। इस संधि का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग, व्यापार और नागरिक आवाजाही को आसान बनाना था। भारत अपनी सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता। चीन इस पूरे समीकरण में अपनी जगह मजबूत करना चाहता है। ऐसे में दोनों देशों को संवाद और विश्वास आधारित संबंधों की नई संरचना विकसित करनी होगी।

दक्षिण एशिया की राजनीति में भारत और नेपाल का रिश्ता सबसे अनोखा, जटिल और सबसे भावनात्मक रिश्तों में से एक माना जाता है। दुनिया में बहुत कम ऐसे पड़ोसी देश हैं, जिनके बीच सीमाएं भी खुली हों और समाज भी इतने गहरे स्तर पर जुड़े हों। भारत और नेपाल का संबंध केवल दो सरकारों का संबंध नहीं है; यह सदियों से साझा संस्कृति, धर्म, भाषा, व्यापार, परंपराओं और मानवीय रिश्तों का जीवंत उदाहरण रहा है, लेकिन यही रिश्ता समय-समय पर अविश्वास, राष्ट्रवाद, सीमा विवाद और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की वजह से तनावपूर्ण भी हो जाता है। हाल के दिनों में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के एक बयान ने फिर यही सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर भारत-नेपाल संबंध बार-बार सीमा विवाद और राजनीतिक असहजता के मोड़ पर क्यों पहुंच जाते हैं। बालेन शाह ने नेपाली संसद में कहा कि सिर्फ भारत ने ही नेपाली भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया, बल्कि नेपाल ने भी कुछ भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रखा है। इस बयान के बाद नेपाल की संसद में हंगामा मच गया। विपक्ष ने उनसे सबूत मांगे, विदेश मंत्रालय को सफाई जारी करनी पड़ी और सोशल मीडिया पर तीखी बहस शुरू हो गई। पहली नजर में यह एक सामान्य राजनीतिक बयान लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह उस गहरे बदलाव का संकेत है जो पिछले कुछ वर्षों में भारत-नेपाल संबंधों में दिखाई दे रहा है। यह केवल सीमा विवाद का मामला नहीं है। इसके पीछे राष्ट्रवाद, भू-राजनीति, चीन की बढ़ती भूमिका, नेपाल की नई राजनीतिक सोच और भारत की पारंपरिक पड़ोसी नीति से जुड़ी कई परतें मौजूद हैं। भारत और नेपाल का रिश्ता आधुनिक सीमाओं से कहीं पुराना है। नेपाल के लाखों नागरिक भारत में शिक्षा प्राप्त करते हैं, रोजगार करते हैं और व्यापार से जुड़े हैं। भारतीय शहरों में नेपाली समुदाय सहज रूप से घुला-मिला दिखाई देता है।

भारत की सेना में गोरखा रेजिमेंट का गौरवपूर्ण इतिहास दोनों देशों के भरोसे और साझेदारी का प्रतीक रहा है। खुली सीमा ने इस रिश्ते को और विशेष बनाया है। दुनिया के अधिकांश देशों के विपरीत भारत और नेपाल के नागरिक बिना वीजा और पासपोर्ट के एक-दूसरे के यहां आ-जा सकते हैं। यही वजह है कि भारत-नेपाल संबंध केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक संबंध भी हैं। राजनीतिक तनाव पैदा हो सकते हैं, लेकिन जनता के स्तर पर अपनापन अक्सर बना रहता है। भारत-नेपाल संबंधों की आधुनिक संरचना काफी हद तक 1950 की भारत-नेपाल शांति और मैत्री संधि पर आधारित है। इस संधि का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग, व्यापार और नागरिक आवाजाही को आसान बनाना था। उस समय चीन में कम्युनिस्ट क्रांति और हिमालयी क्षेत्र की बदलती भू-राजनीति को देखते हुए भारत नेपाल को अपनी सुरक्षा नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानता था। इस संधि ने नेपाल को भारत के साथ विशेष आर्थिक और सुरक्षा संबंध दिए। व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़े। लेकिन समय के साथ नेपाल में यह धारणा मजबूत होने लगी कि यह संधि बराबरी के आधार पर नहीं बनी थी। नेपाल के कई राजनीतिक दल और बुद्धिजीवी इसे "असमान संधि" बताते रहे हैं। भारत इस संधि को सुरक्षा और रणनीतिक

सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मानता है, जबकि नेपाल इसे अपनी संप्रभुता और स्वतंत्र विदेश नीति से जोड़कर देखता है। यही कारण है कि संधि की पुनर्समीक्षा की मांग समय-समय पर उठती रहती है। भारत और नेपाल के बीच सबसे संवेदनशील मुद्दा सीमा विवाद का है। कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और सुस्ता जैसे क्षेत्रों को लेकर दोनों देशों के दावे अलग-अलग हैं। यह विवाद 2020 में सबसे ज्यादा उभरा, जब भारत ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया। इसके जवाब में नेपाल ने संविधान संशोधन कर नया नक्शा पारित किया, जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। नेपाल में इसे राष्ट्रीय अस्मिता का मुद्दा बना दिया गया। सड़कों पर प्रदर्शन हुए और भारत विरोधी भावना तेज हो गई। भारत इन क्षेत्रों को अपनी रणनीतिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि ये चीन सीमा के बेहद करीब स्थित हैं। बालेन शाह का हालिया बयान भी इसी राजनीतिक वातावरण की उपज माना जा रहा है। उन्होंने ब्रिटेन की संभावित भूमिका का जिक्र कर नया विवाद खड़ा कर दिया। भारत हमेशा सीमा विवादों को द्विपक्षीय तरीके से सुलझाने की नीति पर कायम रहा है, इसलिए नेपाल की ओर से तीसरे पक्ष का संकेत नई दिल्ली के लिए असहज करने वाला था। भारत-नेपाल संबंधों को अब चीन के बिना समझना संभव नहीं है। पिछले एक दशक में चीन ने नेपाल में तेजी से अपना प्रभाव बढ़ाया है। सड़क, रेल, हाइड्रोपावर और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में चीन का निवेश लगातार बढ़ रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत नेपाल को चीन एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है। वह चीन के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंध बढ़ाकर भारत के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। नेपाल की राजनीति में भी चीन की भूमिका पहले से कहीं अधिक सक्रिय दिखाई देती है। भारत के लिए यह स्थिति चिंता का विषय है। नई दिल्ली हमेशा नेपाल को अपनी उत्तरी सुरक्षा नीति का अहम हिस्सा मानती रही है। खुली सीमा और हिमालयी भूगोल के कारण भारत नहीं चाहता कि कोई बाहरी शक्ति नेपाल में अत्यधिक प्रभाव स्थापित करे। भारत-नेपाल संबंधों में 2015 का वर्ष एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। नेपाल ने नया संविधान लागू किया, जिसका मधेशी समुदाय ने विरोध किया। मधेश आंदोलन के दौरान भारत-नेपाल सीमा पर आपूर्ति बाधित हो गई। नेपाल में यह धारणा बनी कि भारत ने "अनौपचारिक नाकेबंदी" की है।

हालांकि भारत ने हमेशा कहा कि यह समस्या सीमा पर चल रहे आंदोलन की वजह से थी, लेकिन नेपाल में भारत विरोधी भावना तेजी से बढ़ी। दूसरी ओर सुरक्षा चुनौतियां भी कम नहीं हैं। खुली सीमा अवसर भी देती है और जोखिम भी पैदा करती है। नकली मुद्रा, तस्करी, मानव तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों के लिए सीमा के दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है। दोनों देशों के बीच खुफिया सहयोग और सुरक्षा समन्वय लंबे समय से चलता रहा है, लेकिन राजनीतिक अविश्वास कई बार इस सहयोग को प्रभावित करता है। दोनों को यह समझना होगा कि 21वीं सदी की राजनीति केवल ऐतिहासिक निकटता के भरोसे नहीं चल सकती। नेपाल बराबरी और सम्मान चाहता है। भारत अपनी सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता। चीन इस पूरे समीकरण में अपनी जगह मजबूत करना चाहता है। ऐसे में दोनों देशों को संवाद और विश्वास आधारित संबंधों की नई संरचना विकसित करनी होगी। 1950 की संधि की पुनर्समीक्षा पर खुली बातचीत हो सकती है। सीमा विवादों के समाधान के लिए स्थायी तंत्र बनाया जा सकता है। शिक्षा, डिजिटल तकनीक, ऊर्जा और युवा सहयोग को नई प्राथमिकता दी जा सकती है।

(लेखक प्रसिद्ध लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

विश्व साइकिल दिवस

डॉ. मोनिका शर्मा

पर्यावरण-स्वास्थ्य संकट के दौर में बढ़ा साइकिल का महत्व

आज विश्व साइकिल दिवस है। हर वर्ष 3 जून को मनाया जाने वाला यह खास दिन साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने वाली जन-जागरूकता लाने से जुड़ा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2018 में पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के साइकिल के इस्तेमाल को रेखांकित करने हेतु यह घोषित किया गया था। वहीं 2022 में टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए साइकिलों को सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के एक अभिन्न अंग के तौर पर शामिल किया गया। तकलीफदेह है कि इन्सानों और पर्यावरण, दोनों स्वस्थ रखने वाली साइकिल, सुविधाजनक जीवनशैली की चाह में आम जीवन से दूर हो गई है। जबकि परिवहन के इस सरल, किफायती और स्वच्छ साधन से दूर होना प्रकृति और इंसानी मन-जीवन दोनों पर भारी पड़ रहा है। यही वजह है कि यह दिन वैश्विक स्तर पर लोगों को दैनिक यात्रा में प्रदूषण घटाने और सक्रिय जीवन शैली के लिए साइकिल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विचारणीय है कि आज देश और दुनिया में छाये ऊर्जा संकट के बीच साइकिल की सवारी बेहद अहम हो गई है। इतना ही नहीं, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार करने वाली साइकिल बढ़ती व्याधियों के चलते भी उपयोगी हो चली है। साथ ही पर्यावरण के मोर्चे पर दमघोटू होती हवा, ट्रैफिक जाम और पर्यावरण असंतुलन से तापमान और ठंड में असहनीय बढ़ोतरी को देखते हुए साइकिल सवासरी की ओर फिर लौटना आवश्यक है। ध्यातव्य है कि विश्व साइकिल दिवस 2026 का विषय भी 'हरियाली भरे भविष्य के लिए साइकिल चलाना' है। यह विषय पर्यावरण संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और सतत परिवहन को बढ़ावा देने में साइकिल की भूमिका पर केंद्रित है। लाजिमी भी है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी जीवन का जोखिम बनने वाली समस्याओं का व्यावहारिक समाधान साइकिल का उपयोग करना ही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए लाभकारी साइकिल चलाने को महत्वपूर्ण माना जाता है। डब्लूएचओ शारीरिक गतिविधि बढ़ाने, कैंसर और मधुमेह जैसी गैर-संचारी बीमारियों को कम करने और वायु- ध्वनि प्रदूषण घटाने के लिए साइकिल के उपयोग बढ़ावा देता है। साइकिलिंग को शिक्षा, ऊर्जा, रोजगार, शहरों और असमानताओं सहित कई सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि के सूत्रधार के रूप में मान्यता भी देता है। असल में स्वास्थ्य से जुड़ी चिंतनीय स्थितियों के बीच साइकिल का उपयोग बहुत मददगार साबित हो सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मोटापे से ग्रस्त आबादी के आंकड़े बढ़ रहे हैं।वर्ष 2023-24 में 30.7 प्रतिशत महिलाएं और 27.3 प्रतिशत पुरुष मोटापे से ग्रस्त पाए गए हैं।सर्वेक्षण में सामने आया है कि वयस्कों में शरीर का वजन ही नहीं, ब्लड शुगर भी बढ़ रहा है। समझना कठिन नहीं शारीरिक निष्क्रियता इसका अहम कारण है।

परंपरागत जीवनशैली वाले भारतीय समाज में साइकिल बच्चों की प्यारी और पसंदीदा सवारी रही है। बदलती जीवनशैली के चलते बच्चे भी इससे दूर हुए हैं। इसी के चलते कम उम्र में ही मोटापा घेर रहा है। इस मामले में वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस-2026 की रिपोर्ट भी चेताने वाली है। रिपोर्ट में बच्चों में मोटापे के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर चुनौती बना मोटापा बच्चों में डायबिटीज, हृदय रोग और दूसरी जानलेवा व्याधियों का जोखिम बढ़ा रहा है। विचारणीय हैं कि ऊर्जा संकट से निपटने के लिए भी नागरिकों को साइकिल की सवारी को प्राथमिकता देनी चाहिए। साइकिल का उपयोग ऊर्जा संकट का तो सबसे प्रभावी हल है। यह सीधे-सीधे पेट्रोल, डीजल और बिजली पर निर्भरता को कम करता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है। पैदल चलने और साइकिल चलाने जैसी गतिविधियां संयुक्त रूप से 2034 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को लगभग 37 प्रतिशत तक कम करने की क्षमता रखती है। ऐसे में साइकिल का इस्तेमाल वायु गुणवत्ता में सुधार, पर्यावरण संरक्षण और आथिक बेहतरी से भी जुड़ा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के आंकड़ों के अनुसार, देश के लगभग 55 प्रतिशत भारतीय घरों में साइकिल मौजूद होने के बावजूद इसके इस्तेमाल के प्रति उदासीनता का भाव है। आवश्यक है कि यह दिन साइकिल रेलियों, दिवस विशेष से जुड़े आयोजनों और जन-जागरूकता अभियानों तक ही ना सिमटे। आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और प्रकृति की बेहतरी से जुड़ी साइकिल की सवारी को आम जीवन में जगह दें।

(लेखिका स्वतंत्र स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

मंदिर जैसे उपासना स्थल क्यों बनाए जाते हैं?

संकलित

दर्शन

जब ईश्वर का वास हृदय में माना गया है, तो मंदिर जैसे उपासना स्थल क्यों बनाए जाते हैं? मंदिरों की स्थापना के पीछे उद्देश्य था कि पूजा, अर्चना और यज्ञ आदि द्वारा पवित्र तन्मात्रओं यानी पंचभूतों के सूक्ष्म रूप की सृष्टि की जाए। किसी साधु हृदय व्यक्ति को पूजा का कार्यभार सौंपा जाए। स्थान का मन पर अदृश्य प्रभाव पड़ता है। चिकित्सालय में व्यक्ति को हर तरफ रोग और रोगी ही दिखते हैं। स्वस्थ व्यक्ति भी वहां अशक्त महसूस करने लगता है। हमारे शरीर से प्रतिदिन शुभ या अशुभ अदृश्य सूक्ष्म शक्ति-राशि का उत्सर्जन होता रहता है। मंदिर जाने वाला व्यक्ति काम, क्रोध और आलस्य बाहर छोड़कर ईश्वर के प्रति भक्तिभाव से जाता है। यह सामूहिक भक्ति या उपासना शुभ तन्मात्रओं व तरंगों का सृजन करती है। अतः यहां आगमन दुर्बल मन वाले मनुष्यों में ऊर्जा का संचार करता है। सज्जनों से ही प्रार्थना स्थलों की पवित्रता बनी रहती है। यदि मंदिर में असाधु व्यक्तियों का आवागमन बढ़ जाए तो स्थान अपनी पवित्रता खोने लगता है। पवित्र श्रवण मास में शिवलिंग पर दुग्ध, बेलपत्र, फल-फूल आदि चढ़ाकर पुण्य अर्जित करने की होड़ लगी रहती है। यदि ईश्वर है और वह हमारी प्रार्थना से प्रसन्न होता है तो वह एक बेलपत्र, अंजुली भर दूध या एक पुष्प से भी प्रसन्न हो जाएगा। सावन के महीने से इतर भी ये दृश्य आमतौर पर मंदिरों में आम होते हैं। यदि यह व्यवस्था सुचारु न हो तो अव्यवस्था स्वाभाविक है। इसी कारण कई मंदिरों में व्यक्तिगत रूप से भोग-अर्पण की मनाही है।

संस्कार क्या है?

संकलित

प्रेरणा

एक राजा के पास सुन्दर घोड़ी थी। कई बार युद्ध में इस घोड़ी ने राजा के प्राण बचाये और घोड़ी राजा के लिए पूरी वफादार थी। कुछ दिनों के बाद इस घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया, बच्चा काना पैदा हुआ, पर शरीर हष्ट पुष्ट व सुडौल था। बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे ने माँ से पूछा- मां मैं बहुत बलवान हूं, पर काना हूँ, यह कैसे हो गया? इस पर घोड़ी बोली- बेटा जब में गर्भवती थी, तू पेट में था तब राजा ने मेरे ऊपर सवारी करते समय मुझे एक कोड़ा मार दिया, जिसके कारण तू काना हो गया। यह बात सुनकर बच्चे को राजा पर गुस्सा आया और मां से बोला- मां मैं इसका बदला लूंगा। मां ने कहा राजा ने हमारा पालन-पोषण किया है, तू जो स्वस्थ है, सुन्दर है, उसी के पोषण से तो है, यदि राजा को एक बार गुस्सा आ गया तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उसे क्षति पहुंचाए, पर उस बच्चे के समझ में कुछ नहीं आया, उसने मन ही मन राजा से बदला लेने की सोच ली। एक दिन यह मौका घोड़े को मिल गया राजा उसे युद्ध पर ले गया। युद्ध लड़ते-लड़ते राजा एक जगह घायल हो गया, घोड़ा उसे तुरन्त उठाकर वापस महल ले आया। इस पर घोड़े को ताज्जुब हुआ और माँ से पूछा- मां आज राजा से बदला लेने का अच्छा मौका था, पर युद्ध के मैदान में बदला लेने का ख्याल ही नहीं आया और न ही ले पाया, मन ने गवारा नहीं किया। इस पर घोडी हंस कर बोली- बेटा तेरे खून में और तेरे संस्कार में धोखा है ही नहीं, तू जानकर तो धोखा दे ही नहीं सकता है। तुझ से नमक हरामी हो नहीं सकती, क्योंकि तेरी नस्ल में तेरी मां का ही तो अंश है।

अंतर्मन

आज की पाती

टीबी अब लाइलाज बीमारी नहीं

एक समय था जब टीबी यानी क्षय रोग का नाम सुनते ही मरीज और उसके परिवार में डर का माहौल बन जाता था। लोगों को लगता था कि यह बीमारी जीवन भर पीछा नहीं छोड़ेगी और इसका इलाज संभव नहीं है। जानकारी की कमी और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण अनेक मरीज समय पर उपचार नहीं ले पाते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चिकित्सा विज्ञान ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आज टीबी का प्रभावी इलाज उपलब्ध है और लाखों मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर सामान्य जीवन जी रहे हैं। यही कारण है कि अब टीबी को लाइलाज बीमारी नहीं माना जाता, बल्कि समय पर पहचान और नियमित उपचार से इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। – *कांतिलाल मांडोत, सूरत*

ट्रेंड

'वंदे भारत' ट्रेन

आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का प्रतीक बन चुकी स्वदेशी 'वंदे भारत' ट्रेन, जो सुरक्षित और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, देश के विकास की एक जीवंत तस्वीर पेश करती है।
-**जगत प्रकाश नड्डा,** केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

अग्निवीर योजना

केंद्र सरकार द्वारा भारतीय सेना में अग्निवीर योजना लागू किए जाने से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सीमित हो गए हैं। अग्निवीर योजना के कारण कई युवाओं के सपने और आकांक्षाएं आहत हुई हैं, जिससे उनमें निराशा का माहौल पैदा हो गया है।
-**सुखविंदर सिंह सुक्खू,** सीएम, हिमाचल प्रदेश

कानून-व्यवस्था का पतन

पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एशियाई खेलों के लिए चयनित पैरा एथलीट विराग त्यागी की हत्या, राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल की हत्या, सूर्य चौहान और एक दूध व्यापारी की हत्या उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था के पतन का प्रतीक है।
-**अखिलेश यादव,** सांसद, सपा

झारखंड शराब घोटाला

झारखंड शराब घोटाला महज भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों के संरक्षण में चलाया जा रहा एक संगठित आर्थिक अपराध है। शराब माफियाओं और सत्ता में बैठे लोगों के करीबी लोगों की मिलीभगत से जनता की कमाई को खुलेआम लूटा गया।
-**बाबूलाल मरांडी,** पूर्व सीएम, झारखंड

करंट अफेयर

अफगान में महिला शिक्षाविदों का भविष्य अंधकारमय

कल्पना कीजिए कि आपने अपना करियर बनाने में दशकों लगा दिए हैं। आपके पास मास्टर डिग्री है। आपने सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाया है। आप हर सुबह उद्देश्य और उत्साह के साथ अपने कार्यस्थल पहुंचती हैं। फिर रातोंरात आपके लिए संस्थान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। आपको बता दिया जाता है कि अब आप वापस नहीं आ सकतीं। ऐसा किसी गलती की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि आप एक महिला हैं। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद पूरे अफगानिस्तान में महिला शिक्षाविदों के साथ यही हुआ। हमने 12 अफगान महिला शिक्षाविदों से बातचीत की। इनमें से आठ उस समय अफगानिस्तान में थीं, जबकि चार हाल ही में देश छोड़ चुकी थीं। जो महिलाएं अफगानिस्तान में थीं, उनमें से केवल एक ही बाद में देश छोड़ने में सफल हुई। बाकी सभी अब भी वहीं हैं। उन्होंने जो कुछ हमें बताया, वह बेहद पीड़ादायक था। जब तालिबान ने 1996 से 2001 के बीच पहली बार अफगानिस्तान पर शासन किया था, तब महिलाओं को शिक्षा और कई प्रकार के रोजगार से वंचित कर दिया गया था। अमेरिका के नेतृत्व वाले हस्तक्षेप के बाद स्थिति धीरे-धीरे सुधरी।

ऑफ बीट

लाफिंग गैस के निरंतर उपयोग से मौत संभव

अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन अमेरिकी नागरिकों को मनोरंजन के लिए नाइट्रस ऑक्साइड उत्पादों के लगातार बढ़ते और संभावित रूप से घातक उपयोग के बारे में चेतावनी दे रहा है, विशेष रूप से युवाओं के बीच। नाइट्रस ऑक्साइड को आमतौर पर लाफिंग गैस कहा जाता है। 'गैलेक्सी गैस' और 'मियामी मैजिक' जैसे नामों से बेचे जाने वाले ये उत्पाद सस्ते हैं और गैस स्टेशन, बड़े किराना स्टोर और वॉलमार्ट सहित प्रमुख खुदरा दुकानों पर आसानी से उपलब्ध हैं। इन्हें ऑनलाइन भी बेचा जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य मामलों के सहायक प्रोफेसर के रूप में इन उत्पादों का अध्ययन करने के चलते मैं जानता हूं कि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। लाफिंग गैस का मनोरंजन के लिये या अन्य वजहों से निरंतर उपयोग कई प्रकार की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, और कुछ मामलों में मृत्यु भी हो सकती है। संभावित नुकसान की एक लंबी सूची- लाफिंग गैस के बार-बार इस्तेमाल से होने वाले गंभीर दुष्प्रभावों की सूची लंबी है। इसमें स्मृति हानि, मतिभ्रम, सिरदर्द, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन, रक्त के थक्के, अंगों की कमजोरी, चलने में परेशानी, आंत्र या मूत्राशय की समस्या, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या और मस्तिष्क क्षति शामिल हैं।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

हताश होते ट्रंप

लेबनान पर इजरायली हमलों के कारण ईरान द्वारा शांति-वार्ता रोके जाने से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खफा होना स्वाभाविक है। एक अमेरिकी न्यूज वेबसाइट ने दावा किया है कि ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कड़ी फटकार लगाई है। वेबसाइट की मानें, तो ट्रंप ने नेतन्याहू को यह तक कह डाला कि 'अगर मैं न होता, तो आप जेल में होते। मैं आपकी जान बचा रहा हूं। आपकी हरकतों के कारण हर कोई आपसे और इजरायल से नफरत करने लगा है।' इस दावे की सत्यता को परखे बिना कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के मिजाज और ईरान की जंग में उनके पास बचे विकल्पों को देखते हुए यह अतिरंजित खबर नहीं लगती। यह तथ्य है कि संघर्ष-विराम बढ़ाने का एकतरफा एलान वाशिंगटन ने किया है। यह भी सच है कि तमाम अमेरिकी सर्वेक्षण ईरान युद्ध के बाद देश में ट्रंप की लोकप्रियता में रिकॉर्ड गिरावट दिखा रहे हैं, जबकि कुछ ही महीनों में वहां मध्यावधि चुनाव होने हैं। उधर होर्मुज से ऊर्जा आपूर्ति के बाधित होने से पश्चिम एशिया में मित्र देश ट्रंप प्रशासन से नाखुश हैं। कई रिपब्लिकन सांसदों ने भी ट्रंप की नीतियों का विरोध किया है। ऐसे में, लेबनान में नेतन्याहू की कार्रवाइयां उनकी मुसीबत बढ़ाती जा रही हैं।

हालांकि, इस युद्ध में एक महाज सूचनाओं का भी है। अमेरिका और ईरान, दोनों तरफ से ऐसी बातें उछाली जा रही हैं, जिससे दूसरे खेमे का सिराजा बिखरता दिखाई पड़े। अभी चंद रोज पहले ईरानी मीडिया के सूत्रों के हवाले से एक खबर ने विश्व मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी कि ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स (आईआरजीसी) के कट्टरपंथी खेमे की बढ़ती दखलंदाजी से नाराज सदर पेजेशकियान ने सर्वोच्च नेता को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और कट्टरपंथी फौजी खेमे ने सत्ता हथिया ली है। कुछ घंटों में ही ईरानी राष्ट्रपति कार्यालय से इसका खंडन भी आ गया। यह बात इसलिए विश्व मीडिया को विश्वसनीय लगी, क्योंकि इस वक्त ईरान के अंदरूनी सियासी हालात साफ नहीं हैं और कई बार तेहरान के बयान और आईआरजीसी की कार्रवाई में तालमेल का अभाव साफ दिखा। अमेरिका-ईरान शांति-वार्ता की एक मुश्किल वहां किसी फैसले को सर्वमान्य बनाना भी है। इस सूरते-हाल का स्वाभाविक ही नेतन्याहू पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, इसीलिए वह ईरान समर्थित हिज्बुल्ला के ठिकानों को लगातार निशाना बना रहे हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप वैसे भी अपने बड़बोलेपन से सुर्खियां बटोरते रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू पर उनके कथित नाराजगी भरे बोल से उनकी हताशा ही झलकती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति वैसे भी अपने बड़बोलेपन से रोज-रोज सुर्खियां बटोरते रहे हैं, लेकिन ईरान युद्ध ने उन्हें गहरे एहसास कराया है कि जंग जुबान से नहीं जीती जा सकती और अब हताशा के उद्गार सामने आने लगे हैं। निस्संदेह, इस जंग ने ईरान का बहुत आर्थिक नुकसान किया है, मगर अमेरिका ने कुछ कम क्षति नहीं उठाई है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण वह सामरिक-आर्थिक नुकसान को फिर भी झेल लेगा, मगर अवधारणाओं की जंग में वह फिलहाल शिकस्त खाता हुआ दिख रहा है। दुनिया में सर्वशक्तिमान होने की उसकी छवि को इस युद्ध ने ऐसे गहरे जख्म दिए हैं, जिनका भरना आसान नहीं होगा। ट्रंप प्रशासन अगर वाकई चाहता है कि पश्चिम एशिया में स्थायी शांति हो, तो उसे नेतन्याहू की महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगानी ही पड़ेगी, वरना हर बीतते दिन के साथ राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में कमजोर पड़ते जाएंगे। यूरोप के साथी देश पहले ही उनसे दूर जा रहे हैं, पश्चिम एशिया में भी अमेरिकी कूटनीति को गंभीर क्षति पहुंच सकती है।

बदलाव और बदला से गुजरता बंगाल

इतिहास यही बताता है कि बंगाल में सरकार जल्दी नहीं बदलती, लेकिन जो भी पार्टी सत्ता में आती है, वह सबसे पहले विपक्ष की जड़ें साफ करने में जुट जाती है।

प्रभाकर मणि तिवारी | वरिष्ठ पत्रकार

पश्चिम बंगाल के हालिया विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 'बदला नहीं बदलाव' का नारा दिया था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली उसकी सरकार के शुरुआती 25 दिनों के कार्यकाल के दौरान 'बदला' भी नजर आ रहा है और 'बदलाव' भी। भ्रष्टाचार के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के दर्जनों नेताओं की गिरफ्तारी और कई नेताओं के साथ विभिन्न हिस्सों में हुई मारपीट को 'बदले' के तौर पर देखा जा रहा है, तो असंतोष और बगावत से जूझ रही तृणमूल कांग्रेस की परिस्थिति को बदलाव के तौर पर।

बदलाव की यह झलक शुभेंदु मंत्रिमंडल के विस्तार में भी नजर आती है। सोमवार को भाजपा के जिन 35 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, उनमें पूर्व पत्रकार, पूर्व क्रिकेटर से लेकर घरेलू सहायिका तक शामिल हैं। पार्टी ने इस विस्तार में राज्य के तमाम इलाकों और समाज के तमाम वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। इसके अलावा, चुनावी संकल्प-पत्र के वायदों के मुताबिक, महिलाओं को तीन हजार मासिक देने वाली अन्नपूर्णा योजना और सरकारी बसों में उनकी मुफ्त यात्रा के फैसले पहली जून से ही लागू कर दिए गए हैं। सरकार ने साल 2024 में सुर्खियां बटोरने वाले कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल कांड की नए सिरे से जांच कराने का भी फैसला किया है। भाजपा ने आरजी कर पीड़िता की मां को अपना उम्मीदवार बनाया था, जो चुनाव तो जीत गई हैं, लेकिन उनको फिलहाल मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है।

हालांकि, चुनाव नतीजों के बाद राज्य भर में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों में तोड़-फोड़ व आगजनी हुई और पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, उससे कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हिंसा के लिए सीधे भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। राजनीतिक हलकों में भी सवाल उठ रहा है कि आखिर तृणमूल कांग्रेस पर हिंसा के आरोप लगाने वाली पार्टी सत्ता में आने के बाद खुद उसी राह पर क्यों चल पड़ी है?

वैसे, यह हिंसा अभी तृणमूल की चिंता का विषय नहीं है। यहां चुनावी हिंसा का दशकों पुराना इतिहास रहा है। दिक्कत यह है कि लगातार पंद्रह साल तक राज करने वाली यह पार्टी सत्ता हाथ से निकलते ही बिखरती हुई नजर आ रही है। चुनावी नतीजों के बाद से ही पार्टी के नेताओं में इस्तीफे देने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह थमता हुआ नहीं नजर आ रहा। ऐसे नेताओं में नगरपालिका और पंचायत स्तर के नेताओं के साथ ही शांतनु सेन जैसे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी शामिल हैं। इसके साथ ही बागी नेताओं की सूची भी लगातार लंबी होती जा रही है।

यही नहीं, ममता बनर्जी ने पार्टी की भावी रणनीति व आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए अपने आवास पर पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन 80 में महज 19 विधायक ही वहां पहुंचे। नतीजतन बैठक रद्द करनी पड़ी। ममता ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए धरने का अपना पारंपरिक हथियार भी अपनाया है। पार्टी को एकजुट रखने की कवायद के तहत उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लंबे बयान दिए हैं।

इस बीच, पार्टी फर्जी हस्ताक्षर घोटाले में भी फंस गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में शोभनदेव चट्टोपाध्याय के चयन के समर्थन वाले तृणमूल विधायकों के पत्र में कथित तौर पर कुछ विधायकों के हस्ताक्षर फर्जी होने का आरोप है। कई विधायकों के हस्ताक्षर संदिग्ध होने और उपस्थित न होने के बावजूद पत्र में उनके नाम होने के कारण विधानसभा सचिवालय ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले की जांच अब सीआईडी कर रही है।

जाहिर है, फिलहाल ममता अपने राजनीतिक जीवन की सबसे कठिन चुनौती से जूझ रही हैं। किसी दौर में उन्होंने अकेले अपने बूते कांग्रेस से नाता तोड़कर नई पार्टी बनाई थी और सिंगूर व नंदीग्राम जैसे आंदोलनों की लहर पर सवार होकर महज तेरह साल के भीतर ही वाम मोर्चा का 34 साल से जमा-जमाया राज छीन लिया था, किंतु अब सत्ता हाथ से निकलते ही उनके सामने पार्टी को एकजुट रखने की गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की दलील है कि तृणमूल कांग्रेस ने सरकार में रहते जो कुछ बोया था, उसकी ही फसल काट रही है। अब उसकी हिंसा व भ्रष्टाचार से त्रस्त आम लोग उसके नेताओं को निशाना बना रहे हैं।

भाजपा सरकार के सत्ता संभालने के बाद उसके पहले पच्चीस दिनों के दौरान बंगाल की जमीनी परिस्थिति में कितना बदलाव आया है? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पार्टी ने अपने कुछ चुनावी वायदों को लागू किया है और कुछ को लागू करने की दिशा में पहल की है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ उसका अभियान भी जारी है। तृणमूल कांग्रेस के दर्जनों नेताओं की गिरफ्तारी हुई है और उनसे करोड़ों की रकम बरामद की गई है। फिलहाल, सरकार अपने वायदों को लागू करने की कोशिश करती नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष के सांसदों से मारपीट जैसी घटनाएं उसे कठघरे में खड़ा कर रही हैं, इसलिए हिंसा रोकना उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए।

भाजपा के कुछ नेताओं का दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के एक-तिहाई से भी ज्यादा विधायक पाला बदलकर भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठे हैं, पर अभी पार्टी ने उनके लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं। इसकी वजह यह है कि ऐसा करने पर आम लोगों में गलत संदेश जा सकता है। पहले दागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद शीर्ष नेतृत्व की सलाह पर आगे कोई फैसला किया जाएगा।

बंगाल के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें, तो यहां सरकारें बहुत जल्दी नहीं बदलतीं। इतना ही नहीं, इतिहास यह भी कहता है कि कोई पार्टी सत्ता में आने के बाद सबसे पहले विपक्ष की जड़ें साफ करने में जुट जाती है। पहले वाम मोर्चा ने कांग्रेस के साथ ऐसा किया था। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद सीपीएम व कांग्रेस राजनीतिक हाशिये पर पहुंच गईं। लिहाजा, अब सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा या जूझारू राजनेता रहीं ममता बनर्जी अपनी पार्टी को एकजुट रखने में कामयाब रहेंगी? फिलहाल कोई इसका स्पष्ट जवाब नहीं दे सकता।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

अपनी बोली-बानी की ओर लौटने की जरूरत

धनंजय चोपड़ा | मीडिया विशेषज्ञ

पिछले दिनों एक युवा कार्यक्रम के दौरान 'स्टोरीटेलिंग सत्र' में मैं कहानियां सुना रहा था। कहानी के बीच में मैंने जैसे ही अपने शहर की बोली में एक मुहावरेदार डायलॉग बोला, पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा, मानो सभागार में बैठा हर युवा अपनी बोली-बानी में कुछ सुनने का इंतजार कर रहा हो। फिर मैंने आगे की पूरी कहानी स्थानीय बोली में ही सुनाई, जो खूब पसंद की गई। एक-दो दिन में उस कहानी की अनगिनत रील बन गईं और वे सोशल मीडिया में छा गईं।

अपनी बोली-बानी की ओर लौटने का इससे बेहतर समय फिर नहीं आएगा, क्योंकि पहले नई शिक्षा नीति अपनी मातृभाषा में पढ़ाई और अब सीबीएसई त्रिभाषा फॉर्मूले की बात कह रहा है। ऐसे में, उम्मीद बंधती है कि अपनी बोली-बानी बचाने का काम पीछे आ रही पीढ़ियों के संग-साथ किया जा सकेगा। यूनेस्को दो बरस पहले से ही कह रहा है कि पिछले छह दशकों में भारत की 250 से अधिक भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं और 197 भाषाएं व बोलियां लुप्त होने के कगार पर हैं। तकनीक के भरोसे आगे बढ़ने के समय में पूरी दुनिया में भाषाओं-बोलियों का यही हाल है। भाषाओं पर काम करने वाले 'एथनोलॉग' के ताजा आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की सात हजार में से 44 प्रतिशत भाषाएं और बोलियां अपना अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रही हैं।

कनाडा में विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने पाया है कि जिनके पास अपनी बोली-बानी होती है, वे अधिक विश्वास से जीवन बिताते हैं।

बोली-बानी को संभाले रहने में भारत का अब तक का रिकॉर्ड दुनिया के अन्य देशों से कहीं बेहतर रहा है, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की धमक के बाद मामला कुछ-कुछ बिगड़ता जा रहा है। बड़ी वजह है कि स्थानीय स्तर पर हमने अपनी बोली-बानी में किस्सागोई की परंपरा को नजरअंदाज किया है। एक समय था, जब किस्सागोई घर-घर का हिस्सा हुआ करती थी। घरों, परिवारों और मोहल्लों में बड़े-बूढ़ों की कहानियां-किस्से अपनी बोली-बानी में हुआ करती थीं। उनके स्थानीय शब्दों, मुहावरों और लोकोक्तियों की मजबूत थाती को सोशल मीडिया के प्रसार ने कमजोर कर दिया।

शोध बताते हैं कि अपनी बोली-बानी में किस्सागोई मानसिक सेहत को गहराई से प्रभावित करती है। वास्तव में, जिन बुजुर्गों को अकेलेपन का शिकार होने से हम रोक नहीं पा रहे हैं, उन्हें किस्सों के साथ लाने पर उनका आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और सफल जीवन जीने के फलसफों की थाती को लगातार नया कर सकते हैं।

पिछले दिनों कनाडा के एक विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने पाया कि जिन युवाओं के पास अपनी बोली-बानी की ताकत थी, वे आत्मविश्वास से जीवन बिता रहे थे और उनमें आत्महत्या की दर भी लगभग शून्य थी। इसी तरह का अध्ययन स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, जहां लोगों ने अपनी भाषा में किस्सागोई को अपनाकर युवाओं में जीवन को बेहतर ढंग से जीने और कुछ नया करने के प्रति ललक बढ़ा दी।

भारतीय ज्ञान परंपरा में किस्सागोई या दास्तानगोई को बेहतरीन स्थान मिलता रहा है, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी के साथ होड़ में अपनी इस विधा को कुछ मंचों तक सीमित कर दिया और वह भी कुछ लोगों तक। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि स्कूल-कॉलेजों में अपने इलाके की बोली-बानी में किस्सों को कहने वाले बुजुर्गों को आमंत्रित किया जाए और उनकी किस्सागोई से विद्यार्थियों को जोड़ा जाए? विद्यार्थियों को अपने गांव-परिवार-इलाके की संस्कृति से जुड़ी जानकारियों को अपनी स्थानीय बोली में किस्सों के रूप में सुनाने को प्रेरित किया जाए। इसमें ध्यान रखना होगा कि शब्दों और उनसे जुड़ी ध्वनियों तथा सांस्कृतिक आभाओं से विद्यार्थियों को कुछ इस तरह परिचित कराया जाए कि वे रोजमर्रा की बातचीत में उनके प्रयोग से हिचकिचाएं नहीं, बल्कि सामने वाले तक उसे संप्रेषित करें।

गौर कीजिए, जिन जगहों की अपनी बोली-बानी लुप्त हो गई, वहां का पारंपरिक ज्ञान प्रसार भी कमजोर हुआ है। इसलिए, समय आ गया है कि हम टेक्नोलॉजी का सही ढंग से प्रयोग करते हुए अपनी बोली-बानी को बचाने का प्रयास करें, साथ ही अपने बुजुर्गों की किस्सागोई को वापस पटरी पर लाने का काम करें, ताकि यह परंपरा निरंतरता पाने में पीछे न रहे और नए-नए किस्सागो तैयार होने से शब्दों की दुनिया बची रहे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

ब्रह्म परम औषधि

मनुष्य स्वभाव से जिज्ञासु प्राणी है। वह हरेक वस्तु, घटना और परिस्थिति के पीछे छिपे कारण को जानना चाहता है। यही जिज्ञासा विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म की जन्मदात्री रही है। यदि हम संसार की किसी भी वस्तु का विश्लेषण करना प्रारंभ करें, तो पाएंगे कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण का परिणाम है। उदाहरण के लिए, रसगुल्ले का कारण दूध है और दूध का कारण गाय। गाय स्वयं किसी पूर्व कारण का परिणाम है। इस प्रकार कारण और परिणाम की यह शृंखला अनंत प्रतीत होती है।

यदि मनुष्य इस शृंखला का धैर्यपूर्वक अनुसरण करता जाए, तो अंततः वह उस बिंदु तक पहुंचता है, जहां बुद्धि आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाती है। वहां एक ऐसा परम कारण विद्यमान है, जो स्वयं किसी अन्य कारण का परिणाम नहीं है। भारतीय दर्शन उसे ब्रह्म कहता है- सभी कारणों का कारण, समस्त सृष्टि का मूल आधार। वह स्वयंभू है। उसका कोई पूर्व कारण नहीं है। इसलिए उसे किसी विशेष रूप, आकार या सीमा में बांधना संभव नहीं।

यहीं से आध्यात्मिक साधना का वास्तविक आरंभ होता है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है कि परमसत्ता किसी सीमित रूप में कैद नहीं की जा सकती, तब उसकी दृष्टि व्यापक होने लगती है। इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति ईश्वर को किसी विशेष रूप, समुदाय या सीमित कल्पना तक बांध देता है, तो वह सत्य की व्यापकता से दूर रह जाता है। ऐसी साधना अंततः निराशा और भ्रम का कारण बन सकती है। आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि अमरत्व का मार्ग श्रद्धा, एकाग्रता और निष्कपट समर्पण से होकर गुजरता है। जब साधक पूरे मन से परम चेतना को अपनाता है, तब उसके जीवन में गहरा परिवर्तन आता है। यह अमरत्व केवल शरीर की अमरता नहीं, बल्कि दुखों और बंधनों से मुक्ति की अवस्था है।

मानव जीवन में दुखों की समस्या सदैव रही है। भूख लगती है, तो भोजन चाहिए; रोग होता है, तो औषधि चाहिए। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों को भारतीय दर्शन में 'अर्थ' कहा गया है। भोजन भूख मिटाता है, दवा रोग कम करती है, धन जीवन की अनेक कठिनाइयों को सरल बनाता है। इन सबकी भी एक सीमा है। आज मिटी हुई भूख कल फिर लौट आती है। आज ठीक हुआ रोग भविष्य में पुनः उत्पन्न हो सकता है। धन और संसाधन भी स्थायी सुरक्षा या चिरस्थायी सुख की गारंटी नहीं दे सकते। यही कारण है कि भारतीय मनीषियों ने अर्थ को आवश्यक तो माना, किंतु अंतिम लक्ष्य नहीं। जीवन की मूल समस्या अस्थायी कष्टों का समाधान नहीं, बल्कि दुखों के मूल कारण से मुक्ति है और यह मुक्ति बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि उस परम चेतना की अनुभूति में निहित है, जो सभी सीमाओं से परे है।

जीवन की मूल समस्या अस्थायी कष्टों का समाधान नहीं, बल्कि दुखों के मूल कारण से मुक्ति है और यह बाहरी वस्तु में नहीं, उस परम चेतना की अनुभूति में निहित है, जो सीमाओं से परे है।

श्री श्री आनंदमूर्ति

द्रौपदी मुर्मु | राष्ट्रपति, भारत

छात्रवृत्ति योजनाएं केवल आर्थिक सहायता नहीं हैं, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम हैं। यह उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती हैं, जिनमें प्रतिभा तो होती है, परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है।

75 साल पहले

हिन्दुस्तान Hindustan 03 जून, 1951

राहत की सांस

यद्यपि सुदूरपूर्व से शान्ति व सुस्थिरता के समज्ज्वल प्रकाश की हम बहुत दिनों तक आशा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस विनाशकारी अंधड़ तथा भयंकर घटाटोप ने गत वर्ष 25 जून को कोरिया में अपने मनहूस पांव रखे थे, उसके मिटने का अभी कोई लक्षण ही दृष्टिगोचर नहीं होता, किन्तु पेकिंग रेडियो की इस घोषणा से अवश्य ही बहुतों ने राहत की सांस ली होगी कि तिब्बत तथा चीन के बीच समझौता हो गया।

समझौते की 17 शर्तों का मनन करने के बाद इस धारणा का उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि जहां पेकिंग सरकार ने तिब्बत को उसके स्वशासन की अखंडता का आश्वासन दिया है वहीं ऐसी शर्तें भी रखी हैं, जो कि तिब्बती जनता के स्वतंत्र जीवन के लिए कुछ बोझिल हो सकती हैं। तिब्बत पहले की भांति भविष्य में भी खुदमुख्तार रह सकता है, बशर्ते चीन केवल इस बात पर दृष्टि रखे कि तिब्बत में चीन-विरोधी कोई हलचलें नहीं होतीं। इसमें सन्देह नहीं कि जमाने के साथ तिब्बत को भी आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए तिब्बती जनता में शिक्षा का प्रचार आवश्यक है और उसे एक नवीन प्रेरणा मिलनी चाहिए।

दुर्गम पर्वतमालाओं से आवेष्टित इस 'दुर्ग' में आधुनिक सभ्यता एक दिन प्रवेश अवश्य करेगी। 'आन्तरिक स्वतंत्रता' की रक्षा के नाम पर यथास्थिति का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन यह भी स्मरण रहे कि तिब्बती जनता की स्वाभाविक शान्ति-प्रियता, उसकी अपनी परम्पराओं तथा धार्मिक विश्वासों पर आघात नहीं होना चाहिए। वर्तमान समझौते की सफलता की कसौटी यही है कि चीन तिब्बत के आन्तरिक मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप कर उसकी प्रगति में अधिकतम सहयोग देता है या नहीं। साथ ही यह भी देखना है कि दलाई लामा और पंचन लामा के संबंध कैसे रहते हैं और 'मुक्ति सेना' की गतिविधि कैसी चलती है। भारत सरकार सम्भवतः यह देख रही है कि तिब्बत के साथ भारत के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों पर समझौते का क्या प्रभाव पड़ता है। संधि के अनुसार, चीन की साम्यवादी सरकार तिब्बत में जो प्रशासक और सैनिक समितियां स्थापित करेगी उनके कार्यों से भारत, चीन तथा तिब्बत के भावी संबंधों की स्थिति का पता चल जायेगा।

साइकिल का समय कभी गया ही नहीं

विश्व साइकिल दिवस (3 जून) के अवसर पर साइकिल भी मन ही मन मुस्करा रही होगी कि देखो, आखिर मेरे भी अच्छे दिन आ ही गए! जो कभी आंगन के कोने में धूल फांकती थी, वह आज पेट्रोल-डीजल के महंगाई-पुराण में मुख्य नायिका बन बैठी है। बिना पेट्रोल, डीजल, बिजली और बैटरी के सिर्फ 'हवा' पर चलने वाला यह वाहन सच में आत्मनिर्भर भारत का सबसे पुराना ब्रांड अंबेसडर है। मैकमिलन का यह मितव्ययी आविष्कार कभी घर-घर की शान हुआ करता था। पैडल मारते-मारते न सिर्फ मंजिल मिला करती थी, बल्कि पैरों का व्यायाम भी हो जाता था। मगर आज हालत यह है कि बाइक से जिम जाने वाले महानुभाव वहीं खड़ी साइकिल पर पसीना बहाते हैं।

साइकिल की सबसे बड़ी खूबी है, इसका संयमित चरित्र। इसमें गति और ब्रेक का ऐसा संतुलन है कि दुर्घटना भी सोच-समझकर ही होती है। न हेलमेट का झंझट, न चालान का डर। साइकिल से गिरकर चोट लग जाए, तो समाज कहता है- चलो, सीख रहे हो! और अगर बाइक से गिरो, तो वही समाज कहता है- अरे, संभलकर, ज्यादा हुड़हुड़ाओ मत! रही बात सवारी क्षमता की, तो तकनीकी रूप से यह एक व्यक्ति के लिए बनी है, लेकिन भारतीय जुगाड़ विज्ञान ने इसे पारिवारिक वाहन बना दिया है। आगे डंडे पर एक, पीछे कैरियर पर एक और बीच में खुद चालक- तीन सवारी की न्यूनतम व्यवस्था। कभी-कभी तो एक हाथ से हैंडल, दूसरे से सामान पकड़े हुए, और मुंह से पड़ोसी को 'राम-राम' करते हुए संतुलन बनाए रखना- यह कला सिर्फ भारतीय साइकिल चालक ही जानता है। इसे सीखने की प्रक्रिया भी किसी आध्यात्मिक साधना से कम नहीं। पहले हाफ पैडल, फिर फुल पैडल, और अंत में बिना हाथ चलाने का मोक्ष। उस समय गिरना भी उपलब्धि का हिस्सा माना जाता था- घुटनों एवं कोहनी के छिले निशान आज भी बचपन के 'सर्टिफिकेट' की तरह 'पहचान के निशान' हैं।

समय बदला, बाइक आई, फिर कार आई और साइकिल को कोने में धकेल दिया गया, लेकिन जैसे ही पेट्रोल-डीजल के दामों ने जनता की कमर तोड़ी, साइकिल ने फिर से एंट्री मारी, वह भी पूरे स्वाभिमान के साथ। बड़े-बड़े अधिकारी, नेता और सेलिब्रिटी साइकिल चलाते हुए फोटो खिंचवाने लगे हैं। जनता समझ गई कि मामला गंभीर है और अब साइकिल ही सहारा है। आज साइकिल पर्यावरण की रक्षक, स्वास्थ्य की संरक्षक और जेब की हितैषी बनकर सामने खड़ी है। न प्रदूषण, न खर्च, न ट्रैफिक का तनाव- बस पैडल मारिए और जिंदगी आगे बढ़ाइए।

विनोद कुमार, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

विश्व साइकिल दिवस

भारतीय सड़कों पर इसे चलाने की चुनौती

'विश्व साइकिल दिवस' मनाने का मुख्य उद्देश्य साइकिल को एक सरल, सस्ता, विश्वसनीय, पर्यावरण के अनुकूल और स्वास्थ्यवर्द्धक परिवहन साधन के रूप में बढ़ावा देना है। वास्तव में, यह दिवस लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाने, धरती पर कार्बन उत्सर्जन कम करने और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही, यह दिवस सड़क सुरक्षा, सस्ती परिवहन व्यवस्था और हरित भविष्य के निर्माण का संदेश भी देता है।

किंतु इसके उद्देश्य जितने सार्थक हैं, उन उद्देश्यों को अमल में लाना उतनी ही बड़ी चुनौती। भारत में तो साइकिल ट्रैक का घोर अभाव है। जहां हैं, वहां भी वह अतिक्रमण का शिकार है। इसी तरह, आधारभूत सुविधाओं का अभाव भी एक बड़ी चुनौती है। सड़कों पर मोटर-वाहनों की बढ़ती संख्या और तेज रफ्तार गाड़ियों से सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते खतरे ने भी साइकिल के प्रति हमारी सोच प्रभावित की है। भले ही बार-बार कहा जाता है कि साइकिल फायदेमंद है। यह न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य को, बल्कि हमारी आबोहवा की सेहत को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। किंतु असलियत यही है कि महानगरों में साइकिल के अनुकूल यातायात व्यवस्था की कमी है, जिससे लोगों का साइकिल के प्रति रुझान घटा है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए शहरों में समर्पित साइकिल लेन विकसित करना, सार्वजनिक साइकिल शेयरिंग योजनाओं का विस्तार करना, स्कूलों व कॉलेजों में साइकिल उपयोग को प्रोत्साहित करना, सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन के प्रति जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। वर्ष 2026 के लिए विश्व साइकिल दिवस की थीम 'एक हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना' निर्धारित की गई है। यह थीम पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा बचत तथा टिकाऊ शहरी विकास में साइकिल की भूमिका को रेखांकित करती है। जरूरत यही है कि साइकिल को सही मायने में स्वास्थ्य व परिवहन संरक्षण का प्रतीक बनाया जाए। यह ईंधन रहित साधन वायु प्रदूषण और कार्बन-उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर बढ़ते जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीनहाउस गैसों की समस्या के बीच हमें प्रभावी और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को आगे बढ़ाना है, तो साइकिल के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हमारे नीति-नियंताओं को इसी पृष्ठभूमि में साइकिल को प्रोत्साहित करने की योजना बनानी चाहिए।

सुनील कुमार महला, टिप्पणीकार

1 जून 2026 को नई दिल्ली के आईटीओ में यमुना का जलस्तर गिरकर 268 फीट निम्नतम स्तर के करीब पहुंच गया। ● सोनू मेहता

नदियों में घटता पानी

भारत में दुनिया की 17 प्रतिशत से ज्यादा आबादी रहती है, पर यहां 4 प्रतिशत जल ही उपयोग योग्य है। यहां नदियां जल का प्रमुख स्रोत हैं, लेकिन सदानीरा नदियां भी सिमटने लगी हैं। चढ़ती गर्मी में हम जल संकट से कैसे जूझ रहे हैं? यहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक उदाहरण है। हर साल की तरह यमुना में पानी बहुत घट गया है, पानी कितना घटा है और कैसे जूझ रहा है राजधानी क्षेत्र? पेश है पारस सिंह की रिपोर्ट...

यमुना में पानी तेजी से घट रहा है। गर्मियों में हर साल की तरह नदी का जलस्तर बीते सप्ताह ही वजीराबाद बैराज पर सामान्य स्तर 674.5 फीट से छह फीट नीचे गिरकर लगभग 668.5 फीट रह गया। जलाशय क्षेत्र में केवल 1-1.5 फीट पानी बचा है, जहां से वजीराबाद और चंद्रावल स्थित जल शोधन संयंत्र तक पानी की आपूर्ति की जाती है।

पिछले कुछ दिनों से जलस्तर में लगातार गिरावट दर्ज की गई है और यह 16 जुलाई, 2021 को दर्ज किए गए ऐतिहासिक निम्न स्तर 667 फीट के करीब पहुंच गया है। नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) के अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा आपूर्ति में लगभग 14-15 प्रतिशत की कटौती के कारण नई दिल्ली के इलाकों में भी पानी की कमी महसूस होने लगी। मिसाल के लिए, डीजेबी ने एक दिन 148 मिलियन लीटर प्रतिदिन की मांग के मुकाबले 125 मिलियन लीटर प्रतिदिन पानी की ही आपूर्ति की है।

यमुना के जलाशय में पानी का ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम स्तर 667 फीट दर्ज किया गया था, लेकिन व्यावहारिक रूप से देखा जाए, तो जलाशय में पानी न के बराबर है। अब 268 फीट से नीचे नदी के तल में नहरें खोदकर गहरे क्षेत्रों से संयंत्र की ओर पानी लाना पड़ता है। यह पानी भी गाद मिश्रित है।

दिल्ली में जल की मांग को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। आमतौर पर डीजेबी नौ जल शोधन संयंत्रों के माध्यम से प्रतिदिन 10 करोड़ गैलन पानी की आपूर्ति करता है। एक अधिकारी के अनुसार, जल आपूर्ति में 14-15 प्रतिशत की और कटौती की गई है और निवासियों को सलाह दी जा रही है कि वे स्थिति बिगड़ने की आशंका में पर्याप्त पानी का भंडारण कर लें।

इस बीच, दिल्ली के लिए हरियाणा से अधिक पानी की खरीद के लिए बातचीत चल रही है और आने वाले दिनों में राहत मिलने की संभावना है। यहां यह ध्यान देने की बात है, दैनिक ग्रीष्मकालीन बुलेटिन जारी करने की प्रथा पिछले वर्ष बंद कर दी गई थी। नदी के तल में गहरे जलमार्ग खोदकर पानी निकालने की कवायद चल रही है। दिल्ली को किसी तरह से पानी देने के प्रयासों के बावजूद महानगर के उत्तर, उत्तर-पश्चिम और मध्य क्षेत्रों में पानी की भारी कमी देखी जा रही है। दूसरे शहरों के लिए भी यह एक बड़ा उदाहरण है कि नदी के किनारे बसा एक महानगर पानी के लिए कैसे जूझ रहा है?

पिछले सप्ताह हरियाणा ने मुनक नहर प्रणाली के माध्यम से अतिरिक्त 55 क्यूसेक पानी भेजा था। अधिकारियों के अनुसार, पानी की कमी लगभग 90-100 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि यमुना नदी में अतिरिक्त पानी छोड़े बिना स्थिति में सुधार होने की संभावना नहीं है।

आमतौर पर, दिल्ली को यमुना, गंगा और भूजल स्रोतों से 1,002 एमजीडी पानी मिलता है, जबकि मांग 1,250 एमजीडी की है। इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली टैंकरों और कई ट्यूबवेलों का इस्तेमाल करती है। सामान्यतः यमुना से लगभग 210 क्यूसेक पानी मिलता है, जो पूरी तरह सूख चुकी है। बारिश का इंतजार शुरू हो गया है। बीते दिनों जो छुटपुट बारिश हुई है, उससे नदी जल पर कोई असर नहीं पड़ा है। पहले से ही जल संकट से जूझ रहे इस महानगर में मई के अंत और जून के पहले पखवाड़े की भीषण गर्मी के दौरान यह कमी और भी बढ़ जाती है।

गंगा से यमुना में जल लाने की योजना

पिछले साल केंद्र सरकार की निगरानी में यमुना के पुनरुद्धार के लिए चलाई जा रही परियोजना के तहत गंगा से यमुना में 500 क्यूसेक पानी मोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस प्रस्ताव को व्यावहारिकता संबंधी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और संभवतः यह योजना ठंडे बस्ते में ही पड़ी रहेगी। बताया जाता है कि पूर्वी यमुना नहर और दिल्ली के बीच के कई इलाके बेहद खराब हालत में हैं और पानी को ले जाने में सक्षम नहीं होंगे। साथ ही ग्रीष्म ऋतु में गंगा जल प्रणाली में भी पानी की कमी रहती है, इसलिए वर्तमान में यह योजना व्यावहारिक नहीं पाई गई है। मूल सवाल यही है कि गर्मियों के दिनों में जब गंगा नदी में ही पानी कम होने लगा है, तब वह यमुना को कैसे पानी दे सकती है?

विशेषज्ञ बताते हैं कि गंगा प्रणाली में किसी और नदी के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। नहर प्रणाली कई जगहों पर क्षतिग्रस्त है और निकट भविष्य में इस पानी को दिल्ली तक नहीं ले जा पाएगी। एक अधिकारी बताते हैं कि हम इसे अल्पकालिक आधार पर पर्यावरणीय प्रवाह में सुधार के लिए चलाई जा रही परियोजनाओं के हिस्से के रूप में नहीं देख रहे हैं। परियोजना को भविष्य में पुनर्जीवित किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में यह ठंडे बस्ते में ही पड़ी है। इसकी पुष्टि एक अन्य सरकारी अधिकारी भी करते हैं। अब ध्यान राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर केंद्रित रहेगा, जिनके तहत कोरोनेशन पिलर और यमुना विहार से वजीराबाद तक उच्च गुणवत्ता वाले उपचारित अपशिष्ट जल को ले जाने के लिए एक समर्पित जल परिवहन प्रणाली बनाई जाएगी।

बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश अतिरिक्त जल उपलब्ध कराने को तैयार नहीं है। अब दिल्ली के प्रयास ओखला, कोरोनेशन पिलर और यमुना विहार जैसी आंतरिक परियोजनाओं पर केंद्रित होंगे। दिल्ली उपचारित अपशिष्ट जल के बदले उत्तर प्रदेश से अतिरिक्त सामान्य जल प्राप्त करने के प्रयास जारी रखेगी। यह सही है कि दिल्ली में जल की मांग आबादी के साथ बढ़ती चली जा रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए खास प्रयासों का अभाव रहा है।

दिल्ली, नोएडा में अभी गंगा जल

यमुना में इतना पानी नहीं है कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की प्यास बुझा सके। फिलहाल, यमुना को गंगा से सीधे पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन दिल्लीवाले गंगा जल पी रहे हैं। दिल्ली मुख्य रूप से अपने पड़ोसी राज्यों पर जल के लिए निर्भर है। दिल्ली को लगभग 61.1 प्रतिशत सामान्य जल हरियाणा से, 25.25 प्रतिशत उत्तर प्रदेश से गंगा के माध्यम से और शेष भूमिगत जल स्रोतों से प्राप्त होता है।

उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद को भी गंगा जल की आपूर्ति होती है। हरिद्वार में ऊपरी गंगा नहर से कच्चा जल निकाला जाता है और गाजियाबाद के डासना तक प्रवाहित होता है। डासना से पानी पाइप के माध्यम से गाजियाबाद स्थित प्रताप विहार जल शोधन संयंत्र तक पहुंचाया जाता है। यहां जल का पूर्ण शुद्धिकरण किया जाता है। उपचारित जल को पाइपलाइन के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से नोएडा पहुंचाया जाता है। चूंकि नोएडा की कुल जल मांग अधिक है, इसलिए प्राधिकरण इस सतही जल को भूजल के साथ मिलाकर अलग-अलग सेक्टरों और आवासीय समितियों को आपूर्ति करता है।

जल गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा

दिल्ली में वजीराबाद के बाद यमुना जल गुणवत्ता में तेज गिरावट देखी जाती है, क्योंकि यहां सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट नदी में प्रवेश करते हैं।

यमुना निगरानी समिति की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली में वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज तक यमुना का 22 किलोमीटर लंबा हिस्सा नदी की कुल लंबाई के 2% से भी कम है, लेकिन नदी में होने वाले कुल प्रदूषण का लगभग 76% हिस्सा इसी क्षेत्र में होता है। साफ है कि जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रदूषण को भी रोकना होगा। पानी में जहरीले पदार्थों के बढ़ने से उसकी उपलब्धता भी प्रभावित होती है।

केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना का हवाला देते हुए, *एचटी* ने पिछले वर्ष रिपोर्ट किया था कि एजेंसियों ने वजीराबाद के ऊपर की ओर जल निकासी के लिए कई नालों और जल निकासी नालियों का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद यमुना नदी अत्यधिक प्रदूषित हो जाती है। प्रस्तावित उपाय में कहा गया था कि लगभग 500 क्यूसेक पानी को रुड़की से देवबंद सहायक शाखा के माध्यम से पूर्वी यमुना नहर में मोड़ने की आवश्यकता है। यह अतिरिक्त 500 क्यूसेक पानी यमुना में तीन जगहों पर डाला जाना था। योजना के अनुसार, पानी यमुना से होकर गुजरेगा और दिल्ली से गुजरने के बाद आगरा नहर के माध्यम से फिर ऊपर उठाया जाएगा। एकमात्र शर्त यह थी कि डीजेबी इस अतिरिक्त पानी का उपयोग अपने निजी उपयोग के लिए नहीं करेगा, अन्यथा, पूरा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। इस योजना की दिशा में काम बाकी है। कायदा यही बोलता है कि दिल्ली यमुना का उद्धार करके देश के सामने मिसाल कायम करे। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि नदियों को बचाए बिना जल संकट का स्थायी समाधान नहीं हो सकता।

Hindustan Times

पानी की कमी और इंतजार : तापमान या गर्मी के बढ़ते ही देश के ज्यादातर शहरों और गांवों में पेयजल का अभाव देखा जा रहा है।

1341

क्यूबिक मीटर/प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जल उपलब्ध था साल 2025 में भारत में। यह उपलब्धता साल 1951 में 5177 क्यूबिक मीटर के उच्च स्तर पर थी।

आपूर्ति पर्याप्त नहीं : देश में जल की तेजी से बढ़ती मांग

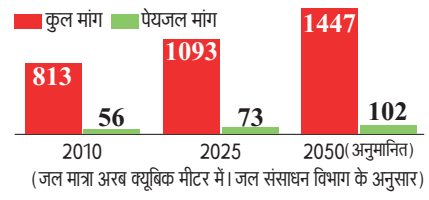

2050 तक कहां-कितना पानी चाहिए?

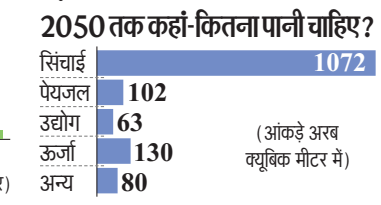

गंगा में अब जल कितना?

50% तक पानी गंगा में घट गया है, बहाव में आ रही कमी।

वैज्ञानिक तौर पर बहती हुई नदी के कुल पानी को पूरी तरह से ठीक-ठीक मापना संभव नहीं है, क्योंकि जलस्तर हर मौसम व स्थान के साथ बदलता रहता है। हां, नदी के औसत वार्षिक जल प्रवाह का वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं। गंगा नदी का औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 52,500 करोड़ घन मीटर है। इसका लगभग 80 प्रतिशत पानी मानसून के महीनों (जून से सितंबर) में बह जाता है। एक वैज्ञानिक अनुमान यह भी है कि नदी के 58 प्रतिशत से अधिक पानी गर्मी के महीनों में वाष्पित हो जाता है। संरक्षण के लिए ज्यादा काम की जरूरत है। गंगा जी के लिए हिमनद ही नहीं, भूजल संरक्षण भी जरूरी है।

यमुना से रूठ रहा जल

25% तक घट गया है यमुना में पानी, प्रवाह में आई कमी।

यमुना में पानी की मात्रा और उसका जलस्तर स्थिर नहीं रहता है, बल्कि यह पहाड़ों पर होने वाली बारिश और हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी पर निर्भर करता है। सामान्य दिनों में इसमें सामान्य बहाव होता है, लेकिन मानसून के दौरान या भारी बारिश के बाद पानी का स्तर कई लाख क्यूसेक तक पहुंच जाता है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। यदि आप दिल्ली या किसी अन्य क्षेत्र के लिए आज का सटीक जलस्तर मापना या जानना चाहते हैं, तो केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। यमुना में सहायक स्रोतों से ही पानी आ रहा है, इसके बहाव को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है।

खतरे की ओर बढ़ती कावेरी

28% तक घट गया है कावेरी नदी का प्रवाह

कावेरी बेसिन की औसत जल क्षमता लगभग 21,358 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसमें से लगभग 19,000 एमसीएम जल का उपयोग किया जा सकता है। कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहनेवाली एक सदानीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी लम्बाई प्रायः 760 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसके पानी को लेकर दोनों राज्यों में विवाद है। इस विवाद को कावेरी जल विवाद कहा जाता हैं। एक अध्ययन के अनुसार, साल 2026 से 2050 के बीच इसके जल प्रवाह में और 3.5 प्रतिशत की कमी आ जाएगी।

नर्मदा को बचाना होगा

15% नर्मदा जल का उपयोग हो पाता है, बाकी बह जाता है

मध्य भारत की जीवनरेखा मानी जाने वाली नर्मदा नदी आज एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। कभी दिव्य पवित्रता और पारिस्थितिक समृद्धि का प्रतीक रही यह नदी आज अनियंत्रित शहरीकरण, औद्योगिक प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन की उपेक्षा के कारण बढ़ते पर्यावरणीय संकट को दर्शाती है। इसकी जैवविविधता में 25 प्रतिशत कमी आ गई है। इस नदी का करीब 40 प्रतिशत क्षेत्र अतिक्रमण का शिकार हुआ है। इसमें गिरने वाले गंदे पानी के महज 30 प्रतिशत का ही शोधन हो पाता है। नर्मदा की 41 सहायक नदियों का भी हाल साल-दर-साल बिगड़ता जा रहा है।

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। आय में वृद्धि होगी, परंतु कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है।

वृष : मन परेशान रहेगा। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। भागदौड़ अधिक रहेगी। खर्चों की अधिकता रहेगी, परंतु कारोबार में वृद्धि होगी। आय भी बढ़ेगी।

मिथुन : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी।

कर्क : धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। कारोबार में बदलाव की संभावना बन रही है। मन परेशान हो सकता है। किसी दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं।

सिंह : मन प्रसन्न रहेगा। घर-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी। वस्त्र उपहार में मिल सकते हैं। कारोबार में लाभ के अवसर भी मिलेंगे।

कन्या : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन परेशान हो सकता है। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ में भी वृद्धि होगी। किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद भेंट हो सकती है।

तुला : धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। माता की सेहत का ध्यान भी रखें। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन परेशान भी हो सकता है।

वृश्चिक : संतान सुख में वृद्धि होगी। परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। माठे खानपान में रुचि बढ़ सकती है। मन परेशान रहेगा। संयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें।

धनु : मन प्रसन्न तो रहेगा, परंतु आत्मविश्वास में कमी रहेगी। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ में भी वृद्धि होगी।

मकर : मन परेशान हो सकता है। जीवनसाथी और पिता की सेहत का ध्यान रखें। कारोबार में बदलाव की संभावना बन रही है। भागदौड़ अधिक रहेगी।

कुंभ : नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की के अवसर मिलेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में विस्तार होगा। आय में वृद्धि होगी। मन प्रसन्न रहेगा।

मीन : पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। शैक्षिक व शोधादि कार्यों में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर मिलेंगे।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋषिकांत गोस्वामी

03 जून, बुधवार, **शक संवत्** : 13 ज्येष्ठ (सौर) 1948, **पंजाब पंचांग** : 20 ज्येष्ठ मास प्रविष्टे 2083, **इस्लाम**: 16 जिल्हिजा, 1447, **विक्रमी संवत्** : द्वितीय (अधिक) ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तिथि रात्रि 09.22 मिनट तक। शुभ योग प्रातः 08.12 मिनट तक पश्चात शुक्ल योग, वणिज करण, चंद्रमा धनु राशि में (दिन-रात)।

सूर्य उत्तरायण। ग्रीष्म ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा प्रातः 08.12 मिनट से रात्रि 09.22 मिनट तक। श्री गणेश चतुर्थी व्रत।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

कृपया यह बताएं कि मुकदमे की फाइलें कहां रखें कि लाभ हो? -रीता नारंग, लखनऊ

- मुकदमे की फाइल दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं रखनी चाहिए। इससे शत्रु पक्ष से झगड़ा बढ़ सकता है और मुकदमा हारने का भय रहता है।
- कोर्ट केस की फाइल बैंक की पासबुक या फिक्स्ड डिपाजिट के साथ नहीं रखनी चाहिए। कोर्ट केस की फाइल दक्षिण पश्चिम दिशा में रखने पर मुकदमे के बहुत लंबे समय तक चलने की संभावना रहती है। मुकदमे की फाइल ईशान कोण में रखना सबसे अच्छा होता है। इसके शुभ फल मिलते हैं। फाइल का कवर लाल या काला न हो। कटी-फटी भी न हो। फाइल के ऊपर केसर या हल्दी से ओम एवं श्री लिखें।

वर्ग पहेली : 8348

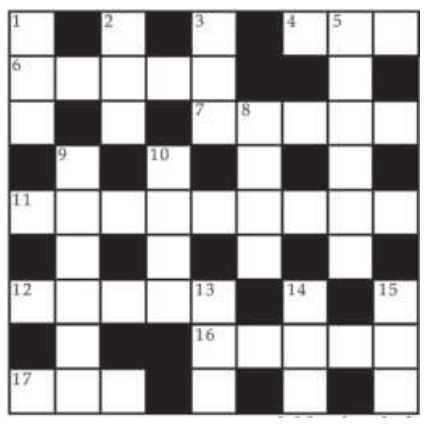

बाएं से दाएं
4. काव्य रचना; पदावली; पद्यमय विवरण; रसात्मक रचना (3)
6. बंदीकरण; मौके पर की गई गिरफ्तारी (2,3)
7. घटाना; निकालना (2,3)
11. हर समय काम में लगे रहना (2,2,2,3)
12. कार्य संपन्न करना; निपटाना; कारगर सिद्ध होना; प्रभावी होना; सफलता मिलना (2,3)
16. फंसाना; लालच देना; लालसा जगाना; लुब्ध करना (2,3)
17. मानदंड; स्तर (3)

ऊपर से नीचे
1. ओंठ; नीचे का; पहले का; धरती और आकाश के बीच का स्थान (3)
2. गीला पदार्थ पोतना (3)
3. पथ; मार्ग; रास्ता (3)
5. सोचना; संकल्प करना; ध्यान करना; मनन करना (3,3)
8. इतराना; चंचलता दिखाना; लचककर नखरे से चलना; कुल्हड़ (4)
9. लोकसमर्थन; जनता का समर्थन (6)
10. गीत रचने वाला; गीत लिखने वाला (4)
13. अज्ञान; अबोधता; नासमझी; मूर्खता (3)
14. अन्नादि रखने का स्थान; कोठार; कोष; खजाना (3)
15. चुनने का कार्य; निर्वाचन (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8347

सुडोकू : 8330 * आसान

4		1				2		6
			1	3	5			
8								1
7		4		8		1		2
6	8						7	3
9		3		2		8		4
5								9
			6	9	2			
3		6				4		7

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8329

5	3	7	4	6	9	1	2	8
4	6	8	5	2	1	7	9	3
9	1	2	3	8	7	4	6	5
6	5	4	9	1	3	2	8	7
8	9	1	7	5	2	3	4	6
2	7	3	6	4	8	9	5	1
7	8	6	1	9	4	5	3	2
1	2	9	8	3	5	6	7	4
3	4	5	2	7	6	8	1	9

खाते से रकम निकाल एफडी में तेजी से निवेश कर रहे भारतीय

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय परिवारों के बचत करने के तरीके में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। देश में बड़ी संख्या में लोग अब बचत खाते में पैसा रखने के बजाय सावधि जमा (एफडी) में निवेश कर रहे हैं। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, बीते चार वर्षों में एफडी और अन्य सावधि जमाओं की हिस्सेदारी 55.2 प्रतिशत से बढ़कर 61.6 प्रतिशत हो गई।

रिपोर्ट के अनुसार, पिछले चार वर्षों में बैंक जमाओं के स्वरूप में बड़ा बदलाव आया है। मार्च 2022 में बैंकों की कुल जमाओं में बचत खातों की हिस्सेदारी 34.6 प्रतिशत थी, जो मार्च 2026 में घटकर 28.7 प्रतिशत रह गई। वहीं, इसी अवधि में एफडी और अन्य सावधि जमाओं की हिस्सेदारी में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। आंकड़ों से यह भी पता चला कि सात फीसदी से कम ब्याज दर वाली एफडी की हिस्सेदारी पिछले वर्ष के 27.3 फीसदी से बढ़कर मार्च 2026 में 61.8 फीसदी हो गई।

तीन साल की एफडी में सबसे ज्यादा निवेश

रिपोर्ट के अनुसार, लोगों की सबसे ज्यादा रुचि तीन वर्ष की अवधि वाली एफडी में दिखाई दी है। मार्च 2022 में ऐसी एफडी का हिस्सा 50.4 प्रतिशत था, जो मार्च 2026 में बढ़कर 69.8 प्रतिशत हो गया। इससे संकेत मिलता है कि जमाकर्ता लंबे समय तक बेहतर ब्याज दर प्राप्त करना चाहते हैं।

एक करोड़ से अधिक वाली एफडी का दबदबा

यह भी सामने आया है कि बड़ी रकम वाली एफडी की हिस्सेदारी भी लगातार बढ़ रही है। एक करोड़ रुपये या उससे अधिक की एफडी कुल सावधि जमाओं का 46.3 प्रतिशत हिस्सा रखती है।

इनमें भी पांच करोड़ रुपये से अधिक की एफडी का हिस्सा 34.8 प्रतिशत है। इससे पता चलता है कि बड़े निवेशकों की भूमिका बढ़ती जा रही है।

वरिष्ठ नागरिकों का भरोसा कायम

रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों की बैंक जमाओं में हिस्सेदारी लगभग 20 प्रतिशत पर स्थिर बनी हुई है। यह दर्शाता है कि रिटायर लोगों के लिए एफडी अभी भी सबसे भरोसेमंद निवेश विकल्पों में शामिल है।

खाते पर कम ब्याज वजह

विशेषज्ञों के अनुसार, इस बड़े बदलाव के पीछे मुख्य वजह बचत खातों पर मिलने वाला बेहद कम ब्याज और खुदरा महंगाई की मार है। देश के बड़े बैंक वर्तमान में बचत खातों पर केवल 2.5 से 3 प्रतिशत तक ब्याज दे रहे हैं, जबकि एफडी पर 6 से 8 प्रतिशत तक ब्याज मिल रहा है। इसी वजह से निवेशकों का रुझान एफडी की ओर बढ़ा है।

महंगाई से घट रही बचत की असली कीमत

जब बचत खाते पर मिलने वाला ब्याज महंगाई दर से कम होता है, तो जमा धन की वास्तविक क्रय शक्ति घटने लगती है। अप्रैल 2026 में खुदरा महंगाई दर 3.48 प्रतिशत रही। इसका मतलब है कि बचत खाते में रखा पैसा धीरे-धीरे अपनी खरीद क्षमता खो रहा है।

घर-परिवार अब भी सबसे बड़े जमाकर्ता

रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2026 तक कुल बैंक जमाओं में घरेलू क्षेत्र की हिस्सेदारी 59.3 प्रतिशत रही। हालांकि, लोग अब एफडी के अलावा म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार जैसे निवेश विकल्पों की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं, जहां अधिक रिटर्न की संभावना रहती है। भारतीय बचतकर्ता अब अपने निवेश को लेकर पहले से अधिक जागरूक हो रहे हैं।

प्रायोरिटी प्लान पर स्पष्टीकरण मांगा

नई दिल्ली, एजेंसी। दूरसंचार नियामक ट्राई ने अपने शुरुआती आकलन में यह पाया है कि भारती एयरटेल के हाल ही में पेश 'प्रायोरिटी पोस्टपेड' प्लान 'इंटरनेट निरपेक्षता' (नेट न्यूट्रैलिटी) के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। हालांकि, कंपनी से इस मामले में और स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

मामले से जुड़े एक सूत्र ने मंगलवार को यह जानकारी दी। ट्राई इस मुद्दे की विस्तृत जांच कर रहा है कि 5जी नेटवर्क स्लाइसिंग के जरिये अन्य सेवाओं की गुणवत्ता पर कोई असर तो नहीं पड़ रहा। नेटवर्क स्लाइसिंग वह तकनीक है जिसमें दूरसंचार नेटवर्क को अलग-अलग वर्चुअल हिस्सों में बांटकर अलग जरूरतों के हिसाब से सेवा दी जाती है।

बाजार 30s

शेयर बाजार

सेंसेक्स
74,649 +382.50

निफ्टी
23,483 +100.95

सर्राफा

	भाव	बदलाव
सोना	1,61,450	+1,050
चांदी	2,71,000	+1,300

करेंसी

95.36 -0.17 डॉलर/रुपया

शानदार प्रदर्शन

कोटा। जेईई-एडवांस्ड 2026 परिणामों में एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट कोटा ने लगातार तीसरे वर्ष ऑल इंडिया रैंक-1 देकर रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले वर्ष 2016 में भी एलन ने यह उपलब्धि हासिल की थी। संस्था के सीईओ नितिन कुकरेजा ने कहा कि ये परिणाम छात्रों की सफलता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं।

मुनाफे में गिरावट संभव

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण चालू वित्त वर्ष में भारत के एमएसएमई क्षेत्र पर दबाव बढ़ने की आशंका है जिससे उनकी आय और मुनाफे में गिरावट आ सकती है। 'क्रिसिल इंटेलिजेंस' की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 में इस क्षेत्र की आय वृद्धि घटकर 7.5-8.5 प्रतिशत रह सकती है।

केवाईसी कराने के लिए चक्कर कटवा रहे बैंक

हि विशेष

■ **अरुण चट्ठा**

नई दिल्ली। देशभर में बैंक खातों की केवाईसी अपडेट कराने में लाखों ग्राहकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बैंक लंबे समय से निष्क्रिय या कम इस्तेमाल होने वाले खातों को संवेदनशील श्रेणी में डालकर उनके संचालन पर रोक या पाबंदी लगा रहे हैं। इस कारण ग्राहकों को खाता दोबारा सक्रिय कराने और केवाईसी अपडेट कराने के लिए बार-बार बैंक शाखाओं के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

आरबीआई ने केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। इसके बावजूद कई बैंक ग्राहक से आधार कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य दस्तावेज फिर से जमा कराने की मांग कर रहे हैं।

कई मामलों में ऑनलाइन केवाईसी की सुविधा होने के बावजूद ग्राहकों को शाखा में बुलाया जा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों, दिव्यांगों और ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों को हो रही है। जिन लोगों का खाता किसी दूसरे शहर या कस्बे की शाखा में है, उन्हें मूल शाखा भेजा जा रहा है। केवाईसी अपडेट नहीं होने पर कई खातों में लेनदेन पर रोक लगा दी गई है। इसका असर पेंशन, छात्रवृत्ति और सरकारी योजनाओं के लाभ पर पड़ा रहा है।

सोशल मीडिया पर लगा शिकायतों का अंबार

बैंकों के पास केवाईसी अपडेट को लेकर बड़ी संख्या में शिकायतें मिली हैं। सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अरिजीत शर्मा इंडियन ओवरसीज बैंक को टैग करते हुए लिखते हैं कि मैं केवाईसी अपडेट कराने के लिए शाखा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा आधार कार्ड किसी दूसरे व्यक्ति के खाते से लिंक है। यह कैसे हो सकता है, यह साफ तौर पर बैंक अधिकारियों द्वारा की गई गलती है। इसी तरह से दिग्विजय शर्मा लिखते हैं कि मेरी मां की उम्र 75 वर्ष से अधिक है। उनका खाता अस्थाई रूप से फ्रीज कर दिया हैं और बैंक वाले भीषण गर्मी में ब्रांच आने के लिए बोल रहे हैं।

केवाईसी के जरूरी नियम

- यदि ग्राहक की केवाईसी जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो वह केवल 'नो चेंज' की स्व-घोषणा देकर केवाईसी अपडेट करा सकता है।
- ऐसे मामलों में दोबारा दस्तावेज जमा कराने की आवश्यकता नहीं होती।
- यदि किसी ग्राहक का सिर्फ पता बदला है, तो ग्राहक स्व-घोषणा और आवश्यक प्रमाण के साथ केवाईसी अपडेट करा सकता है।
- बैंकों को ग्राहकों को केवाईसी की नियत तिथि से पहले कम से कम तीन बार सूचना देनी होगी। इनमें कम से कम एक सूचना पत्र के माध्यम से भेजना आवश्यक है।
- बैंक को ग्राहक को आसानी से केवाईसी अपडेट कराने के लिए ऑनलाइन एवं डिजिटल सुविधा भी देनी होगी।

जरूरी वस्तुओं के दाम में वृद्धि संभव

नई दिल्ली, एजेंसी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति-जनित दबाव बढ़ने की आशंका है। इससे आने वाले महीनों में आम उपभोग की वस्तुएं महंगी हो सकती हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने मंगलवार को जारी रिपोर्ट में यह अनुमान जताया।

रिपोर्ट कहती है कि 15 मई के बाद से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। इससे खुदरा मुद्रास्फीति करीब 0.36 प्रतिशत बढ़ सकती है। अगर कीमतें 10 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ जाती हैं तो खुदरा महंगाई में 0.48 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। सर्वाधिक प्रभाव सड़क परिवहन पर पड़ेगा।

थोक महंगाई की गणना नए तरीके से

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार थोक मूल्य सूचकांक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) को लागू करने जा रही है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में थोक महंगाई के रुझानों का अधिक सटीक और वास्तविक आकलन करना है। पीपीआई में उत्पादन, इनपुट लागत और सेवाओं की कीमतों को भी शामिल किया जाएगा।

मंगलवार को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार प्रवीण महतो ने बताया कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग 15 जून को नए आधार वर्ष 2022-23 पर आधारित संशोधित डब्ल्यूपीआई के आंकड़े जारी करेगा, जो वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 वाली श्रृंखला का स्थान लेगी। 15 जून को आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक (ओपीपीआई), ट्रायल इनपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक (आईपीपीआई) और सेवा उत्पादक मूल्य सूचकांक (एसपीपीआई) भी जारी किए जाएंगे। सेवा पीपीआई के पहले चरण में बैंकिंग, प्रतिभूति लेनदेन, बीमा, पेंशन फंड प्रबंधन, रेलवे, हवाई यात्री सेवा और दूरसंचार सेवाएं शामिल होंगी।

महंगाई के दबाव का अनुमान लगा सकेंगे

प्रधान आर्थिक सलाहकार महतो ने कहा कि पीपीआई के माध्यम से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि उद्योगों में कच्चे माल और अन्य इनपुट की लागत में बदलाव का असर तैयार उत्पादों की कीमतों पर कैसे पड़ता है। इससे महंगाई के दबाव का सटीक विश्लेषण किया जा सकेंगे। सेवा क्षेत्र के लिए पीपीआई सात सेवाओं के आधार पर तैयार किया गया है।

विभाग 15 जून को जारी करेगा आंकड़े

डब्ल्यूपीआई और ओपीपीआई मासिक आधार पर जारी किए जाएंगे। 15 जून को मई 2026 के प्रारंभिक आंकड़ों के साथ अप्रैल 2023 से अप्रैल 2026 तक की पिछली श्रृंखला भी जारी की जाएगी। विनिर्माण क्षेत्र के लिए इनपुट पीपीआई मार्च 2026 से प्रयोगात्मक आधार पर प्रकाशित किया जाएगा। वहीं, सेवा क्षेत्र के पीपीआई तिमाही आधार पर जारी होगा।

मुद्रा भंडार बचाने के लिए आरबीआई ने सोना बेचा

दावा

- ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स रिसर्च की रिपोर्ट में दावा
- आरबीआई ने 12 अरब डॉलर का सोना बेच दिया

नई दिल्ली, एजेंसी। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में दावा किया है कि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए आरबीआई ने 12 अरब डॉलर मूल्य (करीब 1.14 लाख करोड़ रुपये) का सोना बेच दिया है। आरबीआई ने इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की है।

रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई ने 22 मई को समाप्त हुए दो हफ्तों के भीतर सोना बेचा। हालांकि, इसी अवधि के दौरान आरबीआई ने 7.5 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भी खरीदी हैं। यह आकलन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है। मार्च के अंत तक आरबीआई के पास 880.52 मीट्रिक टन सोना था। इसमें से 77% घरेलू तिजोरियों में रखा गया था। माना जा रहा है कि होर्मुज जलमार्ग में व्यवधान के कारण भारत का आयात बिल बढ़ा है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक होने के कारण भारत को कच्चे तेल के लिए अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है। इससे रुपये और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ा है।

चांदी आयात को अनुमति अनिवार्य

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि रिजर्व बैंक नामित एजेंसियों, डीजीएफटी अनुमोदित संस्थाओं और इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के माध्यम से पात्र आभूषण विक्रेताओं के जरिये चांदी के आयात को केवल वैध आयात मंजूरी के तहत ही अनुमति दी जाएगी।

इस कदम ने चांदी के आयात मानदंडों को और सख्त कर दिया है। आयात मंजूरी विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी की जाएगी। पिछले महीने सरकार ने गैर-जरूरी आयात पर अंकुश लगाने के लिए सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया था।

अमेरिका से अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमति जल्द

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भारत-अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार से नई दिल्ली में तीन दिन की उच्चस्तरीय वार्ता शुरू हो गई। दोनों पक्ष पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि करीब 99 फीसदी मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। ऐसे में वार्ता जल्द पूरी हो सकती है।

सूत्रों के मुताबिक अमेरिका की नई शुल्क नीति के कारण दोनों देशों को व्यापार समझौते के ढांचे में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। भारत चाहता है कि उसे अपने प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर शुल्क लाभ मिले।

उधर, अमेरिकी प्रशासन ने मंगलवार को कृषि और औद्योगिक उपकरणों पर मौजूदा टैरिफ को 25 से घटाकर 15 फीसदी कर दिया है।

गोयल ने ब्रिटेन के मंत्री से मंथन किया

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को ब्रिटेन के व्यापार एवं व्यवसाय मंत्री पीटर कायले के साथ द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की।

एक्स पर पोस्ट में गोयल ने कहा कि भारत-ब्रिटेन आर्थिक सहयोग के अगले चरण की रूपरेखा तैयार करने, साझा व्यावसायिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने पर सार्थक बातचीत हुई।

जल्द उबर सकते हैं भारतीय बाजार

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय शेयर बाजार भले ही दुनिया की रैंकिंग में सातवें स्थान पर खिसक गया हो लेकिन यह फिर रफ्तार पकड़ सकता है। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली के अनुसार, अगले दो वर्षों में भारतीय कंपनियों की आय वृद्धि 10 प्रतिशत से बढ़कर 22 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। यदि ऐसा होता है तो शेयर बाजार में नई तेजी देखने को मिल सकती है।

विदेशी निवेशकों की बिकवाली और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण फिलहाल बाजार दबाव में है, लेकिन घरेलू निवेशकों की मजबूत भागीदारी, आर्थिक विकास और कॉर्पोरेट मुनाफे में संभावित सुधार लंबे समय में भारतीय शेयर बाजार को फिर से मजबूती दे सकते हैं। भारत की 4.15 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यही वजह है कि अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के बावजूद कई वैश्विक संस्थान भारत को दुनिया के सबसे आकर्षक निवेश बाजारों में शामिल मान रहे हैं

इसलिए गिरावट : विदेशी निवेशकों की बिकवाली से भारतीय बाजारों में गिरावट आ रही है। वर्ष 2026 में विदेशी निवेशकों की बिकवाली का आंकड़ा 2.41 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

एक लाख तक पहुंच सकता है सेंसेक्स

मॉर्गन स्टेनली ने रिपोर्ट में कहा है कि अगर कच्चे तेल की कीमत गिरकर 80 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ जाती है और कंपनियों की वार्षिक वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2028 में 19 फीसदी रह सकती है। ऐसे में सेंसेक्स के एक लाख अंक तक जाने की 25 फीसदी संभावना है। अगर क्रूड 120 डॉलर से ऊपर बना रहता है तो सेंसेक्स में गिरावट देखी जा सकती है।

शुद्धि पत्र

दिनांक 12.07.2025 को अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, द्वितीय नोएडा के प्रकाशित विज्ञापन की ई–निविदा सूचना में भूलवश पत्रांक संख्या का प्रकाशन होना रह गया था। कृपया सुधारकर पत्रांक संख्या 2546 पढ़ा जाए।

विज्ञापन व्यवस्थापक

शुद्धि पत्र

दिनांक 29.06.2025 को अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, द्वितीय नोएडा के प्रकाशित विज्ञापन की ई–निविदा सूचना में भूलवश पत्रांक संख्या का प्रकाशन होना रह गया था। कृपया सुधारकर पत्रांक संख्या 2136 पढ़ा जाए।

विज्ञापन व्यवस्थापक

Uttar Pradesh State Institute of Forensic Science, Lucknow
Aurawan, Daroga Kheda, P.O. Banthra, Lucknow - 226401
(Advanced Professional Diploma Programmes)

" BUILD YOUR CAREER IN FORENSIC SCIENCE"
ADMISSIONS OPEN – 2026

Advanced Professional Diploma Programmes

Uttar Pradesh State Institute of Forensic Science (UPSIFS), Lucknow (Established in 2021), functioning under the aegis of the Home Department, Government of Uttar Pradesh and affiliated with the National Forensic Science University, Gandhinagar, invites applications for admission to the following 6-month Advanced Professional Diploma Programmes:

- Crime Scene Management and Legal Compliance
- Forensic DNA Profiling and Legal Compliance
- Questioned Document Examination, Fingerprint Analysis and Legal Compliance

Interested candidates may apply online. Detailed eligibility criteria, fee structure, and admission guidelines are available on the institute website.

Website: www.upsifs.ac.in

Last Date for Submission of Application: 30-06-2026

Registrar
Uttar Pradesh State Institute of Forensic Science (UPSIFS), Lucknow

UP-252062, Dt. 02.06.2026, Website : www.upgov.nic.in

पूर्वोत्तर रेलवे

Email: dycmmgkpd@gmail.com
Website: www.ner.indianrailways.gov.in & www.tenders.gov.in

निविदा सूचना सं. 02 दि. 01.06.26
ई–प्रोक्योरमेंट के माध्यम से निविदा आमंत्रण

उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/डिपो/पूर्वोत्तर रेलवे/ गोरखपुर कृते भारत के राष्ट्रपति तथा उनकी ओर से ई–प्रोक्योरमेंट के माध्यम से निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। सामग्री का पूर्ण विवरण तथा नियम एवं शर्तें वेबसाईट **www.ner.indianrailways.gov.in & www.ireps.gov.in** पर देखा जा सकता है। **क्र.सं. 1: निविदा संख्या एवं खुलने की तिथि:** 10266337 Dt. 22.06.2026; **मद का संक्षिप्त विवरण:** सप्लाई एंड कमीशनिंग ऑफ माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पीड इंडीकेटिंग इत्यादि; **मात्रा:** 21 Set; **अर्नेस्ट मनी(₹):** 1,23,410/-; **क्र.सं. 2: निविदा संख्या एवं खुलने की तिथि:** 10249774D Dt. 23.06.2026; **मद का संक्षिप्त विवरण:** सप्लाई, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ CO2 वेल्डिंग मशीन इत्यादि; **मात्रा:** 25 Nos; **अर्नेस्ट मनी(₹):** 3,03,520/-; **1.** उपरोक्त निविदा आईआरईपीएस के साइट **http/www.ireps.gov.in** पर स्थित है। जो प्रतिष्ठान इलेक्ट्रॉनिकली पंजीकृत हैं वे ई–टेण्डर में सम्मिलित हो सकते हैं। जो प्रतिष्ठान क्लास–3 डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त किये हैं वे अधिकृत एजेन्सी जो भारत सरकार के द्वारा अधिकार पत्र आईटी अधिनियम 2000 से अधिकृत हैं उनसे प्राप्त कर सकते हैं। मैन्युअल निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी। **2.** आपूर्तिकर्तागण को यह सूचित किया जाता है कि उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/डिपो/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर विज्ञापित निविदाएं एवं सभी बुलेटिन निविदाएं केवल ईपीएस (ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम) द्वारा खोली जा रही हैं। जो भी प्रतिष्ठान उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/डिपो/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर की निविदाओं के प्रति इच्छुक हों एवं भाग लेना चाहते हों उन्हें आवश्यक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा एवं अपने प्रतिष्ठान को CRIS/Nwe Delhi में पंजीकृत कराना होगा। इस संबंध में आवश्यक विस्तृत विवरण वेबसाइट **http/www.ireps.gov.in** से प्राप्त किया जा सकता है। **3.** निविदा सूचना के अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रकाशन में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी प्रकाशन मान्य होगा। **4.** एलोकेशन शीर्ष निविदा प्रपत्र, जमानती धनराशि का 00844517 तथा बयाना धनराशि का 00084506 है। उप मुख्य सामग्री प्रबन्धक/डिपो/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर द्वारा प्रकाशित ई–निविदाओं का टेण्डर कॉस्ट तथा ईएमडी का भुगतान ऑनलाइन IREPS PORTAL पर ही मान्य होगा जो दिनांक 01.09.2016 से या उनके बाद प्रकाशित निविदाओं पर प्रभावी होगा। यह Global Tender पर प्रभावी नहीं होगा।

उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/डिपो
मुजाधि/एस–20 **गोरखपुर**

ट्रेनों में बीड़ी/सिगरेट न पियें

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग

संक्षिप्त विज्ञप्ति

सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरुष / महिला शाखा) परीक्षा-2025 के **कला विषय** से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा हेतु प्राप्त आवेदन पत्र की सन्निरीक्षोपरांत जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त किये गये हैं, उनके निरस्तीकरण के कारण सहित विस्तृत विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट **https://uppsc.up.nic.in** पर आज दिनांक 02.06.2026 से उपलब्ध है। उक्त निरस्तीकरण के संबंध में अभ्यर्थीगण दिनांक 08.06.2026 को सांय 05:00 बजे तक अपील कर सकते हैं।

संख्या- 02/14/ई-6/एल0टी0 ग्रेड/2025-26 (शैलेन्द्र सिंह)
दिनांकः- प्रयागराज, 02 जून, 2026 अनुसचिव

उत्तर रेलवे

रुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.ओ.आई)

ईओआई क्रमांक: एनआर–डीएलआई/डब्ल्यू–आईवी/ईओआई/1/2026–27 दिनांक: 02.06.2026

भारत के राष्ट्रपति की ओर से, संभागीय अभियंता–चतुर्थक, दिल्ली संभाग, उत्तरी रेलवे, हरियाणा के बहादुरगढ़ में रेलवे ट्रैक/स्टेशन के पहुंच मार्गों के किनारे स्थित रेलवे भूमि के सौंदर्यीकरण और रखरखाव के लिए सरकारी निकायों, नगर निगम प्राधिकरणों, गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों, निगम संस्थाओं और अन्य इच्छुक पक्षों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है। इच्छुक पक्ष अपनी ईओआई और मांगी गई जानकारी को सीलबंद लिफाफे में ''संभागीय अभियंता–चतुर्थक, दिल्ली संभाग, उत्तरी रेलवे, डीआरएम कार्यालय, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली'' के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

अ. क्षेत्र की सामान्य जानकारी

क्रम सं.	क्षेत्र का विवरण	अनुमानित क्षेत्रफल
1	पार्क संख्या–1, बहादुरगढ़ में डाउन लाइन की ओर OHE 29/40 से OHE 30/8 के बीच स्थित है।	इसका क्षेत्रफल लगभग 2942.56 वर्ग मीटर है।
2	पार्क संख्या–2, बहादुरगढ़ में डाउन लाइन की ओर OHE 29/12 से OHE 29/38 के बीच स्थित है।	इसका क्षेत्रफल लगभग 20381.40 वर्ग मीटर है।

ई.ओ.आई. जमा करने की अंतिम तिथि 23.06.2026 को दोपहर 3:00 बजे तक है।

मंडल अभियंता– चतुर्थ
मंडल रेलवे प्रबंधक कार्यालय
स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली

1874/26
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
पर्यटन विभाग
सी-ब्लॉक, दूसरा तल, विकास भवन-2, अपर बेलारोड
दिल्ली-110054

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति, 2026 का मसौदा पर्यटन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार तथा दिल्ली पर्यटन एवम् परिवहन विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् **(https://tourism.delhi.gov.in)**, एवम् **https://delhitourism.gov.in/** पर सभी हितधारकों सहित आम जनता की जानकारी हेतु अपलोड किया गया है।

मसौदा दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति, 2026 पर अभिमत/टिप्पणियां **25.06.2026** तक निम्नलिखित माध्यमों से आमंत्रित की जाती है:

ई-मेल द्वारा: bndpolicy2026@gmail.com

डाक द्वारा: उप सचिव (पर्यटन), पर्यटन विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
सी-ब्लॉक, दूसरा तल, विकास भवन-2, अपर बेला रोड, दिल्ली -110054

निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

उप सचिव (पर्यटन)
पर्यटन विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

DIP/Shabdarth/Classified/0092/26-27

indiamart
इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड

सीआईएन: L74899DL1999PLC101534
पंजी. कार्यालय: पहली मंजिल, 29–दरियागंज, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली–110002
कार्पोरेट कार्यालय: छटी मंजिल, टॉवर 2, एसोटेक बिजनेस क्रेस्टेरा, प्लॉट नंबर–22, सेक्टर–135, नोएडा – 201305, उ.प्र.
वेबसाइट: www.indiamart.com; **ईमेल:** cs@indiamart-com; **फोन:** 011–45608941

नोटिस – 27वीं वार्षिक आम बैठक एवं ई–वोटिंग की जानकारी

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की सत्ताईसवीं ('27वीं') वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') सोमवार, 29 जून, 2026 को प्रातः 10:00 बजे भारतीय समयानुसार, बैठक में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो वीडियो साधनों ('ओएवीएम') की सुविधा के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत निर्मित नियमों और सेबी के सभी लागू प्रावधानों (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और समय – समय पर जारी विविध परिपत्रों के अनुपालन सहित एजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसायों को संचालित करने के लिए आयोजित की जाएगी।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए की जाएगी। सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ही आयोजित की जा रही है।

लागू वैधानिक अनुपालन के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2025–26 की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम के नोटिस वितरण का काम मंगलवार, 02 जून, 2026 को इलेक्ट्रॉनिक मोड से उन सदस्यों/लाभकारी स्वामियों को भेज दिए गए हैं, जिनके नाम शुक्रवार, 29 मई, 2026 को डिपॉजिटरीज़ पार्टिसिपेंट्स ने प्राप्त कर लिए हैं, और जिनके ईमेल आईडी कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट जैसे मेसर्स एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ('आरटीए') और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी') के पास पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 36(1)(बी) के अनुसार, जिन सदस्यों के ईमेल पते कंपनी/आरटीए/डीपी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें एक पत्र भेजा जा रहा है, जिसमें एक वेबलिंक प्रदान किया गया है, जिसमें कंपनी की वेबसाइट पर 27वीं एजीएम का नोटिस और वित्तीय वर्ष 2025–26 की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट देखी जा सकती है।

उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट http://investor.indiamart.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com के साथ ही नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

कंपनी एनएसडीएल की ई–वोटिंग सेवाओं के माध्यम से अपने सदस्यों को एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग सुविधा और एजीएम में ई–वोटिंग सुविधा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20, समय–समय पर संशोधित और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के सहपठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार (सूचीबद्धता विनियम) के तहत प्रदान कर रही है, ताकि वे प्रस्तावित सभी प्रस्तावों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेनदेन किया जाएगा। इस संबंध में, सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

अ) रिमोट ई–वोटिंग अवधि निम्नानुसार है:

कट–ऑफ तिथि	सोमवार, 22 जून, 2026
ई–वोटिंग का प्रारम्भ	बुधवार, 24 जून, 2026 (प्रातः 09:00 बजे भारतीय समयानुसार)
ई–वोटिंग का समापन	रविवार, 28 जून, 2026 (सांयः 05:00 बजे भारतीय समयानुसार)

वह शेयरधारक सदस्य जिसका नाम कट–ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, वह एजीएम में केवल रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने का हकदार होगा।

रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उसके बाद अक्षम कर दी जाएगी और उपरोक्त तिथि और समय के बाद वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार जब किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिया जाता है, तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान, शेयरधारक सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं।

ब) सदस्यों का वोटिंग अधिकार कट–ऑफ तिथि तक कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगा। कोई व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, उसके लिए एजीएम का यह नोटिस केवल सूचना के उद्देश्य हेतु माना जाएगा।

स) कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम नोटिस के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण की तारीख के बाद इक्विटी रूप शेयर हासिल करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि तक शेयरधारक है, तब वह एजीएम के नोटिस में उल्लिखित दस्तावेज प्रदान करके ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.com पर अपना अनुरोध भेज सकता है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

द) जिन सदस्यों ने एजीएम के आयोजन से पहले ही रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल दिया है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे एजीएम के समय ई–वोटिंग के माध्यम से दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

ध) जिन सदस्यों की ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी/आरटीए/डीपी के साथ पंजीकृत की जा चुकी हैं, वे एजीएम के नोटिस में दिए अनुसार रिमोट ई–वोटिंग के साथ–साथ एजीएम में ई–वोटिंग के निर्देशों का पालन कर सकते हैं।

ङ) किसी मामले में यदि सदस्यों ने इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट और अन्य संचार प्राप्त करने के लिए अपना ईमेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है और/या लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाता का अधिकृत पत्र और केवाईसी को पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, तो कृपया अपने डीमैट में आपके संबंधित डीपी द्वारा उल्लेखित विवरण पंजीकृत/अपडेट कर दें।

च) किसी मामले में, एजीएम से पहले या उसके दौरान किसी भी प्रश्न के मामले में सहायता प्राप्त करने के लिए, आप उन सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) देख सकते है और ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर ऐसे सदस्यों के लिए 'डाउनलोड अनुभाग' पर उपलब्ध जानकारियां देख सकते हैं। आप एनएसडीएल के टोल फ्री नंबर 022–48867000 पर भी संपर्क कर सकते हैं या एनएसडीएल के निर्दिष्ट ई–मेल आईडी: evoting@nsdl.com पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं, जहां पर आपकी सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाएगा।

छ) परिणाम एजीएम के समापन के दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किए जाएंगे और इसे, समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट https://investor.indiamart.com/AGM_EGM-aspx पर 'निवेशक संबंध' के शीर्षक के तहत लोड कर किया जाएगा और परिणाम की घोषणा के बाद एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर बैठक के सभाध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में उपलब्ध किया जाएगा। इसके साथ ही परिणाम, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड पर भी प्रेषित कर दिए जाएंगे, जिन्हें कंपनी की वेबसाइट पर भी डाल दिया जाएगा।

ज) रिमोट ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और तरीका, एजीएम में ई–वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश एजीएम के नोटिस में प्रदान किए जा रहे हैं

कृते इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड
हस्ता/–
मनोज भार्गव
कंपनी सचिव

स्थान: नोएडा
दिनांक: 02 जून, 2026

संपादकीय जागरण

बुधवार, 3 जून 2026 : अधिक ज्येष्ठ कृष्ण - 3 वि. 2083

शिक्षा आदर्श व्यक्तित्व निर्माण का आधार है

शहरों की बिगड़ती सूरत

देश की राजधानी में एक पांच मंजिला भवन गिरने से छह लोगों की मौत और कई के घायल होने के बाद भवन स्वामी की गिरफ्तारी करने के साथ ही नगर निगम के दो इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दे गिए। इस घटना के बाद नगर निगम यह जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर शिकायतों के बाद भी उक्त इमारत में अतिरिक्त मंजिल का अवैध निर्माण कैसे हो रहा था? वह अन्य ऐसी ही इमारतों की छानबीन में भी जुट गया है, लेकिन इसके आसार कम ही हैं कि आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी और अवैध निर्माण का सिलसिला बंद होगा, क्योंकि यदि ऐसा होना होता तो बहुत पहले हो गया होता। आखिर दिल्ली में ऐसी कोई इमारत पहली बार नहीं गिरी, जो अवैध रूप से बनी थी या निर्मित की जा रही थी। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हो चुकी हैं और फिर भी नतीजा ढाक के तीन पात वाला है। ऐसा इसीलिए है, क्योंकि नगर निकाय के अधिकारी-कर्मचारी कुछ ले-देकर अवैध निर्माण होने देते हैं। वे पैसों के लालच में भवन निर्माण संबंधी नियम-कानूनों की अनदेखी करते हैं। इस मामले में जो स्थिति दिल्ली की है, वही शेष देश की भी है।

हमारे हर छोटे-बड़े शहर में अवैध एवं बेतरतीब निर्माण हो रहा है। यह स्थानीय निकायों के संरक्षण और उनकी जानकारी में होता है। इसी कारण शहरों में अवैध तरीके से रिहायशी और व्यावसायिक इमारतों का निर्माण होता रहता है। स्थिति यह है कि जो पुराने भवन दो-तीन मंजिल के होते हैं, वे जर्जर होने के बाद भी अवैध निर्माण के सहारे चार-पांच मंजिलों में तब्दील कर लिए जाते हैं। इससे क्षेत्र विशेष में आबादी का दबाव बढ़ने के साथ नागरिक सुविधाओं का अभाव भी बढ़ता है। अपने देश में ऐसा कोई नियम ही नहीं कि किसी इलाके में कितनी आबादी रहनी चाहिए। इससे भी बड़ी त्रासदी यह है कि हर कहीं रिहायशी इलाके व्यावसायिक इलाकों में तब्दील हो रहे हैं। देश भर में घरों में दुकानें बनाने की होड़ सी कायम है। ऐसा पुराने मोहल्लों के साथ नए मोहल्लों में भी हो रहा है। इसी कारण हमारे शहर बेतरतीब विकास का पर्याय बन गए हैं और वे नागरिक सुविधाओं के अभाव के साथ प्रदूषण एवं गंदगी से घिरते जा रहे हैं। अनियोजित शहर नगरीय जीवन को केवल कष्टकारी ही नहीं बनाते, बल्कि वे विकास में बाधक भी बनते हैं। आज के युग में शहर आर्थिक विकास के इंजन हैं, लेकिन तभी, जब उनका नियोजित ढंग से विकास हो। विडंबना यह है कि जिन नगर निकायों की पहली जिम्मेदारी शहरों के नियोजित विकास को सुनिश्चित करना है, वे उसका ही निर्वाह करने में बुरी तरह नाकाम हैं। यदि शहरों की सूरत संवारनी है और उन्हें विकास का वाहक बनाना है तो स्थानीय निकायों के कामकाज के तौर-तरीकों को पूरी तरह बदलना होगा।

लापरवाह कार्यप्रणाली

दक्षिणी दिल्ली के सैदुलाजाब क्षेत्र में तीन दिन पूर्व पांच मंजिला इमारत ढहने और छह लोगों की जान चली जाने के बाद एमसीडी की नींद टूटी है। क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर सर्वे शुरू किया गया है, जिसके बाद पिछले दो दिन में आठ संपत्तियों को नोटिस जारी कर 72 घंटे में संपत्ति खाली करने को कहा गया है। ये वो संपत्तियां हैं, जिनमें मौके पर अवैध निर्माण होता पाया गया या ये खतरनाक पाई गईं।

सरकार को एजेंसियों के कामकाज की समीक्षा करनी चाहिए और इनको नियोजित विकास में उपयोगी बनाने की दिशा में ठोस प्रयास करने चाहिए

साथ ही एमसीडी ने अवैध निर्माण के रूप में पूर्व में चिह्नित 81 इमारतों में से ऐसी 42 इमारतों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है, जिन पर अब तक कार्रवाई नहीं हो सकी थी। निराशाजनक ये है कि एमसीडी की कार्रवाई तब शुरू हुई, जब हादसे में छह जानें चली गईं। ये आसानी से समझा जा सकता है कि इस सरकारी एजेंसी ने यदि अपना दायित्व ठीक से निभाया होता तो हादसे को रोका जा सकता था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली के अधिकतर क्षेत्रों में अवैध निर्माण की भरमार है। केंद्र व दिल्ली सरकार को डीडीए और एमसीडी के कामकाज की समीक्षा करनी चाहिए और इन सरकारी एजेंसियों को राजधानी के नियोजित विकास में उपयोगी बनाने की दिशा में ठोस प्रयास करने चाहिए।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या अमेरिका-ईरान के बीच कायम युद्धविराम खतरे में पड़ता दिख रहा है?

आज का सवाल

क्या अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने से तमिलनाडु में भाजपा की राह और मुश्किल होगी?

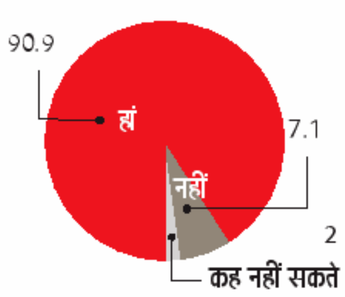

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। (सभी आकड़े प्रतिशत)

गति पकड़ता सेमीकंडक्टर अभियान

हर्ष वी. पंत

भारत अब वैश्विक इलेक्ट्रानिक्स इकोसिस्टम में महज एक उपभोक्ता या असेंबलिंग तक ही सीमित न रहकर स्वयं को एक उत्पादक के रूप में भी स्थापित कर रहा है

वर्तमान दौर में सेमीकंडक्टर की अहमियत किसी से छिपी नहीं रही है। इस संदर्भ में अच्छी बात यह है कि भारत ने भी इसके निर्माण में तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हालिया नीदरलैंड दौरे पर वहां की दिग्गज कंपनी एएसएमएल और टाटा इलेक्ट्रानिक्स के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए है। एएसएमएल को आधुनिक सेमीकंडक्टर निर्माण की रीढ़ मानी जाने वाली उन्नत लिथोग्राफी प्रणालियों के मामले में विश्व के प्रमुख आपूर्तिकर्ता में से एक माना जाता है। यह अनुबंध इसका प्रतीक है कि भारत अब वैश्विक इलेक्ट्रानिक्स इकोसिस्टम में महज एक उपभोक्ता या असेंबलिंग तक ही सीमित न रहकर समूची मूल्य श्रृंखला में स्वयं को स्थापित करने पर ध्यान दे रहा है। यह करार गुजरात के धोलेरा में 11 अरब डालर के निवेश वाले टाटा के प्रस्तावित चिप निर्माण संयंत्र के लिए बेहद अहम है। धोलेरा को भारत के सेमीकंडक्टर हब के रूप में भी देखा जा रहा है।

सेमीकंडक्टर को लेकर भारत का दृष्टिकोण आर्थिक, रणनीतिक और भू-राजनीतिक निहितार्थों से प्रेरित है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इलेक्ट्रानिक्स की खपत में तेजी के चलते देश सेमीकंडक्टर के आयात पर बड़ी हद तक निर्भर है। आज के इस दौर में जहां चिप्स आटोमोबाइल एवं दूरसंचार से लेकर रक्षा प्रणालियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआइ और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे उदीयमान क्षेत्रों की रीढ़ बन चुके हैं, वहां उसकी आधारभूत सामग्री पर बाहरी निर्भरता को घटाना आत्मनिर्भरता के साथ ही आर्थिक सुरक्षा का भी एक अहम अवयव बन गया है। इसका भू-राजनीतिक संदर्भ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वैश्विक सेमीकंडक्टर उत्पादन मुख्य रूप से ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन और अमेरिका में केंद्रित है। कोविड-19 महामारी से लेकर अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी मोर्चे पर तनातनी जैसे पहलुओं ने इस आपूर्ति में गतिरोध पैदा करने का काम किया है। इसने दर्शाया है कि आपूर्ति श्रृंखलाओं का संकेंद्रण कितना भारी पड़ सकता है। इसका ही परिणाम रहा कि प्रमुख वैश्विक विनिर्माताओं और सरकारों ने उत्पादन में विविधता को प्रोत्साहन देने के लिए चीन से इतर उत्पादन की 'चीन प्लस वन' वाली नीति को अपनाया। इस क्रम में अपने बड़े बाजार, जनसांख्यिकीय गहराई और बढ़ते भूराजनीतिक महत्व के चलते भारत स्वयं को एक आकर्षक वैकल्पिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत कर रहा है।

रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो

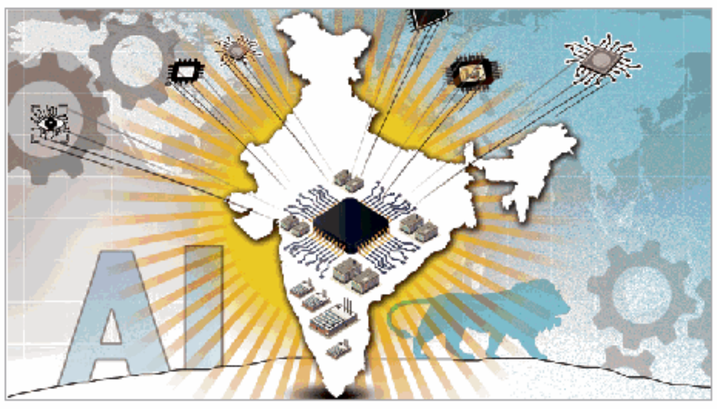

अवधेश राजपूत

सेमीकंडक्टर निर्माण के निहितार्थ केवल वाणिज्यिक हितों तक सीमित नहीं हैं। सुरक्षित और विश्वसनीय चिप आपूर्ति श्रृंखलाओं पर नियंत्रण का पहलू अब राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी गहराई से जुड़ा है। विशेष रूप से रक्षा इलेक्ट्रानिक्स, साइबर बुनियादी ढांचे, दूरसंचार और एआइ संचालित तकनीकों जैसे क्षेत्रों में। इसी कारण सेमीकंडक्टर परिदृश्य महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के एक नए मोर्चे के रूप में उभरा है और इस क्षेत्र में भारत का प्रवेश बदलती वैश्विक वास्तविकताओं को स्वीकारने के उसके रवैये को ही रेखांकित करता है। नई दिल्ली ने इसी को ध्यान में रखकर अपना नीतिगत ढांचा भी तैयार किया है। इसके अंतर्गत 76,000 करोड़ रुपये के आवंटन वाले इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी आइएसएम, स्वीकृत चिप निर्माण परियोजनाओं के लिए 50 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता जैसी पहल की गई हैं। शायद ही विश्व में कहीं और ऐसे प्रोत्साहन दिए गए हैं। केंद्रीय बजट में भी आइएसएम 2.0 के दायरे का विस्तार करते हुए सेमीकंडक्टर उपकरण, सामग्री, बौद्धिक संपदा विकास, आपूर्ति श्रृंखला में लचीलेपन और शोध एवं विकास यानी आरएंडडी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्पष्ट है कि भारत की रणनीति अपनी छितरी हुई क्षमताओं को एकीकृत कर उसका लाभ उठाने पर केंद्रित है।

सेमीकंडक्टर अभियान से जुड़ी कई परियोजनाएं अब धरातल पर साकार होने लगी हैं। गुजरात इन गतिविधियों का गढ़ बना हुआ है। धोलेरा में टाटा-पावरचिप फैब्रिकेशन परियोजना तो साणंद में माइक्रोन की एटीएमपी इकाई स्थापित हो रही हैं। असम को टाटा की ओसैट परियोजना हासिल करने में सफलता मिली है, जबकि उत्तर प्रदेश नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एचसीएल-फाक्सकान संयुक्त उपक्रम के माध्यम से स्वयं को इस परिदृश्य पर मजबूती से उभारने में लगा है। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 तो बाकायदा दर्शाती है कि राज्य सरकारें किस प्रकार अतिरिक्त पूंजीगत सब्सिडी, कर छूट, भूमि दरों में रियायत, बिजली रियायत और कौशल विकास पहलों के माध्यम से केंद्रीय प्रोत्साहनों की पूरक बनकर इस प्रक्रिया को रफ्तार दे रही हैं। केंद्रीय रणनीतिक दूरदर्शिता और राज्यस्तरीय प्रतिस्पर्धा के बीच का यह तालमेल धीरे-धीरे भौगोलिक रूप से एक व्यापक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को तैयार कर रहा है।

कई स्तरों पर प्रगति के बावजूद इस राह में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। चिप निर्माण उन उद्योगों में से एक है, जिनके लिए व्यापक स्तर पर पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। पानी की भरोसेमंद एवं सतत आपूर्ति, बिजली की निरंतर उपलब्धता, कुशल कामकाजी आबादी एवं सक्षम आपूर्ति तंत्र का सुनिश्चित होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान विश्व में निर्यातों को लेकर जिस तरह के नियंत्रण एवं भू-राजनीतिक तनाव, खेमेबंदी और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, उसके प्रभाव से यह क्षेत्र भी अछूता नहीं। इन पहलुओं के सम्मिलित प्रभाव भी इस क्षेत्र के भविष्य की दशा-दिशा को प्रभावित करेंगे।

देखा जाए तो टाटा-एसएमएल अनुबंध, माइक्रोन संयंत्र के संचालन और आइएसएम 2.0 के साथ स्पष्ट है कि भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति संकल्पना के स्तर से वास्तविकता का आकार ग्रहण करने लगी है। इससे एक दीर्घकालिक औद्योगिक क्रांति की बुनियाद रखी जा रही है। वैश्विक सेमीकंडक्टर परिदृश्य में स्वयं को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत कर रहे भारत को इससे केवल आर्थिक लाभ ही नहीं मिलेंगे, बल्कि वह रणनीतिक स्वायत्तता भी प्राप्त होगी, जहां तकनीकी क्षमताएं शक्ति संतुलन में अहम भूमिकाएं निभाने लगी हैं।

(लेखक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

12 बरस की सफलताएं और विफलताएं

राजीव सचान

मोदी सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाते समय इस पर भी ध्यान दे कि उसके हिस्से में कुछ नाकामियां भी हैं

विफलताओं पर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी ● फाइल

मोदी सरकार अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे करने जा रही है। यह तय है कि इस अवसर पर उसकी ओर से अपनी उपलब्धियों का बखान किया जाएगा। इसके लिए भाजपा की ओर से एक अभियान चलाया जाने वाला है, जिसमें लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। निःसंदेह मोदी सरकार के पास अपनी उपलब्धियों के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है और यह हर सरकार का अधिकार है कि वह उनके बारे में जनता को अवगत कराए। यदि मोदी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करें तो उनकी एक लंबी सूची है। इन उपलब्धियों में कई ऐसे साहसिक फैसले हैं, जिनमें से कुछ के बारे में यह कल्पना करना कठिन था कि कोई सरकार ऐसे फैसले ले पाएगी, जैसे जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना, पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक करना और फिर आपरेशन सिंदूर। ये दोनों सैन्य अभियान इस मायने में विशेष रहे कि विश्व में पहली बार किसी परमाणु हथियार संपन्न देश ने दूसरे ऐसे ही देश पर हवाई हमले किए। हालांकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया, लेकिन यदि मोदी सरकार नहीं होती तो शायद यह रास्ता बाधित ही रहता और राम मंदिर का निर्माण आनन-फानन नहीं होता। मोदी सरकार अपने तीसरे कोर एजेंडे समान नागरिक संहिता की दिशा में भी आगे बढ़ रही है।

जीएसटी लागू होना भी इस सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। वैसे तो नोटबंदी भी एक साहसिक फैसला था, लेकिन इसके वैसे सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुए, जैसे अपेक्षित थे। माओवाद का खात्मा भी मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ वर्षों पहले तक माओवाद का खात्मा असंभव सा दिखता था, पर मोदी सरकार और विशेष रूप से गृह मंत्री अमित शाह ने इसे संभव कर दिखाया और वह भी तय समय में। पिछले 12 वर्षों में आधारभूत ढांचे के निर्माण में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई है। देश भर में सड़कों का तेजी से निर्माण हुआ है। इसी तरह पुल, बिजलीघर, हवाई अड्डे निर्मित हुए हैं और रेल सुविधाओं का विकास हुआ है। ग्रामीण विकास की योजनाओं ने भी रफ्तार पकड़ी है। देश में डिजिटलीकरण भी द्रुत गति से हुआ है। इसके चलते भारत डिजिटल लेनदेन के मामले में विश्व में अग्रणी है। विकास के साथ ही प्रभावशाली जनकल्याणकारी योजनाओं की भी एक लंबी सूची है। इन योजनाओं ने आम आदमी का जीवन बदला है। शौचालय निर्माण, उज्ज्वला, आवास, बिजली, आयुष्मान, किसान सम्मान निधि, मुफ्त राशन संबंधी जैसी योजनाओं ने सचमुच लोगों को लाभान्वित किया है। जनधन योजना निर्धन जनता के वित्तीय समावेशन की एक बड़ी मिसाल हैं। इन योजनाओं के चलते करोड़ों लोगों को गरीबी के दायरे से बाहर निकालने में मदद मिली है। मोदी सरकार ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि उसे जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करना आता है। इन 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी बहुत काम हुआ है।

यदि आज भाजपा के नेतृत्व वाली राजग की 22 राज्यों में सरकारें हैं तो इसका एक बड़ा कारण मोदी सरकार की रीति-नीति है। भाजपा कुछ अजेय समझे जाने वाले राज्यों में अपनी सरकार बनाने में सफल रही है। आज विपक्ष के लिए उसका मुकाबला करना कठिन हो रहा है। कोई भी सरकार हो, उसकी प्रत्येक योजना कसौटी पर खरी नहीं उतरती। ऐसा ही मोदी सरकार की कुछ योजनाओं के साथ हुआ है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकी हैं। किसानों की आय दोगुनी करने का भी लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। आम तौर पर हर सरकार के समय महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे रहते हैं। मोदी सरकार के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं।

अब जब मोदी सरकार अपने 12 साल की उपलब्धियों का गुणगान करने में जुटने वाली है, तब किसी को उसका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहिए कि कुछ ऐसे मोर्चों पर उसे विफलता हाथ लगी है, जिनमें उसे सफलता अर्जित करनी चाहिए थी, जैसे शिक्षा और परीक्षाओं की सूरत बदलनी चाहिए थी, लेकिन नई शिक्षा नीति के बाद भी शिक्षा का हाल संतोषजनक नहीं और परीक्षाओं, विशेषरूप से प्रतियोगी परीक्षाओं का हाल तो बहुत ही बुरा है। इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारें एक ही नाव पर सवार हैं। रह-रहकर प्रश्नपत्र लीक होते रहते हैं। मोदी सरकार की एक बड़ी विफलता न्याय को सुलभ और सुगम न बना पाना है। लचर न्यायिक तंत्र देश के विकास में एक बड़ी बाधा है। इसी तरह की एक बड़ी बाधा सरकारी कामकाज में व्याप्त भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार लाइलाज हो गया दिखता है। जहां निर्माण वहां तो भ्रष्टाचार है ही, इसके अलावा जहां कहीं भी सरकारी अनुमति, अनुमोदन आदि की आवश्यकता होती है, वहां भी लेन-देन होता है। स्मार्ट सिटी योजना भी कुल मिलाकर नाकाम ही रही और हमारे शहर बेतरतीब विकास की कहानी कहने के साथ विकसित भारत के लक्ष्य का बड़ी बाधा बने हुए हैं। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि मोदी सरकार अपनी 12 बरस की उपलब्धियों को गिनाते समय इस पर गंभीरता से ध्यान दे कि उसे कुछ विफलताएं भी हाथ लगी हैं, जिनके कारण देश में बेचैनी बढ़ रही है।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

धर्म का मर्म

धर्म एक ऐसा विशाल छत्र है, जिसकी छाया में पूरा संसार क्रियाशील है। ये धर्म ही है, जो जगत को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए एक अदृश्य संविधान के रूप में संसार में व्याप्त है। यही अनंतकाल से भौतिक संसार को निर्बाध बांधे हुए है। धर्म की विकृत तथा संकुचित परिभाषा ने हमें यह विश्वास दिला दिया है कि धर्म का अभिप्राय मात्र मत या पंथ से है। वास्तविकता में तो धर्म वह अटल एवं शाश्वत सिद्धांत है, जिसके माध्यम से संसार की हर क्रिया संचालित होती है। ग्रहों का धर्म है एक निश्चित गति पर सूर्य की परिक्रमा करना, ऋतुओं का धर्म है अपने स्वभाव अनुसार फल देना, वृक्ष का धर्म है छाया तथा फल देना। संपूर्ण प्रकृति धर्मोचित व्यवहार करती है। पशु भी अपनी संरचना के अनुसार धर्म का पालन करते हैं।

मानव के संबंध में धर्म का मर्म बहुत व्यापक है। मानव के अतिरिक्त संपूर्ण जगत का धर्म एक धुरी से बंधा हुआ है, किंतु मानव का धर्म और व्यवहार देश-काल एवं परिस्थिति के सापेक्ष भी है। उसे इस कसौटी पर खरा भी उतरना है, क्योंकि यदि व्यक्ति परिस्थिति के अनुरूप धर्मोचित व्यवहार न करे तो वह अधर्म है। इस कारण भी कि मानव के पास ही वह विवेक है जो तय करता है कि उसके लिए किस समय क्या धर्म है। यहां प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि धर्म का अनुपालन आवश्यक क्यों है? वस्तुतः, धर्म ही वह महीन रेखा है जो उचित तथा अनुचित को अलग करती है। इसके अभाव में समाज अनियंत्रित होकर पशुवत हो जाएगा।

मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का समग्र जीवन एक आदर्श धर्मोचित जीवन का जीवंत उदाहरण है। तभी हम कहते हैं 'रामो विग्रहवान धर्मः' अर्थात राम ही धर्म का विग्रह स्वरूप हैं। अतः जीवन में धर्म का पालन कर्तव्य से मुक्ति के लिए आवश्यक है। महाभारत की शिक्षा है 'यतो धर्मस्ततो जयः' अर्थात जहां धर्म है, वहीं विजय है और विजयश्री का आलिंगन धर्म की परिधि में ही संभव है। धर्म ही उत्थान है और अधर्म ही पतन।

आदित्य नारायण अवस्थी

पाठकनामा

pathaknama@nda.jagran.com

शिक्षा के स्तर में हो सुधार

'अविश्वास से घिरती जा रही परीक्षाएं' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में जगमोहन सिंह राजपूत ने परीक्षा व्यवस्था पर गहराते अविश्वास, नकल, प्रश्नपत्र लीक तथा नैतिक मूल्यों के क्षरण की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। निःसंदेह यह चिंता समयोचित है, किंतु इस संकट की जड़ें परीक्षा कक्षों से कहीं अधिक गहरी हैं। यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि सामाजिक अपेक्षाओं, आर्थिक असमानताओं और शिक्षा की बदलती प्राथमिकताओं का भी परिणाम है। वर्तमान समय में परीक्षा ज्ञानार्जन का साधन कम और आजीविका का प्रवेशद्वार अधिक बन गई है। करोड़ों युवा सीमित अवसरों के लिए संघर्षरत हैं। जब नियुक्तियां वर्षों तक लंबित रहें, प्रतियोगिता असंतुलित हो और सफलता का एकमात्र मानदंड अंक बन जाएं, तब व्यवस्था के प्रति संशय स्वाभाविक है। दुर्भाग्य यह है कि हम परिणामों पर विमर्श करते हैं, कारणों पर नहीं। एक तथ्य यह भी है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व निर्माण, विवेक और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास माना गया था, किंतु आज वह अंकों और प्रमाणपत्रों की प्रतिस्पर्धा में सिमटती जा रही है। कोचिंग-केंद्रित संस्कृति ने जिज्ञासा का स्थान स्मरणशक्ति को और ज्ञान का स्थान परीक्षा-कौशल को दे दिया है। ऐसी स्थिति में अनैतिक साधनों का आकर्षण बढ़ना अस्वाभाविक नहीं। समाधान केवल कठोर दंड में नहीं, बल्कि विश्वास की पुनर्स्थापना में निहित है। भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया जाए। विद्यालयों में नैतिक शिक्षा, तार्किक चिंतन और कौशल विकास को समान महत्व मिले। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाकर युवाओं की अनिश्चितता कम की जाए। परीक्षा तभी विश्वसनीय बनेगी, जब व्यवस्था निष्पक्ष, अवसर पर्याप्त और समाज ईमानदारी को सफलता से अधिक सम्मान देने लगेगा।

awanishg30@gmail.com

लोभ सबसे बड़ा शत्रु

मानव जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति, सद्गुणों का विकास और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह भी है। मनुष्य के भीतर अनेक प्रकार की इच्छाएं और आकांक्षाएं होती हैं। इच्छाएं जीवन को गति देती हैं और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती हैं, किंतु जब यही इच्छाएं सीमा का अतिक्रमण कर लेती हैं और केवल अधिक से अधिक प्राप्त करने की अंधी दौड़ में परिवर्तित हो जाती हैं, तब वे लोभ का रूप धारण कर लेती हैं। लोभ या लालच मनुष्य के समस्त सद्गुणों को नष्ट कर देता है और उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं तथा दुखों का कारण बनता है। इसी कारण सभी धर्मों और महान विचारकों ने लोभ को पापों की जड़ तथा मानव पतन का प्रमुख कारण बताया है। लोभ का अर्थ है आवश्यकता से अधिक पाने की तीव्र और अनियंत्रित इच्छा। सामान्य इच्छाएं मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक होती हैं, परंतु जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से आगे बढ़कर केवल संग्रह, स्वार्थ और भौतिक संपत्ति को ही जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तब लोभ उत्पन्न होता है।

कांतिलाल मांडोत, नई दिल्ली

युवाओं के सपनों का हनन

लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। महान कवि हरिवंशराय बच्चन के यह बोल दुनिया में आने वाली कठिनाइयों से यथार्थ का परिचय कराती हैं। उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है, परंतु जब यही उम्मीदें कड़वे एवं भ्रष्टाचारी संसार द्वारा धराशायी की जाती हैं तब उनका क्या होता है। जो उस विचार से अपने सपने बुनते हैं? देश में बढ़ते पेपर लीक मामले होनहारों के सपनों का हनन कर रहे हैं। अमीर एवं प्रभावशाली व्यक्ति घूस का लेन-देन करके, प्रभाव का लाभ उठाकर "भ्रष्टाचारी" सोच को शरण देते हैं और देश में श्रेष्ठ व सच्चे दावेदारों की जगह हड़पते है। भारत जैसे देश, जहां युवाओं में उनके कलात्मक विचारों की भरमार है, वहां ये युवा ऐसे मंच को तलाशने की कोशिश करते हैं, जहां उनके विचार देश की प्रगति की दौड़ में तेजज भागीदार बन सकें। इसलिए यहां परीक्षाओं में प्रतिद्वंद्विता भी बहुत है, जिससे श्रेष्ठ एवं पद के सही दावेदारों को चुना जा सके। इन सभी प्रणालियों से बचने के लिए लोग "पेपर लीक" करते हैं। बच्चे प्रतिकूल परिस्थितियां झेलकर परीक्षा की तैयारी करते हैं। अपनी मेहनत को इस तरह धूमिल होते देख कई बच्चे सह नहीं पाते और आत्महत्या जैसे गलत एवं कठोर कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। पेपर लीक होने के बाद जिस तरह से प्रणाली दूसरी बार सख्त, पारदर्शी व उचित रूप से परीक्षा कराती है, वह पहले ही कदम उठाकर नहीं कराई जा सकती?

सहर्षी मिश्रा, ग्रेटर नोएडा

पोस्ट

भारतीय इतिहास, राजनीति पर शोध करने वाले अधिकांश पश्चिमी शिक्षाविद शोधार्थी नहीं राजनीतिक कार्यकर्ता हैं।

अभिनव प्रकाश@Abhina_Prakash

पाठ्यक्रम और परीक्षा के बीच अंतर की भरपाई करने वाले तंत्र का नाम ही कोचिंग है। सरकार इस गैप को भर दे तो कोचिंग का क्या काम? लिहाजा कोचिंग वाले टीचर्स को गाली देने से कुछ नहीं होने वाला, सिस्टम में सुधार चाहते हैं तो दबाव नीति निर्धारकों पर बनाइए।

मधुरेंद्र कुमार@Madhurendra13

यह बात सोलह आने सच है कि टीवी पत्रकारों वाली बीमारी आनलाइन अध्यापकों को भी लग गई और वह बीमारी है लोकप्रियता का रोग। जबकि सही बात अलोकप्रिय भी होती है। वायरल के मोह से आगे बढ़ना ही होगा। तमाशा पत्रकारिता का विकल्प तमाशा शिक्षा नहीं।

संकेत उपाध्याय@sanket

तमिलनाडु में अन्नामलाई को किनारे करके भाजपा सही नहीं कर रही। वैसे, यह पहली बार नहीं है जब पार्टी में अपनी प्रतिभाओं को उपेक्षित और दोयम दर्जे के बाहरी नेताओं को उपकृत किया जा रहा हो।

मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

जनपथ

साईं कबहुं न कीजिए 'इतने बढ़िया' काम,
हेलमेट में चलना पड़े हो करके बदनाम।
हो करके बदनाम लोग बरसाएं अंडे,
दौड़ाएं कुछ लोग हाथ में लेकर डंडे!
करि मनमाना काम स्वयं हित खोदे खाई,
अब तो मालिक राम बचाएं 'उनको' साईं!!

-ओम प्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 120 - 4615800, E- mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 319

जब तक जीना, तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है।

– स्वामी विवेकानंद

बेलगाम अपराध

उत्तर प्रदेश में हाल में हत्या की कई घटनाओं से साफ है कि अपराध पर काबू करने के सरकारी दावों के बरक्स हकीकत क्या है। ऐसा लगता है कि कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर राज्य की सरकार और पुलिस बेफिक्र है और दूसरी ओर अपराधियों का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है। यह बेवजह नहीं है कि हत्या की लगातार कई वारदात के बाद विपक्षी दलों की ओर से सरकार को कठघरे में खड़ा किया जाने लगा है। दरअसल, बीते कुछ दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश में एशियाई खेलों के लिए चुने गए एक पैरा-एथलीट और एक राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी महिला खिलाड़ी सहित हत्या की अन्य घटनाओं के बाद सरकार इस बात के लिए आलोचना के कठघरे में है कि क्या राज्य की कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हाल में पिछले कुछ समय से लगातार बड़ी आपराधिक घटनाओं की वजह से खुद मुख्यमंत्री योगी के भीतर काफी नाराजगी देखी गई और उन्होंने ज्यादा अपराध दर वाले जिलों के पुलिस अधिकारियों को सख्त हिदायत दी।

सवाल है कि क्या केवल सख्ती के दावे और हिदायतों के दम पर राज्य में अपराध और आपराधिक मानसिकता वाले लोगों पर काबू पाया जा सकता है। अगर ऐसा संभव हो पाता, तो आज राज्य सरकार जघन्य अपराधों में तेज बढ़ोतरी के लिए खुद को आलोचना के घेरे में खड़ी नहीं पाती। जब उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था, तब भाजपा का वादा यही था कि वह राज्य को अपराध और अपराधियों से मुक्त कराएगी। अपराधियों पर काबू पाने के मकसद से की गई कुछ फौरी सख्ती और कार्रवाइयों से ऐसा लगा भी। मगर हत्या या अन्य किसी जघन्य अपराध के आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराए जाने के कुछ मामलों में पुलिस के रवैये पर सवाल भी उठे। आज एक समांतर सच यह भी है कि आपराधिक मानसिकता के लोग बेधड़क सामान्य से लेकर जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और अपराध के खात्मे का दावा करने वाली सरकार अपराधियों को रोक पाने में नाकाम दिख रही है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के भीतर पुलिस का खौफ खत्म हो गया है।

अपराध के बेलगाम होते जाने के बीच अब ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिनमें हत्या की वजहें हैरान करती हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में राष्ट्रीय स्तर की एक कबड्डी खिलाड़ी की हत्या सिर्फ छत्तीस सौ रुपए के उधार की वजह से कर देने की खबर आई। इस घटना में भी पहला सवाल यही है कि आरोपी के भीतर आखिर क्यों पुलिस और कानूनी कार्रवाई का कोई खौफ नहीं था। दूसरे, कोई व्यक्ति अपने लिए तीन-चार हजार रुपए को इतनी बड़ी रकम कैसे मान लेता है कि वह उसके लिए किसी की हत्या कर दे। उत्तर प्रदेश की इस घटना के अलावा देश के अलग-अलग हिस्सों से अक्सर ऐसी खबरें आती हैं, जिनमें दो-चार या पांच सौ रुपए जैसी मामूली रकम के लिए किसी की जान ले ली जा रही है। क्या देश में यह एक नई तस्वीर बन रही है कि आर्थिक असुरक्षा और बदहाली की स्थिति लोगों के मनोविज्ञान पर गहरा और घातक असर डाल रही है? जाहिर है, आदतन या सुविधा से अपराध करने वालों के खिलाफ सख्ती के साथ-साथ सामान्य पृष्ठभूमि के लोगों के जघन्य अपराधों को अंजाम देने की परिस्थितियों और वजहों पर विचार करना वक्त की जरूरत है। बिना जड़ पर प्रहार किए अपराध पर पूरी तरह काबू पाना एक चुनौती बनी रहेगी।

बाधित शांति

ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम की उम्मीद बंधती है और फिर टूट जाती है। यह स्थिति युद्ध शुरू होने के बाद से ही जारी है। पिछले तीन महीने से युद्ध चल रहा है, लेकिन जब शांति वार्ता की बात आती है, तो आमने-सामने और दूरगामी स्थितियों को ध्यान में रख कर संवाद करने की जरूरत नहीं समझी जाती। अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत किसी सहमति के बिंदु पर नहीं पहुंच रही, तो इसे समझने की जरूरत है। दोनों पक्ष जिस तरह अपनी शर्तों पर अड़े हैं, उससे वैश्विक शांति को तो खतरा है ही, दुनिया भर में ऊर्जा संकट भी गहरा रहा है। गौरतलब है कि ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही अप्रत्यक्ष वार्ता स्थगित कर दी है। उसने क्षेत्रीय तनाव बढ़ने पर यह कदम उठाया है। यह निराशाजनक ही है कि एक तरफ कूटनीतिक कदम उठाने की बात की जाती है, फिर अचानक हमले की स्थिति पैदा कर दी जाती है। पिछले सप्ताह के आखिर में भी अमेरिका ने ईरान के भीतर कई ठिकानों पर बमबारी की। इसके अलावा, लेबनान पर इजराइल के लगातार हमले से ईरान नाराज है और वह चाहता है कि ये हमले रोक दिए जाएं।

हालांकि यह मुद्दा युद्धविराम की मुख्य शर्तों में शामिल है। मगर सवाल है कि अमेरिका युद्धविराम को ताक पर रख कर खुद को या इजराइल को हमले करने से क्यों नहीं रोक पा रहा है। इसमें दोराय नहीं कि अगर दोनों पक्ष गंभीरता से कूटनीतिक पहल करते, तो शांति का कोई रास्ता निकल सकता था। मगर जैसे ही बात आगे बढ़ती है, उसमें दबाव बढ़ाने के साथ रणनीतिक शर्तें जोड़ दी जाती हैं। इससे संवाद के पुल गिर जाते हैं। मौजूदा स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ईरान ने होर्मुज जलमार्ग पर अपना दबदबा बढ़ाने और उसे सख्ती से बंद करने का संकेत दिया है। समझौते की कवायद कई दिनों से चल रही है, लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल रहा, तो आखिर इसकी क्या वजह है। स्पष्ट है कि एक तरफ समझौते की बात की जाती है, दूसरी ओर सैन्य विकल्प चुनने की धमकी दी जाती है। इस द्वंद्व के बीच शांति कायम होने के सभी दावे धरे रह जाते हैं। बेहतर हो कि अमेरिका और ईरान स्थायी युद्धविराम और शांति की ओर कदम बढ़ाएं। सैन्य टकराव से आखिरकार कोई समस्या हल नहीं होती।

महिलाओं की सेहत के उपेक्षित प्रश्न

आज दुनिया के अनेक देशों में महिलाएं पहले की तुलना में ज्यादा दीर्घायु जीवन जी रही हैं। मगर यह भी सच है कि लंबी उम्र के बावजूद उन्हें समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।

अमरपाल शर्मा

दुनिया भर में व्यापक बदलाव हो रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान ने असाध्य कही जाने वाली कई बीमारियों पर काबू पा लिया है। औसत आयु बढ़ी है और तकनीक ने इलाज को पहले से कहीं अधिक आधुनिक और आसान बना दिया है। आज भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में महिलाएं पहले की तुलना में दीर्घायु जीवन जी रही हैं। मगर यह भी सच्चाई है कि लंबी उम्र के बावजूद महिलाओं को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन की हाल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार करोड़ों महिलाएं आज भी ऐसी जिंदगी जी रही हैं, जिसमें दर्द है, उपेक्षा है, गलत इलाज है और एक ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो अब भी पुरुष शरीर को 'मानक' मान कर चलती है। दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं में प्रगति होने के बावजूद महिलाओं के लिए समान और संवेदनशील इलाज अब भी एक चुनौती है। विश्व में महिलाओं की औसत आयु लगभग 73.8 वर्ष है, जो पुरुषों की औसत आयु करीब 68.4 वर्ष से अधिक है। फिर भी उनके जीवन का लगभग पच्चीस फीसद से अधिक समय खराब सेहत के साथ गुजरता है। यानी महिलाएं लंबे समय तक पुरानी बीमारियों और लगातार पीड़ा से त्रस्त रहती हैं। वे कई बार बिना इलाज या गलत निदान से भी जूझती हैं।

सवाल है कि आखिर महिलाओं के लिए अनुकूल और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं क्यों संभव नहीं हो पा रही हैं? क्यों महिलाओं और पुरुषों के लिए समान स्वास्थ्य सेवाएं विकसित नहीं की जा रही हैं? अगर इन सवालों का जवाब ईमानदारी से तलाशें, तो इस स्थिति के पीछे पितृसत्तात्मक सोच है, जिसमें महिलाओं को कमतर आंका जाता है और उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। शिक्षित और आर्थिक रूप से सक्षम महिलाएं भी इससे बच नहीं पा रहीं। वे लगातार चिकित्सा पूर्वाग्रहों का सामना करती हैं। कई बार उनकी पीड़ा को 'भावनात्मक', 'हार्मोन संबंधी' या सामान्य कह कर टाल दिया जाता है। यही कारण है कि महिलाओं की सेहत का सवाल अब केवल चिकित्सा का विषय नहीं रहा, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता का सवाल भी बन चुका है।

संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की अनेक संरचनाएं महिलाओं को केंद्र में रख कर नहीं बनाई गईं। इसे केवल अस्पतालों की कमी कह कर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि यह उस सोच का परिणाम है जिसमें पुरुष शरीर को 'सामान्य' और महिला शरीर को 'विशेष परिस्थिति' मान लिया जाता है।

दुनिया भर में हृदय रोग महिलाओं की मौत की सबसे बड़ी वजहों में शामिल है, लेकिन दिल के दौरे के जिन 'सामान्य' लक्षणों को चिकित्सा जगत लंबे समय से पहचानता रहा है, वे अधिकतर पुरुषों के अनुभवों पर आधारित रहे हैं। महिलाओं में दिल की बीमारी के संकेत कई बार अलग रूप में सामने आते हैं। अत्यधिक थकान, मितली, सांस फूलना, पीठ या जबड़े में दर्द जैसे लक्षणों को अक्सर गंभीरता से नहीं लिया जाता। यही वजह है कि महिलाओं में हृदय रोग का पता अक्सर देर से चलता है। दिल का दौरा पड़ने के बाद महिलाओं में मृत्यु का खतरा पुरुषों की तुलना में अधिक देखा जाता है। कई मामलों में उनकी शिकायतों को सामान्य मान कर अस्पताल से वापस भेज दिया जाता है, जिससे स्थिति गंभीर हो जाती है। इसी तरह माहवारी, माइग्रेन, हार्मोन असंतुलन और रजोनिवृत्ति जैसी समस्याओं को अक्सर 'सामान्य' कह कर टाल दिया जाता है। लाखों महिलाएं वर्षों तक दर्द सहती रहती हैं। इस कारण कई बार उनकी गंभीर बीमारियां छिपी रह जाती हैं।

> सवाल है कि महिलाओं के लिए अनुकूल और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं क्यों संभव नहीं हो पा रही हैं? क्यों महिलाओं और पुरुषों के लिए समान स्वास्थ्य सेवाएं विकसित नहीं की जा रही हैं? अगर इन सवालों का जवाब ईमानदारी से तलाशें, तो इस स्थिति के पीछे पितृसत्तात्मक सोच है, जिसमें महिलाओं को कमतर आंका जाता है। शिक्षित और आर्थिक रूप से सक्षम महिलाएं भी इससे बच नहीं पा रहीं। वे लगातार चिकित्सा पूर्वाग्रहों का सामना करती हैं। कई बार उनकी पीड़ा को 'भावनात्मक', 'हार्मोन संबंधी' या सामान्य कह कर टाल दिया जाता है। यही कारण है कि महिलाओं की सेहत का सवाल अब केवल चिकित्सा का विषय नहीं रहा, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता का सवाल भी बन चुका है।

अगर भारत की स्थिति पर नजर डालें, तो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में मातृत्व पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया गया है। गर्भावस्था, प्रसव और शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं में सुधार भी हुआ है। जननी सुरक्षा योजना, आशा कार्यकर्ता और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने जैसी पहलों ने सकारात्मक प्रभाव डाला है, लेकिन समस्या यह है कि महिला स्वास्थ्य को अब भी 'मातृत्व' तक सीमित कर दिया जाता है। जबकि एक महिला की पहचान केवल मां के रूप में ही नहीं होती। किशोरावस्था, कामकाजी जीवन, मानसिक स्वास्थ्य, वृद्धावस्था और रजोनिवृत्ति से जुड़ी उसकी जरूरतों पर अब भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा।

'द लांसेट' में प्रकाशित एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार पिछले तीन दशकों में दुनिया भर में मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। हालांकि हाल के वर्षों में इस सुधार की रफ्तार धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। वर्ष 2023 में दुनिया भर में लगभग करीब ढाई लाख महिलाओं की मौत गर्भावस्था और प्रसव से जुड़ी जटिलताओं के कारण हुई। इससे स्पष्ट है कि आज भी अनेक देशों, विशेषकर निम्न और मध्य आय वाले देशों में मातृत्व महिलाओं के लिए जोखिम भरा है। भारत उन देशों में शामिल है जहां मातृ मृत्यु के मामले सबसे अधिक दर्ज किए जाते हैं। वर्ष 2023 में देश में करीब 24,700 महिलाओं की मृत्यु गर्भावस्था और प्रसव से संबंधित कारणों से हुई।

मानसिक स्वास्थ्य के मामले में भी महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। घरेलू दबाव, आर्थिक निर्भरता, हिंसा, सामाजिक अपेक्षाएं और लगातार श्रम उनके मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करते हैं। फिर भी बड़ी संख्या में महिलाएं अवसाद, चिंता और मानसिक थकान का इलाज नहीं करा पातीं। इसका कारण केवल संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि सामाजिक सोच भी है। महिलाओं की तकलीफ को अक्सर कमजोरी, ज्यादा सोचने की आदत या घरेलू चिंता कह कर नजरअंदाज कर दिया जाता है। गांवों में स्थिति और जटिल है। वहां स्वास्थ्य सुविधाओं की दूरी, महिला चिकित्सकों की कमी, आर्थिक निर्भरता और सामाजिक संकोच मिल कर महिलाओं के लिए इलाज को कठिन बना देते हैं। कई परिवारों में पुरुष सदस्यों की बीमारी को लेकर ही चिंता की जाती है। जबकि महिलाएं तब तक इलाज नहीं करातीं, जब तक स्थिति गंभीर न हो जाए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से बार-बार यह बात सामने आई है कि देश में बड़ी संख्या में महिलाएं एनीमिया और कुपोषण की शिकार हैं।

ऐसे में हालात बदलने के लिए कदम उठाने होंगे। विद्यालय स्तर पर किशोरियों को स्वास्थ्य, पोषण और मानसिक स्थिति के बारे में जरूरी शिक्षा दी जानी चाहिए। माहवारी और प्रजनन स्वास्थ्य को शर्म के बजाय जब सामान्य स्वास्थ्य की तरह देखा जाएगा, तभी स्थितियां बदलेंगी। कार्यस्थलों पर महिलाओं के स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए संवेदनशील नीतियां बनानी होंगी। वृद्ध महिलाओं के स्वास्थ्य को भी सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति में अधिक महत्त्व देना होगा, क्योंकि अक्सर उनकी समस्याओं को 'उम्र का असर' कह कर टाल दिया जाता है। हमें यह समझना होगा कि महिला स्वास्थ्य केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है।

एक अस्वस्थ महिला का असर पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। अगर महिलाएं लगातार बीमारी, थकान और मानसिक दबाव में जी रही हों, तो उसका प्रभाव अगली पीढ़ी तक जाता है। बीमार और थकी हुई महिलाओं के सहारे कोई समाज लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रह सकता। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन असली प्रगति तभी मानी जाएगी जब महिलाएं केवल दीर्घायु ही नहीं बल्कि सम्मानजनक, स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी सकेंगी।

दूसरा सूर्योदय

अनंतपद्मनाभन

मानवीय जीवन के पारंपरिक नजरिए में सेवानिवृत्ति को अक्सर एक 'पूर्ण विराम' के रूप में देखा जाता है। दशकों की मेहनत के बाद समाज इसे एक अंतिम विदाई मान लेता है। हमें बचपन से ही यह मानने की आदत डाल दी गई है कि साठ साल के बाद का समय केवल शारीरिक गिरावट और घर के एकांत में सिमटने का काल है। हालांकि, जागरूक लोगों के लिए सेवानिवृत्ति अब एक पूर्ण विराम नहीं, बल्कि एक 'अल्पविराम' सिद्ध हो रही है। यह केवल आराम का समय नहीं, बल्कि व्यक्तिगत विकास और समाज के प्रति एक नए योगदान का महत्त्वपूर्ण अवसर है। समय का यही नया उपयोग हमारे पूरे दृष्टिकोण को बदल देता है। सेवानिवृत्ति हमें वह कीमती उपहार देती है, जिसे हमने अपनी रोजी-रोटी कमाने (आजीविका) की दौड़ में कुर्बान कर दिया था- 'समय की आजादी'। अब मस्तिष्क उन सपनों को जीने के लिए स्वतंत्र है, जिन्हें हमने वर्षों से दबा रखा था। यह वह जादुई पल है, जब इकट्ठा की गई सफलता को सही अर्थों में सार्थकता में बदला जा सकता है।

आज वरिष्ठ नागरिक समाज के साथ अपने जुड़ाव की नई परिभाषाएं लिख रहे हैं। वे यह साबित कर रहे हैं कि हमारे भीतर का 'परिवर्तन लाने वाला इंसान' कभी सोता नहीं है। यह अपनी मूल पहचान को फिर से जीवित करने का एक सशक्त मार्ग है। इस जीवनशैली को अपनाने वाले बुजुर्ग पूरे समाज के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन रहे हैं।

जब एक सेवानिवृत्त व्यक्ति स्वेच्छा से किसी सामाजिक कार्य का नेतृत्व करता है, तो वह अपने दशकों के अनुभव को समाज को सौंप रहा होता है। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु के बहत्तर वर्षीय सेल्वामणी ने सेवानिवृत्त होने के एक दशक बाद खुद को बेचैन पाया। उनके मन में तकनीकी शिक्षा हासिल करने की पुरानी इच्छा थी। उसे उन्होंने जिंदा रखा और आज वे एक छात्र की तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। घर से कालेज के लिए रोज पचास किलोमीटर की यात्रा करते हैं। उनका संघर्ष केवल डिग्री तक सीमित नहीं है। घर से निकलने से पहले वे रसोई के काम निपटाते हैं और अपनी बीमार पत्नी की देखभाल भी करते हैं। कालेज में छात्र उन्हें प्यार से 'दादाजी' बुलाते हैं। वे सिखाते हैं कि भले ही शरीर की आयु बढ़ जाए, लेकिन लक्ष्य सामने हो तो चेतना हमेशा युवा रहती है। इसी तरह, सक्रियता का जज्बा केरल की कात्यायनी अम्मा में भी दिखा, जिन्होंने छियानबे वर्ष की आयु में साक्षरता अभियान में अट्ठानबे फीसद अंक प्राप्त किए। उनकी सफलता ने उस पुरानी सोच को तोड़ दिया कि बुजुर्ग नई चीजें नहीं सीख सकते। इसके अलावा, बीडी गरवारे ने सेवानिवृत्ति के बाद अपने अनुभव को शिक्षा और समाज सेवा की ओर मोड़ दिया। शारीरिक रूप से दुरुस्त और सेहतमंद रहने के प्रति भी नजरिया बदल रहा है। गुजरात की एक डाक्टर भगवती ओजा अस्सी वर्ष की उम्र पार करने के बाद भी तैराकी और साइकिल चालन में स्वर्ण पदक जीतती रहीं। उनका जीवन सिद्ध करता है कि सक्रियता एक साधना है, जिसमें मन के साथ शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। बुजुर्गों की सक्रियता केवल शौक तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को भी मजबूती प्रदान करती है। वे युवाओं के लिए परामर्शदाता बनकर उन्हें उन गलतियों से बचा सकते हैं, जो अक्सर अनुभव की कमी के कारण होती हैं। यह एक वैश्विक लहर है।

आधुनिक न्यूरोसाइंस यानी मस्तिष्क विज्ञान भी कहता है कि हमारा मस्तिष्क स्थिर नहीं है। कुछ नया सीखने से मस्तिष्क की कोशिकाएं फिर से सक्रिय होती हैं और नए तंत्रिका मार्ग बनते हैं। इसे 'न्यूरोप्लास्टिसिटी' यानी मस्तिष्क का लचीलापन कहते हैं, जो भूलने की बीमारी (अल्जाइमर) जैसी समस्याओं से लड़ने में एक ढाल की तरह काम करती है। खुद को बौद्धिक रूप से व्यस्त रखना इन समस्याओं से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह विज्ञान हमारे प्राचीन 'वानप्रस्थ' दर्शन के साथ भी मेल खाता है, जहां व्यक्ति अपने अनुभवों को समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर देता था।

जब एक अनुभवी व्यक्ति समाज में हिस्सा लेता है, तो वह अपनी संचित बौद्धिक संपदा को वापस मुख्यधारा में लौटा रहा होता है। यह सक्रियता बुजुर्गों को अकेलेपन और अवसाद से भी बचाती है। आज के एकल परिवारों के युग में सक्रियता ही वह पुल है, जो पीढ़ियों के बीच की खाई को पाट सकता है। दादा-दादी का अनुभव और पोते-पोतियों की जिज्ञासा मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। युवाओं को भी समझना होगा कि अनुभव की गहराई के बिना ऊर्जा अक्सर दिशाहीन हो जाती है। सेवानिवृत्ति केवल एक पेशेवर विदाई है, जीवन का संन्यास नहीं। हमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसे मंच बनाने होंगे, जहां वे अपनी पसंद के अनुसार योगदान दे सकें- चाहे वह शिक्षा हो, पर्यावरण हो या सामुदायिक नेतृत्व। यह समाज के विकास की नई पटकथा लिखने जैसा होगा।

दुनिया मेरे आगे

> जब एक अनुभवी व्यक्ति समाज में हिस्सा लेता है, तो वह अपनी संचित बौद्धिक संपदा को वापस मुख्यधारा में लौटा रहा होता है। यह सक्रियता बुजुर्गों को अकेलेपन और अवसाद से भी बचाती है। आज के एकल परिवारों के युग में सक्रियता ही वह पुल है, जो पीढ़ियों के बीच की खाई को पाट सकता है।

कहने का आशय यह है कि सेवानिवृत्ति जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक 'दूसरे सूर्योदय' की शुरुआत है। यह वह समय है, जब हम अपनी आत्मा के छिपे हुए रंगों को फिर से दुनिया के सामने ला सकते हैं। हम वह सब कर सकते हैं जो जिम्मेदारियों के बोझ तले कभी अधूरा रह गया था। संदेश स्पष्ट है- केवल कैलेंडर की तारीखों के साथ वृद्ध नहीं होना चाहिए, बल्कि ज्ञान और कर्म के गौरव के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। अनुभव वह अद्वितीय पूंजी है, जो बांटने से अनंत गुना बढ़ती है और निरंतर सक्रिय रहने से कुंदन की तरह चमकती रहती है। सेवानिवृत्ति केवल एक पद से मुक्ति है, हमारे सामर्थ्य से नहीं। यह समय अपनी सार्थकता को नए आयाम देने का है। ज्ञान के इस दूसरे सूर्योदय का स्वागत पूरी ऊर्जा के साथ करना चाहिए।

घर का सपना

अपने घर का सपना सभी देखते हैं। मगर आज के दौर में यह सपना पूरा करना चुनौतीपूर्ण है। बड़े शहरों में बढ़ती आबादी, महंगी जमीन और सीमित आय के कारण मकान खरीद पाना संभव नहीं है। भारत सरकार ने पिछले दशक में प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से लाखों लोगों को पक्के घर उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई दिया है। मगर शहरी क्षेत्रों में काम करने वाला गरीब और निम्न वर्ग आज भी आवास संकट से जूझ रहा है। महानगरों और औद्योगिक शहरों में काम करने वाले लाखों मजदूर, घरेलू कर्मचारी, निर्माण श्रमिक और छोटे कर्मचारी या तो झुग्गियों में रहने को मजबूर हैं या शहर की सीमा से बाहर गंदी बस्तियों में गुजर-बसर करते हैं। कारण साफ है- वे न तो शहर में मकान खरीद सकते हैं और न ही अधिक किराया दे पाने की स्थिति में होते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और विभिन्न शहरी विकास रिपोर्ट के अनुसार, भारत के बड़े शहरों में मकानों की कीमतें औसत आय की तुलना में कई गुना बढ़ चुकी हैं। एक मध्यमवर्गीय परिवार को भी घर खरीदने के लिए बीस-पच्चीस वर्षों तक गृह ऋण चुकाना पड़ता है।

– विभूति बुपक्या, दिल्ली

मानवीयता की संवेदना

बशीर बद्र का निधन समूचे देश के लिए मानवीय रिश्तों की भाषा की बड़ी क्षति है। उन्होंने शायरी को इश्क और रूमानी कल्पनाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे आम आदमी के दुख, अकेलेपन, विस्थापन, सामाजिक विडंबनाओं और जीवन-दर्शन की गहरी अभिव्यक्ति बना दिया। उनकी शायरी में दर्द भी था, अपनापन भी। दर्शन भी था और सहज मानवीय संवाद भी। उन्होंने उर्दू को सरल, बोलचाल और आत्मीय शैली प्रदान की। उनके शेर सीधे दिल में उतर जाते हैं, क्योंकि उनमें कृत्रिमता नहीं, बल्कि जीवन का सच्चा अनुभव बोलता है। उन्होंने गजल को अभिजात्य दायरे से निकाल कर जन-संवेदना का माध्यम बनाया। उनकी रचनाओं में प्रेम के साथ-साथ समय की निष्ठुरता, बदलते रिश्तों की पीड़ा और इंसानी मूल्यों की चिंता स्पष्ट दिखाई देती है। यही कारण है कि वे केवल शायर नहीं, बल्कि आधुनिक भारतीय समाज के संवेदनशील दार्शनिक भी प्रतीत होते हैं।

– इशरत अली कादरी, भोपाल

यथार्थ की दृष्टि

'दुर्लभ खनिज और साझा हित' (आलेख, 28 मई) पढ़ा। इसमें समकालीन वैश्विक राजनीति, आर्थिक साझेदारी और राष्ट्रीय संसाधनों की महत्ता को यथार्थपूर्ण दृष्टिकोण के साथ सामने रखा गया है। दुर्लभ खनिज गलियारे की परिकल्पना तथा कुछ राज्यों की सक्रिय भूमिका को जिस संतुलित और तार्किक ढंग से रेखांकित किया गया है, उससे भारत की आर्थिक और सामरिक संभावनाओं को समझा जा सकता है। अमेरिका के साथ इस क्षेत्र में विकसित होती साझेदारी और समझौतों की पहल भविष्य की वैश्विक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर तैयार की गई सकारात्मक और दूरगामी सोच का परिचायक बन कर उभरी है। प्राकृतिक संसाधनों का महत्त्व केवल आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में भी एक महत्त्वपूर्ण आधार बन चुका है। मगर वैश्विक सहयोग की नई संभावनाओं के साथ राष्ट्रीय हितों का ध्यान भी हमें रखना होगा।

– अशोक, पटना, बिहार

भरोसे का आधार

मतदाता सूचियों के सघन पुनरीक्षण को लेकर सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए गए ग्यारह दस्तावेजों में आधार कार्ड को लेकर सुधारों की आवश्यकता पर भी ध्यान आकर्षित किया गया था। वास्तव में यह अपनी अपेक्षित सुरक्षा संरचना के अभाव में विश्वसनीयता कायम नहीं कर पाया है। वर्तमान समय में यह एक औपचारिक पहचान पत्र बन कर रह गया है, जबकि इसकी परिकल्पना कहीं अधिक सुरक्षित और सर्वमान्य पहचान दस्तावेज के रूप में की गई थी। पैन कार्ड और वोटर कार्ड की तरह इसका उपयोग तो व्यापक है, किंतु सुरक्षा और सत्यापन के स्तर पर इसमें अभी भी कई कमियां दिखाई देती हैं। आधार में डेबिट कार्ड जैसी आधुनिक सुरक्षा तकनीकों को शामिल किया जाए, ताकि यह भारतीय नागरिकों के लिए जोखिम न साबित हो।

– खुमानसिंह चुंडावत, मंदसौर

अब एआइ से सीखिए योग, 2.80 लाख तस्वीरों से उन्नत प्रारूप तैयार

कृत्रिम मेधा (एआइ) अब किसी प्रशिक्षक की तरह योग की सही और गलत मुद्राओं के बीच का फर्क पहचान सकती है। अनुसंधानकर्ताओं ने 'योग एआइ कोच' नाम का एआइ माडल विकसित किया है। करीब 2.80 लाख तस्वीरों के आधार पर तैयार प्रारूप (माडल) सूर्य नमस्कार समेत योग की 104 प्रकार की मुद्राओं का वास्तविक समय में विश्लेषण कर सकता है। 'योग एआइ कोच' को तैयार करने में एजंटिक एआइ, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि यह माडल सरकारी क्षेत्र के संस्थान इंदौर के 'श्री जीएस इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एंड साइंस' (एसजीएसआइटीएस) की अनुसंधान परियोजना के तहत विकसित किया गया है। इस संस्थान की नवाचारी परियोजना को मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (एमपीसीएसटी) की ओर से 7.10 लाख रुपए के अनुदान की मंजूरी भी मिली है।

दिल्ली के गाजीपुर क्षेत्र में भूजल हुआ विषैला, इस्तेमाल पर प्रतिबंध

राकेश शर्मा

दिल्ली के गाजीपुर क्षेत्र में भूजल विषैला हो गया है। इस क्षेत्र के भूजल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ताजा शोध के मुताबिक, पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी, पूर्वी विनोद नगर और खिचड़ीपुर का भूजल गाजीपुर कचरा पट्टी के कारण विषैला हो गया है। इस क्षेत्र से निकलने वाले भूजल के इस्तेमाल ने गंभीर रोगों की आशंका को बढ़ा दिया है। यह खुलासा राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के भूजल जल विज्ञान प्रभाग के वैज्ञानिक द्वारा किए गए एक शोध में हुआ है।

शोध के अनुसार लंबे समय तक गाजीपुर कचरा पट्टी से निकलने वाले दूषित तत्व रिसकर भूजल तक पहुंच गए हैं। इन तत्व से भू जल को हुए नुकसान की पहचान के लिए भूजल विज्ञान प्रभाग की वैज्ञानिक डाक्टर अंजलि भागवत ने एक नवंबर 2019 से 31 मार्च 2024 तक क्षेत्र में सर्वे किया। साथ ही भूजल, मिट्टी सहित अन्य तत्व के नमूने एकत्रित कर जांच किए व लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्हें पता चला कि भूजल का प्रयोग करने वाले लोगों में त्वचा संबंधित गंभीर रोग हो गए हैं। कई मामलों में कैंसर होने की बात भी सामने आई। इस समस्या को देखते हुए प्रशासन की मदद से क्षेत्र में भूजल इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही दिल्ली जल बोर्ड को टैंकर या पाइप लाइन के माध्यम से पर्याप्त जल उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया है।

शोध

शोध के दौरान किए गए भूजल परिवहन मॉडलिंग के अनुसार प्रदूषण का फैलाव मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण-पूर्व दिशा में लगभग दो किलोमीटर क्षेत्र तक पाया गया है। इस स्थिति से होने वाली परेशानी की रोकथाम के लिए शोध में प्रभावित क्षेत्रों में विशेष बफर और हस्तक्षेप क्षेत्र बनाने की सिफारिश की गई है। शोध में बताया गया कि दिल्ली जल बोर्ड ने प्रभावित क्षेत्रों में भूजल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति पाइपलाइन और टैंकरों के माध्यम से की जा रही है। इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड ने हेल्पलाइन व्यवस्था भी शुरू की थी ताकि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। अध्ययन में यह भी सामने आया कि गाजीपुर कचरा पट्टी, संजय झील, यमुना नदी, वर्षा जल तथा अन्य स्रोत कई स्थानों पर जल प्रदूषण के संभावित कारण बने हुए हैं। वैज्ञानिकों ने प्रदूषण स्रोतों की पहचान के लिए ग्रिड आधारित तकनीक का उपयोग किया है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों का सटीक आकलन किया जा सके।

ताजा शोध के मुताबिक, पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी, पूर्वी विनोद नगर और खिचड़ीपुर का भूजल गाजीपुर कचरा पट्टी के कारण विषैला हो गया है। इस क्षेत्र से निकलने वाले भूजल के इस्तेमाल ने गंभीर रोगों की आशंका को बढ़ा दिया है। यह खुलासा राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के भूजल जल विज्ञान प्रभाग के वैज्ञानिक द्वारा किए गए एक शोध में हुआ है।

गेंदे के फूलों तक पहुंचा प्रदूषण

शोध के दौरान प्रभावित क्षेत्र में गेंदे के पौधे भी लगाए गए। इन पौधे पर हुए अध्ययन के दौरान पाया गया कि मिट्टी या भूजल में पाया जाने वाले दूषित तत्व गेंदे के फूल तक पहुंच गया। यह गंभीर चिंता का विषय है। विशेषज्ञों का कहना है कि उक्त पौधे के फूल में भी दूषित तत्व पाए गए तो गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वैज्ञानिक ने राष्ट्रीय जल आयोग को उचित कार्रवाई की सिफारिश की है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि कल्याणपुरी, विनोद नगर और खिचड़ीपुर के निवासियों को भूजल का उपयोग पीने या घरेलू जरूरतों के लिए नहीं करना चाहिए। इन क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल के लिए केवल अधिकृत जलापूर्ति स्रोतों पर ही निर्भर रहने से कई तरह की समस्याओं से बचा जा सकता है। वहीं अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह शोध दूसरे कचरा पट्टी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसे आधार बनाकर उक्त क्षेत्र में बचाव के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। वहीं समय रहते उक्त क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है।

देश में कचरे से बिजली उत्पादन की रफ्तार धीमी

पंकज रोहिला

कूड़े के पहाड़ व बिजली की बढ़ती मांग लगातार बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने देश में इस संकट से निजात पाने के लिए कचरे से बिजली जैसी अहम योजना शुरू की थी। इसके तहत राज्यों को अपने कचरे के माध्यम से बिजली बनानी थी और कचरा भी कम करना था।

इस पहल के बाद बीते तीन साल में एक अरब यूनिट (1000 मिलियन यूनिट) से अधिक बिजली बढ़ी है, जबकि देश में बिजली मांग में तेजी से इजाफा दर्ज हो रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद नायक के मुताबिक, सरकार देश में हरित ऊर्जा का बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। केंद्र सरकार की रपट बताती है कि कचरे से बिजली उत्पादन करने के मामले में बड़ी ही धीमी रफ्तार से काम हो रहा है। इस श्रेणी में वर्ष 2021- 22 में कुल 1621.06 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया जा रहा था, जो कि वर्ष 2025 -26 में बढ़कर केवल 2703.82 मिलियन यूनिट तक हुआ है। इस प्रकार बीते सालों में कचरे से बिजली का उत्पादन करीब 1082.76 मिलियन यूनिट बढ़ा है। तय मानकों के हिसाब से एक मिलियन यूनिट में करीब दस लाख यूनिट बिजली आती है। इस प्रकार कचरे से 1082760000 (1.08 अरब) यूनिट का इस्तेमाल उपभोक्ताओं द्वारा कचरे से बनी बिजली से किया जा रहा है।

कचरे से बिजली बनाने वाले राज्यों में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख राज्य शामिल हैं। अभी भी देश के कई राज्यों में इस दिशा में पहल होने का इंतजार है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, जैसे प्रमुख राज्य हैं। इन राज्यों में कचरे से बनी बिजली का उत्पादन शून्य दर्ज किया गया है।

रिपोर्ट बताती है कि पूरे भारत में कुल 283621.23 मिलियन (2.8 अरब) यूनिट का बिजली उत्पादन किया जा रहा है। इस बिजली में पवन ऊर्जा से 101248.02, सौर ऊर्जा से 155370.47, बायोमास से 3732.27, गन्ना खोई से 9142.87, लघु हाइड्रो से 11423.78 और कचरे से कुल 2703.82 मिलियन इकाई बिजली का उत्पादन हो रहा है। केंद्र सरकार के मुताबिक केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) का अनुमान है कि राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार वर्ष 2031-32 में संस्थापित उत्पादन क्षमता 873736 मेगावाट होने का अनुमान है, जिसमें लगभग 5,07,411 मेगावाट क्षमता गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे 364566 मेगावाट सौर ऊर्जा, 121895 मेगावाट पवन ऊर्जा, 15500 मेगावाट बायोमास और 5450 मेगावाट लघु जल विद्युत से प्राप्त होगी। वर्तमान में कुल 524 गीगा वाट संस्थापित क्षमता से में करीब 215.5 गीगावाट बिजली गैर पारंपरिक स्रोत से प्राप्त होती है।

केंद्र सरकार की रपट बताती है कि कचरे से बिजली उत्पादन करने के मामले में बड़ी ही धीमी रफ्तार से काम हो रहा है। इस श्रेणी में वर्ष 2021- 22 में कुल 1621.06 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया जा रहा था, जो कि वर्ष 2025 -26 में बढ़कर केवल 2703.82 मिलियन यूनिट तक हुआ है।

154830 मेगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता

रिपोर्ट बताती है कि 154830 मेगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता है। इसमें 64670 मेगावाट सौर ऊर्जा, 6490 मेगावाट पवन ऊर्जा, और 59990 मेगावाट हाइब्रिड ऊर्जा निर्माणाधीन (जनवरी 2026 तक) है जबकि 47920 मेगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता जिसमें 35440 मेगावाट सौ ऊर्जा और 10080 मेगावाट हाइब्रिड योजना 2029 - 30 तक पूर्ण होने का लक्ष्य है।

इंसानों की तरह मिट्टी की सेहत की भी फिक्र जरूरी

सर्वेश कुमार

इंसानों की तरह मिट्टी की सेहत का भी ध्यान रखकर फसलों की उत्पादकता में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके लिए खास तौर पर मिट्टी में पोषक तत्वों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। इसमें जैविक खाद, लघु सिंचाई सहित अन्य उपायों को अपनाकर फसलों के लिए पौधों को पोषण तत्वों के नुकसान की बचत की जा सकती है। जैविक खेती से उर्वरकों के इस्तेमाल में कटौती के साथ ही देश में फसलों की गुणवत्ता में सुधार से कृषि क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिल सकती है।

जानकारों का कहना है कि जैविक खेती करने वाले किसानों की वित्तीय सेहत बेहतर बनाए रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है। कृषि मामलों के जानकारों के मुताबिक पश्चिम एशिया संकट के बीच जैविक खेती और जैव उर्वरकों के इस्तेमाल बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। प्राकृतिक खेती के साथ साथ उर्वरकों का कम से कम इस्तेमाल के साथ साथ मिट्टी में पोषक तत्वों के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। कुछ जगहों पर खेतो की मिट्टी में नाइट्रोजन अगर 30-40 फीसद है तो इसे बढ़ाकर 70 फीसद किया जा सकता है।

पर्यावरण

इसके लिए पानी का नुकसान या वाष्पीकरण और पोषक तत्वों की कमी को दूर करना जरूरी है। पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए एहतियाती उपायों से बेहतर पैदावार के साथ साथ फसलों की गुणवत्ता और बेहतर हो सकती है। मिट्टी की मैपिंग के जरिए जरूरी पोषक तत्वों के संतुलित इस्तेमाल से पैदावार की गुणवत्ता और मात्रा में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। रसायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल में पोषक तत्वों के असंतुलित इस्तेमाल का असर मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है। जैविक कृषि एक ऐसी विधि है जिसमें रासायनिक खाद, कीटनाशकों और कृत्रिम दवाओं के बयान पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों, जैविक खादों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हुए भूमि की उर्वरा शक्ति को सुरक्षित बनाए रखना है। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक पदमश्री ए के सिंह के मुताबिक गुणवत्ता कृषि को बढ़ावा देने के लिए मिट्टी की गुणवत्ता, खासकर इसके पोषण का ध्यान रखना जरूरी है। फिलहाल कई बार खेतों में मिट्टी की जरूरत के मुताबिक नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस सहित अन्य पोषक तत्वों का असंतुलन होने से भी पैदावार प्रभावित होती है। जैव उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए इनकी गुणवत्ता नियंत्रण के लिए बेहतर प्रबंधन भी जरूरी है।

जैविक खेती से उर्वरकों के इस्तेमाल में कटौती के साथ ही देश में फसलों की गुणवत्ता में सुधार से कृषि क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिल सकती है।

मिट्टी की मैपिंग के जरिए जरूरी पोषक तत्वों के संतुलित इस्तेमाल से पैदावार की गुणवत्ता और मात्रा में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। रसायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल में पोषक तत्वों के असंतुलित इस्तेमाल का असर मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है।

स्वच्छता

अहमदाबाद में मंगलवार को स्वच्छता अभियान के तहत साबरमती नदी की सफाई करते स्वयंसेवक।

रोमांच व संस्कृति का संगम बनी 'बाइकिंग' प्रतियोगिता

सुनील दत्त पांडेय

उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली की सुरम्य एवं सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नीति घाटी में 31 मई से दो जून तक आयोजित 'नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन' के अंतिम दिन गमसाली से मलारी के मध्य 30 किलोमीटर एमटीबी (माउंटेन बाइकिंग) चैलेंज प्रतियोगिता का रोमांचक आयोजन किया गया। दुर्गम पहाड़ी रास्तों, चुनौतीपूर्ण ट्रैक और मनमोहक प्राकृतिक वादियों के बीच आयोजित इस प्रतियोगिता में देशभर से आए 100 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। 30 किलो मीटर पुरुष एमटीबी चैलेंज प्रतियोगिता में खरिकसिंग अडानिस तांगपू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि सूरज राणा मगर दूसरे एवं प्रकाश थापा मगर तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग की 30 किलोमीटर एमटीबी चैलेंज प्रतियोगिता में अवनी डरियाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। संध्या मौर्या दूसरे तथा इंद्रा कुमारी तमांग तीसरे स्थान पर रहीं।

15 किलोमीटर पुरुष एमटीबी चैलेंज प्रतियोगिता में प्रज्जवल चौहान प्रथम, इशांत सिंह अधिकारी द्वितीय तथा अश्विन रौथान तृतीय स्थान पर रहे। वहीं महिला वर्ग में प्रिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। पर्यटन विभाग द्वारा भारतीय सेना एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) के सहयोग से आयोजित तीन दिवसीय इस भव्य आयोजन में देश के 27 राज्यों से आए कुल 1200 से अधिक प्रतिभागीयों ने हिस्सा लिया। तीन दिवसीय इस आयोजन का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना, स्थानीय संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाना तथा फिटनेस एवं साहसिक खेलों के प्रति जागरूक करना है।

वर्ष 2047 तक 6.8 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन में कमी संभव

सुशील राघव

देश के शहरों में निकलने वाले जैविक कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन न केवल स्वच्छता और ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्त्वपूर्ण है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन से मुकाबले का भी प्रभावी माध्यम बन सकता है। ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार यदि भारत जैविक कचरे के संग्रहण और प्रसंस्करण को व्यापक स्तर पर अपनाता है तो वर्ष 2047 तक लगभग 6.8 करोड़ टन कार्बन डाइआक्साइड समतुल्य उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में बड़ी मात्रा में जैविक कचरा खुले में फेंका जाता है या कूड़ा स्थलों तक पहुंच जाता है, जहां से मीथेन जैसी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है। मीथेन को जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे खतरनाक गैसों में माना जाता है। यदि इस कचरे को खाद और जैव-गैस बनाने के लिए उपयोग किया जाए तो उत्सर्जन को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अध्ययन के अनुसार, त्वरित नीतिगत हस्तक्षेप वाले परिदृश्य में देश 2047 तक जैविक कचरे का सौ फीसद संग्रह और 95 फीसद तक प्रसंस्करण करने में सक्षम हो सकता है। इससे कचरे के ढेरों पर जाने वाली मात्रा घटेगी और उससे बनने वाली मीथेन गैस के उत्सर्जन में भी बड़ी कमी आएगी। इसके साथ ही खाद, जैविक उर्वरक और जैव-सीएनजी जैसे उत्पादों का उत्पादन बढ़ेगा।

रिपोर्ट चेतावनी देती है कि यदि वर्तमान व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया तो वर्ष 2047 तक कचरा क्षेत्र से होने वाला उत्सर्जन बढ़कर लगभग 12 करोड़ टन कार्बन डाइआक्साइड समतुल्य तक पहुंच सकता है। इसलिए समय रहते प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है। सीईईडब्ल्यू प्रार्थना बोराह ने कहा कि कचरा प्रबंधन स्वच्छ हवा से संबंधित बुनियादी ढांचा है। खुले में कचरा जलाना भारतीय शहरों में हानिकारक पीएम 2.5 उत्सर्जन में लगभग 10 फीसद का योगदान देता है, जबकि उचित प्रबंधन न होने पर जैविक कचरा मीथेन, दुर्गंध, आग का जोखिम और प्रदूषण बढ़ाता है, जिससे पुनर्चक्रण योग्य (रीसायकल होने लायक) सामग्रियों का मूल्य घट जाता है। जैसे-जैसे भारतीय शहरों का विस्तार हो रहा है, कचरा प्रबंधन प्रणालियां न केवल मौसमी प्रदूषण के समय, बल्कि पूरे साल हवा की गुणवत्ता और जीवन जीने की सुगमता तय करेंगी। शहरों को कचरे की छंटाई, संग्रह (इकट्ठा करने), प्रसंस्करण, निगरानी और नियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए साल भर चलने वाली, अति-स्थानीय तंत्र की जरूरत है, विशेष रूप से थोक कचरा उत्पादकों, बाजारों, होटलों, रेस्तरां और बड़े आवासीय परिसरों के लिए।

रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के शहरों में प्रतिदिन लगभग 1.71 लाख टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें करीब आधा हिस्सा जैविक कचरे का होता है। वर्ष 2047 तक यह मात्रा और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में जैविक कचरे का प्रभावी प्रबंधन स्वच्छ हवा, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण होगा।

रिपोर्ट

वर्तमान में बड़ी मात्रा में जैविक कचरा खुले में फेंका जाता है या कूड़ा स्थलों तक पहुंच जाता है, जहां से मीथेन जैसी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है। मीथेन को जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे खतरनाक गैसों में माना जाता है। यदि इस कचरे को खाद और जैव-गैस बनाने के लिए उपयोग किया जाए तो उत्सर्जन को काफी हद तक कम किया जा सकता है।